दीक्षांत
Education Centre

दीक्षांत समसामयिकी

सितंबर 2022

क्या है खास....

- चुनावी उपहार की राजनीति
- जाति के बदलते संदर्भ
- ईरान परमाणु समझौता वार्ता
- क्वांटम कम्प्यूटिंग : उपयोगिता और चुनौतियां
- भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022
- अमृत काल के पाँच प्रण
- 'वन नेशन वन फर्टिलाइजर' योजना
- भारत में रामसर स्थल
- स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट
- यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

करेंट अफ़ेयर्स की बेहतर तैयारी हेतु
दीक्षांत एप पर निःशुल्क करेंट अफ़ेयर्स क्लास
में अवश्य भाग लें।

दीक्षांत ऐप डाउनलोड
करने के लिए
QR Code स्कैन करें।

VISIT US: DIKSHANTIAS.COM
9312511015
8851301204
FACEBOOK.COM /DIKSHANT.IAS.7
YOUTUBE.COM /DIKSHANTIAS
TWITTER.COM /DIKSHANTIAS
INSTAGRAM.COM /DIKSHANTIAS
T.ME/ DIKSHANTIAS

दीक्षांत
Education Centre

68th BPSC PRE+MAINS

सामान्य अध्ययन

ऑनलाइन/ऑफलाइन

- दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की टीम द्वारा
- 600 घंटे का कक्षा कार्यक्रम
- अद्यतन पाठ्यक्रम सामग्री (40 बुकलेट)
- डेली टेस्ट (150 टेस्ट) + यूनिट टेस्ट - 16 टेस्ट
- वर्क बुक - 8
- करेंट अफेयर्स एवं बिहार स्पेशल की विशेष कक्षाएँ
- डाउट क्लियरेंस हेतु विशेष मेन्टर की व्यवस्था

नामांकन प्रारंभ / सीमित सीटें

Fee
~~₹75,000~~
₹30,000
only

*Inaugural fee for first 200 students

27 SEPT.
@7 PM

TO REGISTER INSTALL DIKSHANT APP/ ADD.: 289, DHAKA JOHAR, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09, CALL : 7428092240

दीक्षांत समसामयिकी

सितंबर, 2022

मुख्य संपादक
डॉ. एस एस पाण्डेय
डायरेक्टर
शिप्रा पाण्डेय
कार्यकारी संपादक
राकेश पाण्डेय
सह-कार्यकारी संपादक
साकेत आनंद
प्रबंधन परामर्श
शंकर भारती, मरीना
सम्पादन सहयोग
विपिन, नीरज, विकास तिवारी, मो. शोएब, अजय द्विवेदी, संतोष, अभिजीत, प्रकाश जायसवाल, मनोज सिंह
टाइप सेटिंग व डिज़ाइनिंग
सूर्यजीत, पूजा, सुनील, शकिबा संजय, सोनू, प्रवीण, जितेन्द्र

****

- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबसाइटों से गैर-व्यवसायिक एवं शैक्षणिक उद्देश्य से लिये गये हैं और हम इसके लिये उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

IAS दीक्षांत Education Centre PCS
18 वर्षों से ईमानदार प्रयास
FREE COACHING & SCHOLARSHIP PROGRAMME
सामान्य अध्ययन
नया फाउंडेशन बैच
हिन्दी माध्यम
13 SEPT. 6PM
सीमित सीटें... नामांकन प्रारंभ जल्दी करें...
Online Course हेतु Google Play Store से Dikshant Education के App को Download करके अपना रजिस्ट्रेशन करायें
विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें... 7428092240
289, DHAKA JOHAR, NEAR DUSSEHRA GROUND, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09

प्रधान कार्यालय
289, ढाका जौहर, दशहरा ग्राउन्ड के नजदीक, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
संपर्क कार्यालय
704, बत्रा सिनेमा के सामने, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
मोबाइल: 7428092240, 9312511015, 8851301204
ई-मेल: dikshantias2011@gmail.com, वेबसाइट: www.dikshantias.com
भोपाल शाखा
प्लॉट न. 48, 3rd फ्लोर, सरगम टॉकीज के पीछे, जोन-2, एमपी नगर, भोपाल

अनुक्रम

न्यूज़ एक्सप्लेनर

- चुनावी उपहार की राजनीति 6
- जाति के बदलते संदर्भ 8
- नया वन अधिनियम बनाम आदिवासियों के अधिकार 10
- नागोर्नो-काराबाख विवाद 12
- इज़राइल-फिलीस्तीन संघर्ष विराम 15
- ईरान परमाणु समझौता वार्ता 17
- क्वांटम कंप्यूटिंग: उपयोगिता और चुनौतियां 19

राष्ट्रीय घटनाक्रम

- व्यापक विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधि निषेध) संशोधन विधेयक 2022 22
- भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 23
- मंकीपॉक्स पर वीके पॉल टास्कफोर्स का गठन 24
- एक जिला-एक उत्पाद 24
- परवाज योजना 25
- धन शोधन निवारण अधिनियम 25
- ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 26
- वज्र प्रहार 2022 27
- भारत छोड़ो आंदोलन 27
- स्माइल 75-पहल 28
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 28
- राष्ट्रीय ध्वज 30
- अरबिंदो घोष 30
- लोक अदालत 31
- भारतीय सेना को सौंपी गई नई रक्षा प्रणाली 31
- भारत में बाल मृत्यु दर 32
- जल जीवन मिशन 33
- वीएलसी मीडिया प्लेयर पर प्रतिबंध 34
- 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया 34
- सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के प्रावधान को रद्द किया 35
- गरबा को भारत द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया 35
- केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन 35
- भारत ने एक लाख से अधिक (1,01,462) ओडीएफ प्लस गांवों की उपलब्धि हासिल की 36
- सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के लिए मौद्रिक सीमा, अभियोजन और जमानत संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया 36
- इंदौर जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा 36
- भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार 36
- गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल 37
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने "अमृत काल के पांच प्रण" का आह्वान किया 37
- सरकार ने 'नमस्ते' (मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना) शुरू की 37
- भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन 'यात्री सुरक्षा' शुरू किया 38
- एनएचए ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन-आधारित निधि आवंटन की घोषणा की। 38
- भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज या पारसी नव वर्ष मनाया गया 38
- सभी PACS को नियंत्रित करने के लिए सरकारों द्वारा मॉडल नियम शुरू किए जाएंगे 38

- सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियम बदले 39
- संरक्षकता और बाल हिरासत पर संसदीय पैनल की सिफारिशें 39
- 31 दिसंबर 2024 तक पीएमएवाई-शहरी को जारी रखने की मंजूरी 39
- मुंबई में 22वें 'भारत रंग महोत्सव' का उद्घाटन 39
- एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उप-राष्ट्रपति चुने गए 40
- भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के दल ने डोर्नियर 228 विमान पर उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया। 40
- सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू की गई 40
- भारत निर्वाचन आयोग ने 17 वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दी 40
- 'इंडिया @ 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप' जारी 41
- 2021 में आत्महत्या से होने वाली मौतें अपने उच्चतम स्तर पर: एनसीआरबी 41
- भारत का पहला 3डी प्रिंटेड डाकघर 42
- श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 42

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

- भारत-यूरोपीय संघ संबंध 43
- भारत ने नाविकों के सुगम आवाजाही के लिए ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए 44
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेक्सिको यात्रा के दौरान पांडुरंग खानखोजे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किया 44
- भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं का समुद्री साझेदारी अभ्यास (एमपीएक्स) 44
- ब्रिटेन से सात कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर 45
- ग्रीस ने यूरोपीय संघ के 'उन्नत निगरानी' ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की 45
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय-फ्रांस परिवहन क्षेत्र समझौते को अपनी मंजूरी दी 45
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल विधेयक पर हस्ताक्षर किए 46
- भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को पहला डोर्नियर निगरानी विमान दिया 46
- मैक्सिकन राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा 46
- आसियान ने म्यांमार के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया 46
- भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक आधार वाले संबंधों के लिए मालदीव के साथ छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए 47
- अमेरिका ने अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को मारने के लिए 'हेलफायर आर 9एक्स' मिसाइल का इस्तेमाल किया 47
- भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न 47
- "विनबैक्स 2022" अभ्यास 48
- भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह-IV 48
- मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का 4 दिवसीय भारत दौरा 48
- केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया 48
- विश्वविद्यालयों के आसियान-भारत नेटवर्क का शुभारंभ 48
- सैन्य अभ्यास 'एम्पल स्ट्राइक' शुरू किया गया 49
- पहली बार, भारत ने "ताइवान जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के सैन्यीकरण" का उल्लेख किया 49
- वज्र प्रहार 2022 49
- भारत नेपाल में दो जलविद्युत संयंत्रों का निर्माण करेगा 50
- भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (JRC) की 38वीं बैठक 50
- भारत और चीन के बीच तनाव अंतरिक्ष परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है 50
- साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी" का आयोजन 51
- जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी 51

अर्थ जगत

- एफपीआई सलाहकार समिति (एफएसी) 52
- गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस और सहकारी समितियां Eco 53
- भारत की 7% से अधिक आबादी के पास डिजिटल मुद्रा : अंकटाड 53
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 54

- भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 55
- भारतीय खान ब्यूरो 56
- भारतमाला परियोजना के तहत त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर 57
- भारत गैस का बीपीसीएल के साथ एकीकरण को मंजूरी 57
- मिथिला मखाना को जीआई टैग 57
- सरकार ने रक्षा बलों को मेक इन इंडिया मार्ग के माध्यम से आपातकालीन हथियार खरीदने की अनुमति दी 58
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की 58
- तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज अनुदान को मंजूरी 58
- सरकार ने उद्योग के साथ अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए 'मंथन' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 58
- 2021 में, पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं भूखी रहीं: केयर रिपोर्ट 59
- आरबीआई ने डिजिटल उधार के लिए दिशानिर्देशों को जारी किया 59
- भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सीमा पार से आवक भुगतान स्वीकार करने में सक्षम की जाएगी 59
- पीएम मोदी ने पानीपत में दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया 59
- भारत का कॉफी निर्यात 2021-22 में 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर 60
- भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4.90% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया 60
- गन्ना किसानों के लिए अब तक का उच्चतम उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 305 रुपये प्रति क्विंटल स्वीकृत 60
- जुलाई 2022 में व्यापार घाटा 31 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर 60
- डीपीआईआईटी द्वारा 75000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई 61
- मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक बढ़कर 56.4 हो गया 61
- सही दाम 2.0 ऐप लॉन्च 61
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल क्रियान्वयन के आठ वर्ष पूर्ण 61
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी 62
- 'वन नेशन वन फर्टिलाइजर' योजना 62
- गेहूं या मेसलिन आटा निर्यात नीति संशोधन को मंजूरी 62
- 2024-25 तक कोयला उत्पादन को 1.23 अरब टन तक बढ़ाने का लक्ष्य: कोयला मंत्रालय 63

विज्ञान एवं तकनीकी

- एसएसएलवी-डी1 64
- एक अतिरिक्त जीन ने चीनी चावल की किस्म की उपज को 40% तक बढ़ा दिया 64
- उत्तराखंड में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी 64
- वैज्ञानिकों ने बिना शुक्राणु के दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया 65
- भारत ने अपना पहला स्वदेशी मंकीपॉक्स परीक्षण किट लॉन्च किया 65
- भारत रूस से लंबी दूरी के छह टीयू-160 बमवर्षक लेने की योजना बना रहा है 65
- भारत का पहला 3-डी प्रिंटेड कॉर्निया 66
- यूके ओमिक्रोन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना 66
- केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारम्भ किया 66
- इसरो ने भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय 'स्पार्क' लॉन्च किया। 66
- कृषि मंत्री द्वारा स्वदेशी वैक्सीन लम्पी प्रोवैक लॉन्च किया गया 67
- पृथ्वी ने अपने मानक समय से 1.59 मिलीसेकंड कम में एक घूर्णन पूरा करके सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड तोडा 67
- जर्मनी में दुनिया का पहला हाइड्रोजन-संचालित यात्री ट्रेन बेड़ा लॉन्च किया गया 67

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- भारत में रामसर स्थल 68
- स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 69
- ग्रीनलैंड में घोंघा मछली का अस्तित्व संकट में 70
- भारत और श्रीलंका में लंबी उँगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज 70
- भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ 71

- दुनिया के 20 शहरों में से 18 शहर जहां PM 2.5 प्रदूषण में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, वे भारत से हैं: एचईआई अध्ययन 71
- अगस्त्यमलाई में एक नया हाथी अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा 71
- पर्यावास क्षति और शहरीकरण के कारण, पेनिन्सुलर रॉक आगामा दक्षिणी भारत से गायब 71
- यूएनएफसीसीसी को सूचना दिए जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतन निर्धारित योगदान को मंजूरी 72

खेल जगत

- पैरालिंपियन राहुल जाखड़ ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2022 डब्ल्यूएसपीएस शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता 73
- फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया 73
- तमारा वालकॉट ने 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा 73
- 44वें शतरंज ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान और यूक्रेन क्रमश: ओपन और महिला वर्ग में चैंपियन बनकर उभरे 73
- भारत के 75वें ग्रैंडमास्टर बने चेन्नई के वी प्रणव 74
- XXII (22वें) राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 पदक प्राप्त किए 74
- भारत ने बांग्लादेश को हराकर U-20 एसएएफएफ चैंपियनशिप जीती 74
- भारत ने लॉन बॉल कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा 74
- इंग्लैंड ने अपना पहला यूईएफए महिला यूरो 2022 खिताब जीता 75
- "गेम्स वाइड ओपन" पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा 75
- नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में लुसाने डायमंड लीग मीट जीतकर इतिहास रचा 75

राज्यनामा

- यूपी सरकार की भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना 76
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर 'शेरू' का अनावरण 76
- भारत में पहली नाईट सफारी लखनऊ में शुरू की जाएगी 76
- झारखंड किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना 76
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति-2022 का मसौदा जारी किया 77
- बिहार के मुख्यमंत्री ने आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया 77
- छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया 77
- एक सदी पुराने बिहार कॉलेज की खगोलीय प्रयोगशाला को यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया 78
- यूपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 'पंचामृत योजना' शुरू की 78
- विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनेगा 78

विविध

महत्त्वपूर्ण दिवस

- इंटरनॉट दिवस: 23 अगस्त 79
- अक्षय ऊर्जा दिवस 2022: 20 अगस्त 79
- विश्व संस्कृत दिवस 2022: 12 अगस्त 79
- अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022: 12 अगस्त 79
- विश्व हाथी दिवस 2022: 12 अगस्त 80
- विश्व शेर दिवस: 10 अगस्त 80
- विश्व आदिवासी दिवस 2022: 9 अगस्त 80

नियुक्ति

- आईएएस पीयूष गोयल नेटग्रिड के सीईओ नियुक्त 80
- जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश 81
- विश्वनाथन आनंद एफआईडीई के उपाध्यक्ष चुने गए 81
- नल्लाथम्बी कलाइसेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक 81
- श्वेता सिंह प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त 82
- प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार सतर्कता आयुक्त नियुक्त 82
- सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक नियुक्त 82

- अगस्टे तानो कौमे भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक नियुक्त 82
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) 83
- डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक (भारत) नियुक्त 84
- समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष 84
- संजय बारू की नई पुस्तक : "द जर्नी ऑफ ए नेशन: 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी" 84
- 'इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी: ए ब्रीफ हिस्ट्री' 84

पुरस्कार और सम्मान

- राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2020 विजेताओं की घोषणा 85
- भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न के 13वें संस्करण में रणवीर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता 85
- यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 86
- शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 86
- रामाधर सिंह यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फ़ेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने 86
- सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को एआईएफएफ फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर चुना गया 86
- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार प्रदान किए 87
- वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर्स' भेंट किया 87

प्रैक्टिस सेट

- यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न 88

चुनावी उपहार की राजनीति

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप

प्रसंग

- चुनाव में निःशुल्क उपहार वितरण पर प्रभावी रोकथाम लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एनवी रमना ने उल्लिखित किया कि इससे देश के वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो एक 'गंभीर मुद्दा' है।
- ज्ञातव्य है कि 31 मार्च, 2021 को राज्यों पर 59,89,360 करोड़ रुपये की देनदारी थी। याचिकाकर्ता ने मामले में उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर क्रमश: 6,62,891 करोड़ रुपये और 5,36,891 करोड़ रुपये की देनदारी है और वे इस संबंध में शीर्ष पर हैं। ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात में पंजाब सबसे ऊपर है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

सुप्रीम कोर्ट और पक्षकारों का मत

- आम आदमी पार्टी ने उल्लिखित किया कि कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त के 'रेवड़ी कल्चर' में अंतर है।
- अर्थव्यवस्था को पैसे के नुकसान एवं कल्याणकारी कदमों के बीच संतुलन कायम करना होगा।
- न्यायालय ने राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने की संभावना से स्पष्टत: मना किया।
- तर्कहीन मुफ्त उपहार वितरण के आधार पर राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने का विचार 'अलोकतांत्रिक' है। क्योंकि भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्था है।
- रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित '2020-2021 के लिए भारतीय राज्यों की सांख्यिकी की हैंडबुक' और फेडरल बैंक के जून 2022 बुलेटिन का हवाला दिया गया है। जिसे श्रीलंकाई संकट और राज्यों के भारी कर्ज की पृष्ठभूमि में मुफ्त उपहारों के खिलाफ अपने दावे को पुष्ट करने के लिए प्रकाशित किया गया था।

वेलफेयर बनाम चुनाव में निःशुल्क उपहार वितरण

- स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, सीवरेज, बिजली और परिवहन जैसी कुछ बुनियादी महत्व की सेवाएं हैं जिन्हें लोग अपने लिए व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे सरकारों का चयन करते हैं। विदित है कि ये सभी कल्याणकारी उपाय हैं।
- यद्यपि इनमें से कितनी सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए, यह सरकार के राजकोषीय दायरे पर निर्भर करता है। यदि सरकार की व्यय-राजस्व की स्थिति मजबूत है, तो एक सीमा तक मुफ्त सेवाएं दिया जाना सार्थक प्रतीत होता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि सभी राज्यों में अक्सर नकदी की कमी रहती है।
- आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में 'कैग' के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर व्यय लगातार बढ़ रहा है।
- 2020-21 में सब्सिडी पर कुल खर्च का 11.2 फीसदी खर्च किया गया था, जबकि 2021-22 में 12.9 फीसदी खर्च किया गया था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारें ऐसी जगह पैसा खर्च कर रहीं हैं, जहां से उन्हें कोई आय नहीं हो रही है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, बिल माफी और कर्ज माफी पर व्यय फ्रीबीज के अंतर्गत आएंगे।
- संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में उल्लेख है कि राज्य सरकार को उन लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए, जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं या समर्थन के बिना प्रगति नहीं कर सकते हैं। लेकिन विभिन्न दलों के चुनावी घोषणापत्र इससे मेल नहीं खाते हैं।

भारत में निःशुल्क चुनावी उपहार की पृष्ठभूमि और इसकी व्यापकता

- भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसे सरकार की ऐसी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन और संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विदित है कि एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा धन के उचित वितरण के सिद्धांतों पर आधारित होता है।
- सरकार द्वारा अपने उक्त प्रकृति के आधार पर कार्यान्वित विभिन्न पहलों के रूप में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित रोजगार, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, आवास और शोषण तथा हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना आदि को प्रमुखता से शामिल किया जाता है।
- यद्यपि इसे समय-समय पर आयोजित विभिन्न चुनावों (लोकसभा, राज्य विधानसभा आदि) में राजनीतिक दलों द्वारा जीत के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
- किसी विशेष चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रस्तुत निःशुल्क उपहार की प्रकृति सीमित निजी लाभ से प्रेरित होती है और सार्वजनिक वस्तुओं/सुविधाओं को सुदृढ़ता प्रदान करने में कोई योगदान नहीं देती हैं।
- ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु राज्य निःशुल्क चुनावी उपहार संस्कृति को प्रस्तुत करने और अग्रणी खिलाड़ी होने के लिए कुख्यात है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की State Finances- A Risk Analysis रिपोर्ट के मुताबिक 2021-2022 में किस राज्य में अपनी जीएसडीपी की तुलना में कितना कर्ज

1.	पंजाब GSDP का 53.3%	6.	पश्चिम बंगाल GSDP का 34.4% कर्ज
2.	राजस्थान GSDP का 39.5%	7.	झारखंड GSDP का 33% कर्ज
3.	बिहार GSDP का 38.6% कर्ज	8.	आंध्र प्रदेश GSDP का 32.5% कर्ज
4.	केरल GSDP का 37% कर्ज	9.	मध्य प्रदेश GSDP का 31.3% कर्ज
5.	उत्तर प्रदेश GSDP का 34.9% कर्ज	10.	हरियाणा GSDP का 29.4% कर्ज

भारत में निःशुल्क चुनावी उपहार संस्कृति का अभ्युदय

- भारत में निःशुल्क चुनावी उपहार संस्कृति का आरंभ 1967 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हुई थी। उस समय द्रमुक ने एक रुपये में डेढ़ किलो चावल देने का वायदा किया था।
- विदित है कि यह चुनाव पूर्व प्रतिबद्धता ऐसे समय में प्रस्तुत की गई थी, जब देश खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था।
- वर्तमान परिदृश्य में तमिलनाडु से शुरू हुए निःशुल्क चुनावी उपहार की संस्कृति धीरे- धीरे सभी राज्यों में फैल चुकी है।
- आज सभी राजनीतिक दलों के मध्य मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह की प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की जाती हैं।

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए निःशुल्क चुनावी घोषणाओं के कुछ उदाहरण

- आम आदमी पार्टी ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रति माह देने का वायदा किया है।
- वहीं शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने प्रत्येक महिलाओं को लक्षित कर 2000 रुपये देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत प्रत्येक छात्रा को एक स्मार्टफोन, स्नातक की पढ़ाई करने वाली प्रत्येक छात्रा को एक स्कूटी और महिलाओं के लिए निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा आदि प्रदान करने का वचन दिया है।
- समाजवादी पार्टी ने प्रत्येक परिवार के लिए 300 यूनिट निःशुल्क बिजली की आपूर्ति और प्रत्येक महिला को 1500 रुपये पेंशन प्रतिमाह देने का वायदा किया है।

निःशुल्क चुनावी उपहार संबद्ध पूर्व के मामले

- सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को चुनावी निःशुल्क उपहार की राजनीति से अभिप्रेरित किसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्तता पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को अधिहत/जब्त करने और पंजीकरण निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की गई।
- तर्कहीन निःशुल्क उपहारों के वायदे अथवा वितरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी और 171सी के अंतर्गत अवैध परितोषण और अनुचित प्रभाव के समतुल्य माने जाने की मांग की गई।
- याचिका में राजनीतिक दलों के ऐसे निर्णयों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14, 162, 266 (3) और 282 का उल्लंघन बताया गया है।
- चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के प्रासंगिक परिच्छेद में अतिरिक्त शर्त निर्दिष्ट करने हेतु चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई है। विदित है कि यह पैराग्राफ राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक शर्तों से संबंधित है। इस अनुरोध का उद्देश्य चुनाव पूर्व सार्वजनिक धन से चुनावी उपहार के वायदे पर विधिक रोकथाम लगाना है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (बी) और (सी)

- भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (बी) रिश्वत के बदले धन, वस्तु प्रदान करने अथवा स्वीकार करने पर एक वर्ष के कारावास अथवा आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रविधान करता है।
- ज्ञातव्य है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (बी) के अनुसार, रिश्वत का अभिप्राय निर्वाचन अधिकार से संबंधित है।
- धारा 171-सी में अनावश्यक दबाव-प्रभाव, स्वैच्छिक मताधिकार के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करना व परिवर्तित करना शामिल है। इसमें 1 वर्ष तक के कारावास अथवा आर्थिक दंड अथवा दोनों की व्यवस्था की गई है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-14, 162, 266 (3) और 282 के विषय में

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-14

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का पक्षधर है। इसमें वर्णित उपबंधों के अनुसार, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 162

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार का उल्लेख है। इसमें वर्णित उपबंधों के अनुसार, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा, जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है।
- यद्यपि जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा संघ अथवा उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी।

अनुच्छेद 266 (3)

- भारतीय संविधान में उल्लेखित इस उपबंध के अनुसार, भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से कोई धनराशियां विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित किए जाने की अनिवार्यता का वर्णन है।

अनुच्छेद 282

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 282 में राज्य द्वारा लोक प्रयोजन हेतु किए जाने वाले व्यय के विषय में उल्लेख किया गया है।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण

- राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 29ए के प्रावधानों के अंतर्गत होता है।
- इस धारा के तहत पंजीकरण कराने के इच्छुपक किसी भी संगठन को अपने गठन की तिथि से लेकर 30 दिवस की अवधि के अंदर आयोग में आवेदन-पत्र जमा करना होता है।
- विदित है कि यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत होता है। भारत निर्वाचन आयोग इन दिशा-निर्देशों का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्वआ अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए करता है।

राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह विवादों पर चुनाव आयोग कैसे निर्णय लेता है?

- चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है।
- विदित है कि आदेश के परिच्छेद 15 के अंतर्गत यह प्रतिद्वंदी समूहों अथवा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के मध्य चुनावी चिन्ह से जुड़े विवादों का निराकरण करता है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा निःशुल्क चुनावी उपहार की प्रकृति

- सरकारी योजनाओं के रूप में निःशुल्क घोषणाएँ की जाती है।
- चुनावों में इन योजनाओं को दल विशेष से संबद्ध कर प्रस्तुत किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त सत्ता बनाए रखने के लिए अन्य कई चुनावी घोषणाएँ की जाती हैं।
- विपक्षी दलों द्वारा चुनाव में विजय के मन्तव्य से चुनाव पूर्व अनेक निःशुल्क घोषणाएँ की जाती हैं।

निःशुल्क चुनावी उपहार संस्कृति के आलोचनात्मक पक्ष:

- मुफ्त चुनावी उपहार की संस्कृति सीमित राजनीतिक लाभ से अभिप्रेरित है और सार्वजनिक उद्देश्य हेतु लाभ देने के संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन करती हैं।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं से मतदाताओं का निर्णय प्रभावित होता है।
- भारत के अधिकांश राज्यों में सुदृढ़ वित्तीय ढांचे का अभाव है और राजस्व के मामले में वहाँ बहुत सीमित संसाधन की उपलब्धता है। फलतः इस तरह की संस्कृति राज्यों पर आर्थिक बोझ का कारण बनेगी।
- निःशुल्क उपहार न केवल गरीब और हाशिए के समुदायों का राजनीतिकरण करेगी, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें राज्य के संसाधनों के उनके उचित हिस्से से वंचित करने का कारण बनेगी।
- मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली आपूर्ति, पानी, मुफ्त लैपटाप जैसे चुनावी वायदों के चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल करने से जनता को कई आवश्यक और मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। इसकी कीमत उन्हे बढ़े हुए करों और महंगाई के रूप में भी चुकानी पड़ती है।
- मुफ्त की संस्कृति बिचौलियों की भागीदारी के कारण भ्रष्ट आचरण का मार्ग प्रशस्त करती है।
- मुफ्त उपहारों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम बहुत ही अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं।
- इस तरह की संस्कृति का प्रचलन भारत में तर्कसंगत सोच से परे लोकतांत्रिक राजनीति में व्यक्तित्व दोषों को प्रोत्साहित करेगी।

निष्कर्ष

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक विशेषता का मूलभूत अवयव है। सशक्त लोकतंत्र और टिकाऊ विकास की दृष्टि से निःशुल्क चुनावी उपहार की संस्कृति का प्रचलन हानिकर सिद्ध होगा।
- फलतः केंद्र एवं निर्वाचन आयोग को संयुक्त रूप से इसे नियंत्रित करने हेतु विधिक पहल करनी चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू

जाति के बदलते संदर्भ

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**प्रथम प्रश्न पत्र :** भारतीय समाज

प्रसंग

- जीवन की संभावनाओं को विनियमित करने वाली प्रणाली, राजनीतिक लामबंदी के एक तरीके और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के रूप में जाति के अर्थ में परिवर्तन आया है।
- विदित है कि जाति को एक व्यापक पदानुक्रमित संस्थागत व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। जिसके साथ जन्म, विवाह, भोजन-बंटवारे आदि जैसे बुनियादी सामाजिक कारकों को श्रेणीगत और स्थिति के पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये उप-विभाजन पारंपरिक रूप से व्यवसायों से संबद्ध हैं और उच्च और निचली जातियों के संबंध में सामाजिक संबंधों को निर्धारित करते हैं।

जाति की सक्रियता के वर्तमान संदर्भ

- जाति आज मुख्यतः तीन तरीकों से सक्रिय है।
- सर्वप्रथम, यह एक ऐसी प्रणाली है, जो भौतिक अवसर या जीवन के अवसरों के वितरण को नियंत्रित करती है। फलतः यह स्थायी असमानताओं का एक स्रोत है।
- दूसरा, यह राजनीतिक लामबंदी के प्राथमिक तरीकों में से एक है, भले ही जाति की राजनीति अब पहले की तुलना में कहीं अधिक भिन्न, जटिल और अनिश्चित हो गई है।
- तीसरा और संभवतः सबसे प्रमुख, एक छोटे से उच्च वर्ग को छोड़कर सभी के लिए, उच्च जाति कुलीन जाति समुदाय का एक रूप है, जो रिश्तेदारी, अपनेपन और पहचान की भावना प्रदान करती है।

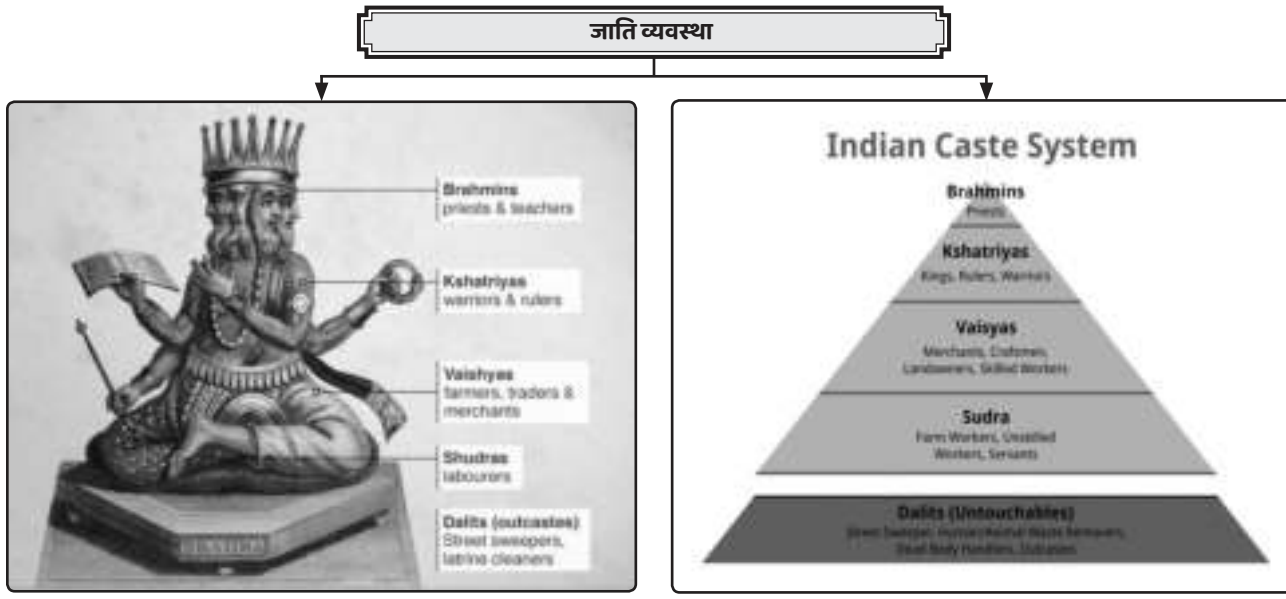

जाति शब्द की व्युत्पत्ति

- जाति शब्द स्पेनिश और पुर्तगाली "कास्टा" से हुई है, जिसका अर्थ है जाति, वंश, या नस्ल।
- पुर्तगालियों ने जाति को आधुनिक अर्थों में नियोजित किया, जब उन्होंने इसे भारत में 'जाति' कहे जाने वाले वंशानुगत भारतीय सामाजिक समूहों पर लागू किया।
- 'जाति' मूल शब्द 'जन' से बना है, जिसका अर्थ है जन्म लेना। इस प्रकार, जाति का संबंध जन्म से है।
- एंडरसन और पार्कर के अनुसार, "जाति सामाजिक वर्ग संगठन का वह चरम रूप है, जिसमें स्थिति पदानुक्रम में व्यक्तियों की स्थिति वंश और जन्म से निर्धारित होती है।

भौतिक अवसरों को विनियमित करने के लिए एक तंत्र के रूप में जाति

- इसे आरक्षण-योग्यता प्रणाली के उत्थान और पतन के रूप में भलिभाति समझा जा सकता है।
- आरक्षण 1932 के पूना पैक्ट से निकला एक पूर्व-स्वतंत्रता विचार था और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संहिताबद्ध था। इसे पिछड़ेपन की अपेक्षा जातिगत भेदभाव के लिए एक उपचारात्मक उपाय के रूप में लागू किया गया।
- नए संविधान ने सैद्धांतिक रूप से जाति को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके अभ्यास में हस्तक्षेप नहीं किया। आरक्षण को अब जातिविहीनता के सामान्य सिद्धांत के अपवाद के रूप में रखा गया था और इसे राज्य द्वारा कुछ जातियों को प्रदान किए जाने वाले एक प्रकार के अनर्जित 'लाभ' के रूप में देखा जाता था।
- आरक्षण योग्यता प्रणाली अब ध्वस्त हो गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा से स्पष्ट है।

राजनीतिक लामबंदी के रूप में जाति

- जाति की राजनीति पहले अस्पृश्यता के अभियान तक सीमित थी, किन्तु पूना पैक्ट के कारण विस्तृत हुई, जिसने प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया कि केवल उच्च जातियों के लिए स्वीकार्य दलित प्रतिनिधि ही चुने जाएंगे।
- संख्या के अप्रतिरोध्य बल के समर्थन में, पिछड़ी जाति के राजनेताओं ने 1960 के दशक में अपने जातिगत निर्वाचन क्षेत्रों को लामबंद करना शुरू कर दिया।
- विदित है कि वर्तमान समय में इसमें एक बड़ा अंतर देखा जा सकता है, जिसे सत्ता में उच्च जाति की राजनीति और निचली जाति की राजनीति के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

पिछड़ी जातियों के भेदभाव पर आंकड़े

- एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) की रिपोर्ट 2019 के अनुसार, एससी/एसटी के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है।
- 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में एससी के खिलाफ अपराध में 7% से अधिक और एसटी के खिलाफ अपराधों में 26% की वृद्धि हुई।
- 2019 में उत्तर प्रदेश में एससी के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए, इसके बाद राजस्थान और बिहार का स्थान है।
- मध्य प्रदेश में एसटी के खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, इसके बाद राजस्थान और ओडिशा का स्थान है।
- 2006 और 2016 के बीच दलितों या अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ 422,799 अपराध और आदिवासियों (एसटी) के खिलाफ 81,332 अपराध दर्ज किए गए।
- एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक 15 मिनट में एक दलित के खिलाफ एक अपराध होता है। हर दिन छह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है।
- 2007 से 2017 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध में 66 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए भारत के संविधान में किए गए प्रावधान

- अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 46 - इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करनी होगी।
- अनुच्छेद 16 (4ए) - राज्यों के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में उन्हें पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देना होता है।
- अनुच्छेद 330 और 332 - संसद, राज्यों की विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

➲ अनुच्छेद 338 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग

➲ हाथ से मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए, भारत सरकार ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 लागू किया है।

➲ ज्ञातव्य है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनिसेफ, आईएलओ, यूएनडीपी विभिन्न हितधारकों के साथ हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और अच्छे रोजगार तक पहुंच वाले समुदायों का पुनर्वास करने के लिए काम कर रही है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2015

➲ दिसंबर 2015 में, भारतीय संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2015 पारित किया।

➲ इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराधों को रोकना और दंडित करना है।

➲ यह ऐसे अपराधों के परीक्षण और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है।

राज्य के प्रयास

➲ राज्यों की विधानसभाओं और संसद में पिछड़ी जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

➲ शिक्षा, विकास की पहल जैसे छात्रवृत्ति, लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, विशिष्ट संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

➲ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1974 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के माध्यम से दलितों के खिलाफ अस्पृश्यता और अत्याचार की रोकथाम की व्यवस्था की गई है।

➲ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास करना है।

➲ स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

➲ 102वें सीएए ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है।

जातिगत भेदभाव को समाप्त करने हेतु किए जा सकने वाले कुछ उपाय

➲ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की समान पहुंच पर बल देने की आवश्यकता।

➲ पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ कुशल नौकरियों तक बेहतर पहुंच के प्रयास।

➲ हाथ से मैला ढोने जैसी नौकरियों को पूर्णतः समाप्त करने की आवशस्यकता।

➲ मास मीडिया का उपयोग करके भेदभाव के बारे में अधिक जागरूकता पैदा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

➲ फलतः बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानता के दृष्टिगत सरकार को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने, भेदभाव को कम करने के लिए सीएसओ, एनजीओ की मदद से व्यवहार में बदलाव लाने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि पर व्यय को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

स्रोतः द हिन्दू

नया वन अधिनियम बनाम आदिवासियों के अधिकार

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रसंग

➲ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने नए वन अधिनियम के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

➲ ज्ञातव्य है कि समिति का गठन इस विवाद के प्रत्युत्तर में किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित नए नियम वनवासियों के अधिकारों को कमजोर करते हैं।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

➲ अनंत नायक (एनसीएसटी के सदस्य) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन

➲ एनसीएसटी एक संवैधानिक निकाय, जिसे संविधान में अनुच्छेद 338ए को सम्मिलित करके 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से स्थापित

➲ वन संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित नए नियमों, एफआरए, 2006 और अन्य संबंधित मुद्दों की जांच

➲ आयोग को संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना अनिवार्य है।

वन संरक्षण नियम

➲ वन संरक्षण नियम, वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 के कार्यान्वयन से संबंधित है।

➲ यह सड़क निर्माण, राजमार्ग विकास, रेलवे लाइनों और खनन जैसे गैर-वानिकी उपयोगों के लिए वन भूमि से संबद्ध अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

➲ विदित है कि वन संरक्षण अधिनियम का व्यापक उद्देश्य वन और वन्यजीवों की रक्षा करना, राज्य सरकारों द्वारा वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए वन भूमि को बंद करने के प्रयासों पर रोक लगाना और वनों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करना है।

वन सलाहकार समिति (एफएसी)

- पांच हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि के लिए भूमि को डायवर्ट करने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए।
- यह एक विशेष रूप से गठित समिति के माध्यम से की जाती है, जिसे वन सलाहकार समिति (एफएसी) कहा जाता है।

वन सलाहकार समिति (एफएसी) की भूमिका

- एफएसी वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है ।
- एफएसी गैर-वन उपयोगों जैसे खनन, औद्योगिक परियोजनाओं, टाउनशिप के लिए वन भूमि के डायवर्जन से जुड़े प्रश्नों पर विचार करता है और राज्य सरकार को वन मंजूरी देने के मुद्दे पर सलाह देता है।
- ध्यातव्य है कि एक बार जब एफएसी आश्वस्त हो जाता है और उसे स्वीकृति प्रदान कर देता है (या प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है), तो इसे संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है, जहां भूमि स्थित है।
- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, जो वनवासियों और आदिवासियों के उनकी भूमि पर अधिकारों की रक्षा करता है, का अनुपालन किया जाता है।
- एफएसी की स्वीकृति का आशय यह भी है कि भूमि के भविष्य के उपयोगकर्ताओं को वनीकरण के लिए प्रतिपूरक भूमि प्रदान करनी होगी और साथ ही शुद्ध वर्तमान मूल्य (10-15 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के बीच) का भुगतान करना होगा।

वन संरक्षण अधिनियम, 2022

- वन संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण जून, 2022 में सार्वजनिक किया गया था।
- यह विभिन्न संशोधनों और अदालती फैसलों से वर्षों में वन संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन को समेकित करता है।
- नए नियम निजी पक्षों के लिए वृक्षारोपण करने और उन्हें भूमि के रूप में कंपनियों को बेचने का प्रावधान करते हैं, जिन्हें प्रतिपूरक वनीकरण लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है ।
- केंद्र सरकार के अनुसार, यह भारत को वन क्षेत्र बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही राज्यों की समस्याओं को उनके अधिकार क्षेत्र में प्रतिपूरक उद्देश्यों के लिए नहीं मिलने की समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।
- विदित है कि पहले के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
- साथ ही नए नियमों में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि आदिवासी और जंगल में रहने वाले समुदायों का क्या होगा, जिनकी भूमि को विकास कार्यों के लिए चयनित किया गया है।
- अद्यतन नियमों से पहले, राज्य निकाय एफएसी को दस्तावेज़ अग्रेषित करेंगे, जिसमें इस स्थिति की जानकारी भी शामिल होगी कि क्या क्षेत्र में स्थानीय लोगों के वन अधिकारों का निपटान किया गया था।

प्रस्तावित संशोधन

- मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि 1980 से पहले रेलवे और सड़क मंत्रालयों द्वारा अधिग्रहित सभी भूमि को अधिनियम से छूट दी जाए। इसमें उल्लिखित है कि इन जमीनों को विस्तार के लिए अधिग्रहित किया गया था, लेकिन बाद में इन क्षेत्रों में जंगल उग आए हैं और सरकार अब विस्तार के लिए भूमि का उपयोग करने में सक्षम नहीं है।
- यदि संशोधन लाया जाता है, तो इन मंत्रालयों को अब अपनी परियोजनाओं के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी और न ही वहां निर्माण के लिए प्रतिपूरक शुल्क का भुगतान करना होगा।
- उन व्यक्तियों के लिए जिनकी भूमि राज्य-विशिष्ट निजी वन अधिनियम के अंतर्गत आती है या 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में निर्दिष्ट वन के शब्दकोश अर्थ में आती है, सरकार आवासीय इकाइयों सहित "वास्तविक उद्देश्यों के लिए संरचनाओं के निर्माण" की अनुमति देने का प्रस्ताव करती है। इसके अंतर्गत एकमुश्त छूट के रूप में 250 वर्ग मीटर तक का प्रावधान है।
- अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास रक्षा परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट प्रदान की गई है।
- वन भूमि से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल तभी जब विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- मंत्रालय ने लीज के नवीनीकरण के दौरान गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए लेवी को हटाने का प्रस्ताव दिया है, इसके अनुसारा लीज देने और नवीनीकरण के समय दोहरा लेवी "तर्कसंगत नहीं है"।
- अधिनियम के तहत आने वाली सड़कों के किनारे पट्टीदार वृक्षारोपण को छूट दी जाएगी।

चिंताएं

- कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं का कहना है कि वन नियमों में ढील से जंगलों के बड़े क्षेत्रों के गायब होने की संभावना है।
- निजी भूमि पर वनों की छूट से कई वन क्षेत्र समाप्त हो जाएँगे। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में 4% भूमि निजी वनों के अंतर्गत आती है।
- 1980 से पहले अधिग्रहित वन भूमि पर सड़कों और रेलवे के लिए छूट जंगलों के साथ-साथ वन्यजीवों - विशेष रूप से हाथियों, बाघों और तेंदुओं के लिए हानिकारक होगी।
- पर्यावरणविदों का कहना है कि निजी वनों पर निजी आवासों के लिए एक बार की छूट से वनों का विखंडन होगा और अरावली पहाड़ों जैसे खुले क्षेत्रों में अचल संपत्ति का निर्माण होगा।
- संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक बार वन मंजूरी मिल जाने के बाद, वनवासियों और आदिवासियों के किसी भी दावे को मान्यता नहीं दी जाएगी और उसका निपटारा नहीं किया जाएगा।
- वन भूमि के परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों पर केंद्र की ओर से और भी अधिक दबाव डाला जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

- इस अधिनियम को अम्ब्रेला एक्ट के रूप में जाना जाता है। यह केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए अधिकृत करता है। इसमें पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण को रोकना और औद्योगिक सुविधाओं के संचालन को प्रतिबंधित करना शामिल है।

- इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। इसमें 26 खंड और 4 अध्याय हैं।
- विदित है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में उल्लिखित है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे।
- अनुच्छेद 51A में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बाध्य है।

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लोगों की भागीदारी के माध्यम से खराब हो चुके वनों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम लागू किया है।
- यह वर्ष 2000 में शुरू किया गया था, जो वन सीमांत समुदायों की आजीविका पर केंद्रित है।
- यह योजना राज्य वन विकास एजेंसी (SFDA), वन विकास एजेंसी (FDA) और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMC) को शामिल करते हुए त्रि-स्तरीय सेटअप के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

भारत वन नीति 1952

- इसका उद्देश्य कुल भूमि क्षेत्र का एक तिहाई, पहाड़ी क्षेत्रों में 65% और मैदानी इलाकों में 25% के साथ, वन कवर के तहत लाना और वन्यजीवों और जंगलों की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश देना था।
- राष्ट्रीय वन नीति ने वनों के लिए एक कार्यात्मक सक्षमता का निर्धारण किया।
- संरक्षण वन अत्यधिक जलवायु और हिमस्खलन, भूस्खलन, कटाव और बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों का सामना करने के लिए संरक्षित हैं। यह वास्तव में एक क्षेत्र की मिट्टी, पानी और जलवायु परिस्थितियों पर एक सुरक्षात्मक कारक के रूप में कार्य करते हैं।
- वहीं राष्ट्रीय वन रक्षा, संचार, उद्योग और राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों के लिए संरक्षित हैं।
- ग्राम वन को "ईंधन वन" के रूप में जाना जाता था और गाँव की आबादी की आवश्यकता पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जलाऊ लकड़ी, खाद और अन्य स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम वनों द्वारा की जाती है।

निष्कर्ष

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन भूमि मोड़ के लिए दबाव पर सार्वजनिक विमर्श की अनुमति प्रदान की है।
- इसने अधिसूचित वनों के लिए वन कानूनों को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव किया है, अपराधों को गैर-जमानती बनाने के साथ-साथ एक वर्ष तक के कारावास सहित बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया है।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

नागोर्नो-काराबाख विवाद

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव

प्रसंग

- हाल ही में, नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य विवाद बढ़ गया।
- विदित है कि नागोर्नो-कराबाख को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद काफी पुराना है। यह क्षेत्र अजरबैजान में स्थित है।
- यह विवाद 3 अगस्त को शुरू हुआ, जब अजरबैजान ने दावा किया कि उसने एक जवाबी अभियान में कराबाख में क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, एक अर्मेनियाई हमले के बाद एक अज़रबैजान सैनिक की मौत हो गई थी।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

हाल ही में उत्पन्न विवाद के कारण और संघर्ष विराम की पृष्ठभूमि

- यह विवाद 3 अगस्त को शुरू हुआ, जब अजरबैजान ने दावा किया कि उसने एक जवाबी अभियान में कराबाख में क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।
- अर्मेनियाई हमले के बाद एक अज़रबैजान सैनिक की मृत्यु हो गई थी।
- नागोर्नो-कराबाख के विवादित दक्षिण काकेशस क्षेत्र में 2020 से युद्धविराम प्रभावी है। इस महीने की शुरुआत में संवेदनशील समझौते का उल्लंघन किया गया था, जो परस्पर विरोधी पक्ष - आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य घातक झड़पों का कारण बना।
- विदित है कि यह क्षेत्र अभी अजरबैजान में है। यद्यपि, इस पर 1994 से आर्मेनिया का नियंत्रण है। इस क्षेत्र में 2020 में भी एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में 6600 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। 6 सप्ताह तक चले युद्ध के बाद रूस ने मध्यस्थता कर दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराया था। रूस ने क्षेत्र में दो हजार से ज्यादा सैनिकों को भेजा था।
- अतीत में हुए कई युद्धविराम समझौतों के बावजूद नागोर्नो-कराबाख संघर्ष गतिरोध बना हुआ है। बाकू और येरेवन दोनों उस क्षेत्र के पूर्ण ऐतिहासिक स्वामित्व का दावा करते हैं, जो अज़रबैजान की सीमाओं के भीतर स्थित है, लेकिन यहाँ जातीय अर्मेनियाई लोगों की बड़ी आबादी है।
- अजरबैजान द्वारा कराबाख पर कब्जा करने की घोषणा के बाद, नागोर्नो-कराबाख में सेना ने दावे को विवादित कर दिया और अजरबैजान पर दो सैनिकों की हत्या का आरोप लगाया, संघर्ष के जवाब में "आंशिक लामबंदी" की घोषणा की।
- आर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अज़रबैजान की "आक्रामक कार्रवाइयों" को रोकने में मदद करने का आह्वान किया है। उसने यह दावा किया कि अज़रबैजान नागोर्नो-कराबाख की आबादी के खिलाफ "आतंक की नीति" जारी रखता है।

- रूस ने अज़रबैजान पर 2020 के युद्धविराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है और दावा किया है कि वह अर्मेनियाई और अज़रबैजानी प्रतिनिधियों के साथ "स्थिति को स्थिर करने के उपाय" कर रहा था।

क्या कहता है 2020 का समझौता?

- 10 नवंबर, 2020 के नौ सूत्री समझौते पर अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर किए।
- समझौते ने तत्काल युद्धविराम, अज़रबैजान के कब्जे वाले क्षेत्रों से वापसी की समयसीमा, रूसी शांति सैनिकों की शुरूआत और नए परिवहन गलियारों की आवश्यकता को प्रभावी किया।
- यद्यपि, यह शांति समझौते को प्रभावी करने में विफल रहा, क्योंकि इसने दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन को बदल दिया। साथ ही, संबद्ध पक्षों में कई मुद्दों पर स्पष्टता का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने बाद में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

शांति समझौते के संदर्भ में प्रगति

- दोनों पक्षों के मध्य 2020 के बाद से, बातचीत की प्रक्रिया धीमी रही है।
- अर्मेनिया और अजरबैजान द्वारा की गई कूटनीतिक पहल से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर वार्ता प्रक्रिया में विलंब करने का आरोप लगाया है।
- ध्यातव्य है कि युद्ध के दो वर्ष पश्चात 2022 में दोनों पक्षों ने नागोर्नो-कराबाख के लिए शांति योजना पर चर्चा करने की मंशा व्यक्त की थी। इस हेतु दोनों नेताओं ने ब्रसेल्स में मुलाकात की, जिसके दौरान अज़रबैजान ने अपनी निराशा व्यक्त की कि बाद की कूटनीति बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी है, क्योंकि आर्मेनिया भू-राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में बदलने की मंशा से वार्ता को लम्बा खींच रहा था।

नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र

- यह एक पहाड़ी और घना वन क्षेत्र, जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह काकेशस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग और आर्मीनियाई पर्वतीय मैदान के पूर्वी भाग के बीच स्थित है।
- जातीय अर्मेनियाई लोगों की बड़ी आबादी है, जो अज़ेरी शासन (अज़रबैजान की कानूनी प्रणाली) को अस्वीकार करते हैं।

विवाद के कारण

- पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मीनिया और अज़रबैजान नागोर्नो-काराबाख के इलाक़े को लेकर 1980 के दशक में और 1990 के दशक के शुरूआती दौर में संघर्ष कर चुके हैं।
- दोनों ने युद्धविराम की घोषणा भी की, किन्तु सही अर्थों में शांति समझौते पर दोनों के मध्य कभी सहमति नहीं बन पाई।
- दक्षिण-पूर्वी यूरोप में पड़ने वाली कॉकेशस के क्षेत्र की पहाड़ियां रणनीतिक रूप से बहुत अहम मानी जाती हैं। सदियों से क्षेत्र की मुसलमान और ईसाई ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती रही हैं।
- 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना, तो अभी के ये दोनों देश आर्मीनिया और अज़रबैज़ान उसका हिस्सा बन गए। विदित है कि ये सोवियत गणतंत्र कहलाते थे।
- नागोर्नो-काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मीनियाई है, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने उसे अज़रबैजान के हाथों सौंप दिया।
- इसके बाद दशकों तक नागोर्नो-काराबाख के लोगों ने कई बार ये इलाक़ा आर्मीनिया को सौंपने की अपील की।
- दोनों पक्षों के मध्य वास्तविक विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ और नागोर्नो-काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर स्वयं को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया।
- इसके बाद यहां शुरू हुए अलगाववादी आंदोलन को अज़रबैजान ने ख़त्म करने की कोशिश की। हालांकि, इस आंदोलन को लगातार आर्मीनिया का समर्थन मिलता रहा।
- परिणाम ये हुआ कि यहां जातीय संघर्ष होने लगे और सोवियत संघ से पूरी तरह आज़ाद होने के बाद एक तरह का युद्ध शुरू हो गया।
- यहां हुए संघर्ष के कारण लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। दोनों पक्षों की तरफ़ से जातीय नरसंहार की शुरुआत हुई।
- वर्ष 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्धविराम की घोषणा से पहले नागोर्नो-काराबाख पर आर्मीनियाई सेना का क़ब्जा हो गया।
- इस समझौते के बाद नागोर्नो-काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा तो रहा, किन्तु इस क्षेत्र पर अलगाववादियों का अधिकार रहा, जिन्होंने इसे गणतंत्र घोषित कर दिया। यहां आर्मीनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी, जिसमें आर्मीनियाई जातीय समूह से जुड़े लोग थे।
- इस समझौते के तहत नागोर्नो-काराबाख लाइन ऑफ़ कॉन्टैक्ट भी बना, जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के सैनिकों को अलग करता है।
- इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए 1929 में फ्रांस, रूस और अमेरिका की अध्यक्षता में बनी ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिंस्क ग्रुप की मध्यस्थता में शांति वार्ता जारी है, लेकिन अब तक किसी समझौते तक पहुंचा नहीं जा सका है.
- बीते तीन दशक से यहां रह रह कर तनाव गहरा जाता है और झड़पें भी होती हैं।

युद्धविराम समझौते पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है?

- विभिन्न विवादित मुद्दों के कारण दोनों पक्षों के मध्य बार-बार संघर्ष विराम उल्लंघन होता है। प्रमुख मुद्दों में दोनों देशों के बीच सीमा का परिसीमन, क्षेत्र में नए परिवहन गलियारों की प्रकृति और नागोर्नो-कराबाख और इसकी वर्तमान जातीय अर्मेनियाई आबादी का भविष्य शामिल है।
- पहला साझा अंतरराष्ट्रीय सीमा के परिसीमन का मुद्दा है। 2020 के समझौते के बाद, अर्मेनियाई कराबाख से अजरबैजान को पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र सौंप दिया गया, जो आर्मेनिया और नागोर्नो-कराबाख के बीच एक बार सॉफ्ट बार्डर बनाने से जुड़ा था, यद्यपि यह एक जटिल अंतरराष्ट्रीय सीमा थी।
- हालांकि, अर्मेनिया और अजरबैजान अतीत में कभी भी उनके बीच सीमा पर सहमत नहीं हुए हैं और 2020 के युद्धविराम ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सीमा को वास्तव में कैसे रेखांकित किया जाना चाहिए।

- दूसरा, परिवहन मार्गों पर विवाद का मुद्दा है। स्टेपानाकर्ट (नागोर्नो-कराबाख क्षेत्र के भीतर एक शहर) से अर्मेनिया तक जाने वाला भूमिगत मार्ग दोनों देशों के बीच एक मुद्दा बन गया है।
- 2020 के समझौते में कहा गया है कि पक्षों को तीन साल के भीतर एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण करना चाहिए, जिसके बाद वर्तमान मार्ग पर तैनात रूसी शांति सैनिकों को नए रास्ते पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- वर्तमान में, केवल एक ही सड़क लाचिन कॉरिडोर है, जो अज़रबैजान के पहाड़ी लाचिन क्षेत्र से शुशा तक चौकी से गुजरती है, जिसे अज़रबैजान की सेना ने 2020 के युद्ध में वापस ले लिया था। सड़क का निर्माण अज़रबैजान को लाचिन शहर और आस-पास के क्षेत्रों पर नियंत्रण वापस लेने की अनुमति देगा। हालांकि, अज़रबैजान ने आर्मेनिया पर नई सड़क के कई किलोमीटर खंड को बिछाने के संचालन को रोकने का आरोप लगाया है।
- तीसरा, नागोर्नो-कराबाख की स्थिति पर अंतर का मुद्दा है। नागोर्नो-कराबाख के जातीय रूप से अर्मेनियाई एन्क्लेव, जिसे कलाख गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है, ने एक बड़े संभावित शांति समझौते के हिस्से के रूप में अज़रबैजान को रियायतें देने की आर्मेनिया की इच्छा पर निराशा व्यक्त की है। जबकि आर्मेनिया नागोर्नो-कराबाख की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं का समर्थन करता है, अज़रबैजान अपनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहता है।

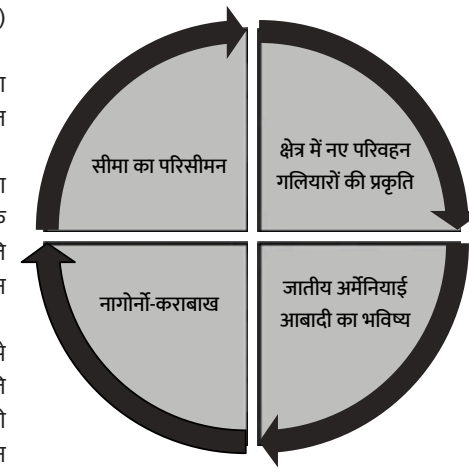

- 2020 के समझौते के अनुसार, बिंदु एक का दावा है कि संघर्ष के पक्षों को "अपनी वर्तमान स्थिति में रुकना" चाहिए, जबकि बिंदु चार में कहा गया है कि रूसी शांति सेना को अर्मेनियाई सैनिकों की वापसी के साथ-साथ तैनात किया जाएगा। हालांकि, दोनों पक्ष आर्मेनिया के साथ इन बिंदुओं की अलग-अलग व्याख्या करते हैं, जिसमें कहा गया है कि पहला बिंदु उन्हें अपनी सेना को करबाख में रखने की अनुमति देता है और उन्होंने करबाख के आसपास के सात अज़रबैजानी जिलों से सशस्त्र बलों को वापस लेकर चौथे बिंदु का अनुपालन किया है। इसके विपरीत, अज़रबैजान का कहना है कि जैसे ही रूसियों को जमीन पर तैनात किया गया था, अर्मेनियाई सेना को कराबाख से वापस लेना चाहिए था, यह तर्क देते हुए कि बल अवैध है और रूसी शांति सैनिकों से इसे निरस्त्र करने का आग्रह किया है।
- चौथा, दोनों पक्षों के मध्य कैदियों की अदला-बदली को लेकर विवाद है। आठवें बिंदु के अनुसार, दोनों पक्षों को युद्धबंदियों, बंधकों और अन्य हिरासत में लिए गए व्यक्तियों और शवों का आदान-प्रदान करना था। जबकि पिछले दो वर्षों में कैदियों के आदान-प्रदान की एक श्रृंखला हुई है, अज़रबैजान पक्ष में अभी भी कई बंदी हैं जबकि आर्मेनिया के पास कुछ ही हैं।

मिन्स्क समूह

- मिन्स्क समूह, जिसकी गतिविधियों को मिन्स्क प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, नागोर्नो-कराबाख संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए ओएससीई के प्रयासों का नेतृत्व करता है।
- इसकी सह-अध्यक्षता फ्रांस, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाती है।
- यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) के निर्देशन में नागोर्नो-कराबाख संघर्ष के शांतिपूर्ण, समाधान की परिकल्पना की गई थी।

समूह के स्थायी सदस्य

- अज़रबैजान
- आर्मीनिया
- बेलारूस
- जर्मनी
- इटली
- स्वीडन
- फिनलैंड
- टर्की

क्षेत्र का सामरिक महत्व

- ऊर्जा संसाधनों से सम्पन्न अजरबैजान ने काकेशस (काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का क्षेत्र) से तुर्की और यूरोप तक कई गैस और तेल पाइपलाइनों का निर्माण किया है ।
- इनमें से कुछ पाइपलाइन संघर्ष क्षेत्र (सीमा के 16 किमी के भीतर) के समीप से गुजरती हैं।
- दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति में, पाइपलाइनों को लक्षित किया जा सकता है, जो ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करेगा और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भी वृद्धि का कारण बन सकता है।

नागोर्नो-काराबाख और भारत

- भारत के पास "पड़ोसी पहले", "एक्ट ईस्ट" या "मध्य एशिया कनेक्ट" के विपरीत की दक्षिण काकेशस के लिए सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नीति नहीं है, यद्यपि यह क्षेत्र भारत की विदेश नीति के रडार की परिधि पर बना हुआ है। इसके अलावा, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया के साथ भारत के संबंधों में विषमता दिखाई देती है।
- अर्मेनिया इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके साथ भारत की मित्रता और सहयोग संधि (1995 में हस्ताक्षरित) है, फलतः नागोर्नो-कराबाख में अज़रबैजान के आक्रमण की स्थिति में भारत को अज़रबैजान को सैन्य या कोई अन्य सहायता प्रदान नहीं कर सकता है।
- आर्मेनिया कश्मीर मुद्दे पर भारत को अपना स्पष्ट समर्थन देता है जबकि अजरबैजान न केवल समर्थन करता है बल्कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के आख्यान को भी बढ़ावा देता है। तथापि, आर्मेनिया के साथ भारत के व्यापार या निवेश का स्तर बहुत कम है।
- अजरबैजान के मामले में, ओएनजीसी/ओवीएल ने अजरबैजान में एक तेल क्षेत्र परियोजना में अपेक्षाकृत कम निवेश किया है और गेल एलएनजी में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है।
- अज़रबैजान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर मार्ग पर पड़ता है, जो भारत को मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ता है। साथ ही यह बाकू-त्बिलिसी-कार्स पैसेंजर और फ्रेट रेल लिंक के माध्यम से भारत को तुर्की और उससे आगे भी जोड़ सकता है।
- यूरो-अटलांटिक संरचनाओं के साथ एकीकरण की जॉर्जिया की विदेश नीति की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए और रूस की संवेदनशीलता के सम्मान में, भारत ने जॉर्जिया के साथ अपने संबंधों के विकास को धीमा कर दिया है, जिसके साथ रूस के संबंध बहुत कम हैं।

- भारत ने नागोर्नो-कराबाख संघर्ष पर अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया है क्योंकि वर्षों से स्थिति विकसित हुई है। 1993 में संघर्ष के शुरुआती चरणों में, भारत ने क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान की अवधारणा का समर्थन किया था। पिछले कुछ समय से, भारत का जोर राजनयिक वार्ताओं के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर रहा है।
- भारत ने इस मुद्दे पर एक संतुलित और तटस्थ रुख अपनाया है। साथ ही, संयम और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और राजनयिक वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्वक संघर्ष के समाधान का आह्वान किया है।
- भारत ने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ओएससीई मिन्स्क समूह के निरंतर प्रयासों के लिए भी अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिसका अर्थ है कि भारत तुर्की सहित किसी अन्य संस्था की भागीदारी के पक्ष में नहीं है।

निष्कर्ष

- 2020 के समझौते में नए परिवहन कनेक्शन और आर्थिक सहयोग के अवसर खोलने की क्षमता है, आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य संघर्ष की स्थिति इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी।
- इसके अलावा, समझौते के पक्षपातपूर्ण होने के लिए आलोचना की गई है। इसके अलावा, समझौता दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दों को हल करने में भी विफल रहा है। इस प्रकार, जब तक इन कमियों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक संघर्ष विराम उल्लंघन जारी रहने की संभावना है।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

इज़राइल-फिलीस्तीन संघर्ष विराम

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव

प्रसंग

- हाल ही में, इजरायल और फिलीस्तीन उग्रवादियों ने गाजा में संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की है।
- ज्ञातव्य है कि दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष विराम लगभग तीन दिनों की हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रभावी किया गया है, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी की मृत्यु हुई और गाजा में सैकड़ों हजारों इजरायलियों का जीवन बाधित हुआ।
- ज्ञातव्य है कि दोनों पक्षों के मध्य युद्धविराम की मध्यस्थता मिस्र द्वारा की गई थी, जिसने अतीत में भी इजरायल और गाजा के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया है।

इजरायल-फिलीस्तीन विवादित क्षेत्र

वेस्ट बैंक
- वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के मध्य में स्थित है।
- इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद से इसे अपने कब्जे में कर रखा है।
- इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस क्षेत्र को लेकर दावा करते हैं।

गोलन हाइट्स
- राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण यह क्षेत्र सीरिया का एक पठार है।
- 1967 के बाद से ही इस पर इजराइल का कब्जा है।
- इस क्षेत्र में कब्जे से जुड़े विवाद को लेकर कई बार शांति वार्ता के प्रयास किए जा चुके हैं, किन्तु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

गाजा पट्टी
- गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के मध्य में स्थित है।
- यह लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर लंबा है।
- यहाँ हमास का कब्जा है, जो इजराइल विरोधी समूह है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- गत वर्ष इस्राइल और हमास के मध्य 11 दिनों तक चले युद्ध के बाद से सीमा पार हिंसा में बढ़ोतरी दृष्टिगत हुई।
- संघर्ष के परिणामस्वरूप इस्राइली हवाई हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ कमांडर, ईरान समर्थित आतंकवादी समूह शामिल हैं, जो एक लक्षित हमले में मारे गए थे।
- इज़राइल ने कई घातक हवाई हमले किए हैं, उनमें से एक ईरान समर्थित आतंकवादी समूह, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ कमांडर की लक्षित हत्या भी शामिल है। आतंकवादियों ने इजरायल के शहरों और कस्बों पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं, जिससे हजारों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

इज़राइल-फिलीस्तीन विवाद की पृष्ठभूमि

- इज़राइल-फिलीस्तीन संघर्ष कम से कम 100 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है।
- विदित है कि वर्तमान में जहां इजराइल है, वहां कभी तुर्की का शासन था, जिसे ओटोमान साम्राज्य कहा जाता था।
- 1914 में पहला विश्व युद्ध के समय तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ वाले देशों का साथ दिया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था। परिणामतः तुर्की और ब्रिटेन आमने-सामने आ गए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध जीता और ओटोमान साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया।
- इस समय तक जियोनिज्म की भावना चरम पर थी। ये एक राजनीतिक विचारधारा थी, जिसका उद्देश्य एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। इसी के कारण दुनियाभर से यहूदी फिलिस्तीन में आने लगे।
- 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेलफोर ने एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संघर्ष की शुरुआत

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने फिलिस्तीन और इजरायल के नए राज्य के बीच फिलिस्तीन के अरब-यहूदी विभाजन का प्रस्ताव रखा।
- इस विभाजन योजना ने 53 प्रतिशत भूमि यहूदी-बहुल राज्य (इज़राइल) को और 47 प्रतिशत फिलिस्तीनी-बहुल राज्य (फ़िलिस्तीन) को अनिवार्य कर दी।
- यह विभाजन योजना मध्य पूर्व के अरब देशों के अनुरूप नहीं था।

हमास और ईरान

- इस्लामिक जिहाद गाजा पट्टी में दो मुख्य फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों में से छोटा है और सत्तारूढ़ हमास समूह द्वारा बहुत अधिक संख्या में है।
- इसे ईरान से प्रत्यक्ष वित्तीय और सैन्य समर्थन प्राप्त है और यह रॉकेट हमलों और इज़राइल के साथ अन्य टकरावों में शामिल होने में प्रेरक शक्ति बन गया है।
- इस समूह की स्थापना 1981 में वेस्ट बैंक, गाजा और अब इजरायल में एक इस्लामी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिकी विदेश विभाग, यूरोपीय संघ और अन्य सरकारों द्वारा एक आतंकवादी संगठन नामित किया गया है।
- इसकी जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड की फ़िलिस्तीनी शाखा में हैं और यह फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के अंदर एक मजबूत सामाजिक-राजनीतिक संरचना द्वारा समर्थित है।
- समूह का चार्टर इजरायल के स्थान पर एक इस्लामी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए निर्देशित करता है।
- विदित है कि हमास गाजा पट्टी और पश्चिमी तट के क्षेत्रों में केंद्रित है।
- इज़राइल का शत्रु देश ईरान इस्लामिक जिहाद को प्रशिक्षण, विशेषज्ञता और धन की आपूर्ति करता है, लेकिन समूह के अधिकांश हथियार स्थानीय रूप से उत्पादित होते हैं।
- हाल के वर्षों में, इसने एक शस्त्रागार विकसित किया है, जिसमें लंबी दूरी के रॉकेट हैं, जो मध्य इज़राइल के तेल अवीव महानगरीय क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम हैं।

अरब इजरायल प्रथम युद्ध (1948)

- 14 मई, 1948 को इजरायल की स्थापना के तुरन्त बाद ही अमरीका ने उसे समर्थन प्रदान किया।
- 15 मई, 1948 को मिस्र, इराक, जोर्डन, सीरिया व लेबनान की संयुक्त अरब सेना ने इजरायल पर हमला किया।
- इस युद्ध में इज़राइल ने जीत हासिल की और 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना में पहले से परिकल्पित भूमि की तुलना में अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया।
- 7 जनवरी, 1949 को युद्ध विराम लागू हो गया परन्तु तब तक इसरायल ने अपने क्षेत्र मे 50 प्रतिशत की वृद्धि कर ली थी।

1967 का छह दिवसीय युद्ध

- 1967 में अरब देशों ने फिर से इज़राइल को एक राज्य के रूप में मान्यता देने से मना किया और युद्ध की घोषणा की, जिसे छह-दिवसीय युद्ध के रूप में जाना जाता है।
- इस युद्ध में भी इजरायल ने जीत हासिल की और फिलिस्तीन के और भी अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लिया।
- वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम, जिसमें पवित्र पुराना शहर है, इजरायल के नियंत्रण में आ गया।
- इसने सीरियाई गोलान हाइट्स और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर भी कब्जा कर लिया ।

ओस्लो समझौता

- इसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा समर्थन प्राप्त था।
- यह 1993 में इजरायल सरकार और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) के बीच हस्ताक्षर किया गया था।
- इसके तहत वेस्ट बैंक का एक हिस्सा फिलिस्तीनी सत्ता के नियंत्रण में आ गया।

फिलिस्तीन और इजराइल की मांग

- फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल 1967 से पहले की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो।
- साथ ही इजराइल पूर्वी येरूशलम से अपना दावा छोड़े, क्योंकि फिलिस्तीन आजाद होने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है।
- वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन की मांगों को मानने से स्पष्ट मना कर दिया है।
- इजराइल येरुशलम से अपना दावा छोड़ने को सहमत नहीं है। उसका कहना है कि येरूशलम हमारी राजधानी है और ये इजराइल का अभिन्न अंग है।

वर्तमान परिदृश्य

- इज़राइल ने पूरे यरुशलम को अपनी राजधानी के रूप में मान्यता दी है। यद्यपि फ़िलिस्तीनी इससे सहमत नहीं हैं और चाहते हैं कि यह भविष्य के स्वतंत्र फ़िलिस्तीन की राजधानी बने।
- इस वर्ष की शुरुआत में, पूर्वी यरुशलम में सेंट्रल कोर्ट ने यहूदी बसने वालों के पक्ष में शेख जर्राह में चार फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घरों से बेदखल करने के निर्णय को बरकरार रखा।
- हाल ही में, रमजान की शुरुआत के साथ, इजरायली पुलिस ने दमिश्क गेट पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिससे फिलिस्तीनियों के लिए समस्या पैदा हो गई थी।
- इजरायली पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद के अंदर धावा बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह यरूशलेम दिवस पर किया गया था ।
- जवाबी कार्रवाई में, इस्लामी आतंकवादी समूह हमास ने दर्जनों रॉकेट दागे ।
- प्रत्युत्तर में इजरायल ने गाजा पर हवाई हमला किया, जिसमें 16 बच्चों सहित कम से कम 65 फिलिस्तीनी मारे गए।

इजरायल फिलिस्तीन के हाल के निर्णय पर भारत का पक्ष

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में हिंसा पर एक आपातकालीन सत्र के दौरान इजरायल और फिलिस्तीनी सरकारों के बीच बातचीत को तत्काल फिर से शुरू करने का आह्वान किया।
- भारत ने विशेष रूप से प्रभावी संघर्ष विराम में मदद करने के लिए मिस्र सरकार को धन्यवाद दिया।
- भारत के लिए विशेष चिंता फिलिस्तीनी नागरिक को मानवीय सहायता प्रदान करना है। गाजा में आबादी, विदित है कि हाल के संघर्ष के कारण गाजा में अधिकांश आबादी प्रभावित हुई थी।

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष पर बातचीत की वापसी को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का पक्ष

- भारत फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में "दृढ़" रहा है और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में लगातार मतदान किया है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया था, जिसने 2017 में यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कड़ी आलोचना की थी ।
- भारत ने 2018 में एक और यूनजीए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जिसमें फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजरायली बलों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की थी।
- भारत ने लगातार उन प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया है, जो पूर्वी यरुशलम पर फिलीस्तीनी दावे के साथ दो-राज्य समाधान को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष

- "इजरायल और फिलिस्तीन में दीर्घकालिक शांति हेतु आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से दो-राज्य समाधान की दिशा में कार्य किया जाये।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से "दो-राज्य समाधान" पर आधारित शांति की बहुत आवश्यकता है और इसे केवल इज़राइल-फिलिस्तीन वार्ता से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- चूंकि भारत का इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छा संबंध रहा है। ऐसे में भारत इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान की दिशा में "उन्नत" भूमिका निभा सकते हैं ।

गाजा पट्टी

- गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच तटीय किनारे पर स्थित है
- यह लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर लंबा है।
- 1948 में अरब-इजरायल युद्ध के बाद से इस पट्टी पर मिस्र का कब्जा था, लेकिन 1967 में इजरायल ने मिस्र को हराकर इस पट्टी पर कब्जा कर लिया।
- यद्यपि, इसका दक्षिणी हिस्सा मिस्र के कब्जे में ही था। इसके दो तरफ इजरायल और दक्षिण में मिस्र है, जबकि पश्चिम की तरफ भूमध्यसागर है।
- इसकी समुद्री सीमाएं इजरायल के कब्जे में है। गाजा पट्टी में कुल 15 लाख लोग रहते है, जिनमें से अधिकतर मुस्लिम हैं।
- 2005 में इजरायल ने गाजा पट्टी से हट जाने का फैसला किया और गाजा पट्टी से यहूदी बस्तियों को भी हटाना शुरू कर दिया।
- 2007 में हुए चुनाव ने गाजा पट्टी पर हमास ने कब्जा कर लिया। हमास इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका जैसे देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं।
- 2007 के आखिर में गाजा पट्टी को दुशमन क्षेत्र घोषित किया और इसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

ईरान परमाणु समझौता वार्ता

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत के हित को प्रभावित करने वाले करार या समझौते

प्रसंग

- हाल ही में, वर्ष 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अमेरिका और ईरान के मध्य वियना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नए दौर की वार्ता आयोजित की गई।
- विदित है कि विश्व शक्तियों और ईरान के अधिकारी के मध्य मार्च 2022 के बाद पहली बार ऑस्ट्रिया की राजधानी में बैठक आयोजित की गई।
- विभिन्न पक्षों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक बार पुनः प्रतिबंध लगाने की अपेक्षा प्रतिबंध हटाने के लिए मतभेद के विभिन्न बिन्दुओं के समाधान की मांग की।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

क्या है और स्थापना वर्ष

- यह विश्व का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है, जो वर्ष 1957 में स्थापित किया गया।

कार्य

- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और सैन्य उद्देश्य के लिये परमाणु हथियारों के प्रयोग पर रोकथाम

अंतर-सरकारी मंच

- विश्व भर में परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग हेतु प्रतिबद्ध

प्रतिवेदन

- संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

ईरान परमाणु समझौता/ संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)

- ईरान परमाणु समझौता को औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के रूप में जाना जाता है।

- जेसीपीओए जुलाई 2015 में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई विश्व शक्तियों के मध्य सम्पन्न हुआ एक ऐतिहासिक समझौता है।
- विदित है कि इसके अंतर्गत ईरान ने अरबों डॉलर के प्रतिबंधों से राहत के बदले में अपने अधिकांश परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने हेतु सहमति व्यक्त की और इसे अधिक व्यापक अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोल दिया।
- समझौते का समर्थन करने वाले पक्षों ने कहा कि यह ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के पुनरुद्धार को रोकने में मदद करेगा और इस तरह ईरान और उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के बीच संघर्ष की संभावनाओं को कम करेगा, जिसमें इजरायल और सऊदी अरब शामिल हैं।
- यद्यपि वर्ष 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को इससे पृथक करने के बाद से यह समझौता संकट में है।
- 2021 में, राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि अगर ईरान समझौते के अनुपालन पर सहमति व्यक्त करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका समझौते पर वापस आने के लिए तैयार है। यद्यपि इसका कोई आशाजनक परिणाम नहीं निकला।

शामिल प्रतिभागी

- जेसीपीओए जनवरी 2016 में प्रभावी हुआ। यह ईरान के असैन्य परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
- ईरान के साथ बातचीत के केंद्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका), यूरोपीय संघ और जर्मनी ने भाग लिया, जिसे सामूहिक रुप से P5 + 1 के रूप में संबोधित किया जाता है।

ईरान परमाणु समझौते की पृष्ठभूमि

- 1970 के दशक में ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने परमाणु कार्यक्रम में सहायता प्राप्त हुई थी। विदित है कि यह सहयोग ईरान को 'शांति के लिए परमाणु' कार्यक्रम' से संबद्ध थी। साथ ही ईरान ह ने अप्रसार संधि पर भी हस्ताक्षर किए।
- इसने 1968 में एक गैर-परमाणु हथियार राज्य के रूप में परमाणु हथियार (एनपीटी) और 1970 में एनपीटी की पुष्टि की।
- यद्यपि ईरानी क्रांति ने देश के परमाणु कार्यक्रम को अस्त-व्यस्त कर दिया और अमेरिका-ईरान के द्विपक्षीय सम्बन्धों को भी प्रभावित किया।
- 1980 के दशक के अंत में ईरान ने पाकिस्तान की सहायता से अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से बहाल किया।
- हालांकि ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था। किन्तु पश्चिमी शक्तियों और उनके मध्य पूर्व के सहयोगियों के लिए ईरान का पक्ष संदेहास्पद था।
- 2000 के दशक के दौरान ईरान और पश्चिमी देशों के मध्य वार्ता हुई।
- वर्ष 2015 में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर विश्व शक्तियों के एक समूह के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर सहमत हुआ।

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)

- जेसीपीओए ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया, जो परमाणु हथियारों में उपयोग किए जाने वाले अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम को विकसित करने की अपनी क्षमता को सीमित करता है। इसमें शामिल था:
- परमाणु तत्वों को समृद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने उन्नत सेंट्रीफ्यूज को विघटित करना,
- यूरेनियम संवर्धन के अपने स्तर को सीमित करना, ताकि ईरान इसे अधिकतम 67% तक ही समृद्ध कर सके।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा अपनी परमाणु सुविधाओं की कड़ी निगरानी के लिए सहमत होना।
- इसके बदले में, हस्ताक्षरकर्ता ईरान पर लगाए गए परमाणु प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने के लिए सहमत हुए, जो आईएईए की जेसीपीओए प्रतिबंधों के साथ तेहरान के अनुपालन की आवधिक समीक्षा पर निर्भर करता है।
- इन प्रतिबंधों में ईरान के ऊर्जा, शिपिंग, वित्तीय और ऑटोमोटिव क्षेत्रों पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूएनएससी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध शामिल थे।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने समझौते को लागू करने, ईरान पर नज़र रखने और निरीक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

ईरान पर पूर्व के प्रतिबंध

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन), अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) ने ईरान को यूरेनियम संवर्धन पर रोकथाम के लिए विवश करने हेतु कई प्रतिबंध लगाए ।
- इसने ईरान की अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित किया। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2012 से 2016 तक ईरान के तेल राजस्व में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत आई।
- जेसीपीओए के अंतर्गत ईरान ने विदेशों में जमा हुई संपत्ति में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पहुंच प्राप्त की और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की बिक्री फिर से शुरू करने और व्यापार के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम था।

अमेरिका की वापसी और प्रतिबंध बहाल

- मई 2018 में, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समझौते से अलग रहने का निर्णय लिया।
- अमेरिका ने माना कि यह सौदा ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के खतरे को दूर करने में विफल रहा और इसमें ईरान के परमाणु स्थलों के निरीक्षण और सत्यापन के लिए पर्याप्त मजबूत तंत्र शामिल नहीं था ।
- नवंबर 2018 में , उन्होंने ईरान और इसके साथ व्यापार करने वाले राज्यों दोनों के लिए लक्षित प्रतिबंधों को बहाल कर दिया।
- इसके परिणामस्वरूप ईरान की अर्थव्यवस्था में मंदी आई, इसकी मुद्रा के मूल्य को रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंचा दिया, इसकी वार्षिक मुद्रास्फीति दर को चौगुना कर दिया, विदेशी निवेशकों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों कि उत्पन्न किया।
- यूके, जर्मनी और फ्रांस ने प्रतिबंधों का विरोध किया और एक वैकल्पिक भुगतान तंत्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अमेरिकी दंड का सामना किए बिना ईरान के साथ व्यापार करने में मदद करना था।
- संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध हटाए गए हैं, किन्तु यह भी शर्त रखा गया कि अगर ईरान समझौते के किसी भी पहलू का उल्लंघन करता है, तो उस पर पांच वर्ष के विस्तार की संभावना के साथ, 10 वर्ष के लिए स्वचालित प्रतिबंध प्रभावी हो जाएँगे।

P5+1 और अन्य द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध

- यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान से प्रतिबंध हटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- यद्यपि 1979 से पहले के अमेरिकी प्रतिबंध प्रभावी रहे। ये प्रतिबंध ईरान के आतंकवादी समूहों को समर्थन, मानवाधिकारों के हनन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के कारण लगाए गए थे।

परमाणु अप्रसार संधि, 1970

- यह एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो परमाणु-हथियार वाले राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एक बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।
- यह 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, 1970 में प्रभावी हुआ और मई 1995 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।
- पांच परमाणु-हथियार राज्यों सहित कुल 191 राज्य संधि में शामिल हुए हैं ।
- विदित है कि किसी भी अन्य हथियार सीमा और निरस्त्रीकरण समझौते की तुलना में अधिक देशों ने एनपीटी की पुष्टि की है , जो इस संधि के महत्व को रेखांकित करता है।
- भारत संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

उद्देश्य

- परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना।
- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना।
- परमाणु निरस्त्रीकरण और सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना।

एनपीटी और भारत

- एनपीटी परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग को बढ़ावा देने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है।
- एनपीटी की घोषणा 1970 में हुई थी।
- ध्यातव्य है कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते। यद्यपि, वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के पर्यवेक्षक द्वारा की जाती है।
- इस पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों में भारत, पाकिस्तान और इस्राइल जैसे देश शामिल हैं।
- उत्तर कोरिया इससे पहले ही अलग हो चुका है।
- भारत ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है।
- भारत और इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों का तर्क है कि विकसित देशों ने पहले ही परमाणु हथियारों का भंडार बना लिया है और शेष देशों पर अप्रसार संधि थोप रहे हैं।
- इस मामले में भारत ने फ्रांस का मुद्दा भी उठाया है और कहा है कि वह बिना एनपीटी हस्ताक्षर किए एनएसजी का सदस्य बना था।

ईरान परमाणु समझौते का भारत पर प्रभाव

- जेसीपीओए की बहाली ईरानी शासन पर कई प्रतिबंधों को कम कर सकती है, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के लिए हितकर सिद्ध होगा।
- ईरान पर प्रतिबंधों को समाप्त करने से चाबहार बंदरगाह, बंदर अब्बास बंदरगाह और क्षेत्रीय संपर्क के लिए अन्य योजनाएं में भारत के हित को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- इससे भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीनी उपस्थिति को निष्प्रभावी करने में सहायता मिलेगी।
- चाबहार के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे में भारत की रुचि है, जिसमे ईरान महत्वपूर्ण पक्ष है, जो भारत का पांच मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करेगा

स्रोत; द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

क्वांटम कंप्यूटिंग: उपयोगिता और चुनौतियां

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रसंग

- 21वीं सदी का युग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का युग होगा, जो मनुष्य को अब तक के असंभव कार्यों को भी पूर्ण करने में सक्षम बनाएगा।
- इन गेम चेंजिंग तकनीकों में, क्वांटम कंप्यूटिंग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। विदित है कि क्वांटम कंप्यूटिंग भौतिकी और इंजीनियरिंग का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो क्वांटम भौतिकी (उप-परमाणु कणों की भौतिकी) के सिद्धांतों पर आधारित है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

क्वान्टम कम्प्यूटिंग

- क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित कंप्यूटिंग का एक क्षेत्र है, जो परमाणु और उप-परमाणु स्तरों पर ऊर्जा और सामग्री के व्यवहार की व्याख्या करता है।
- यह कंप्यूटिंग का एक रूप है, जो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित प्रौद्योगिकी को नियोजित करता है।
- यह क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करता है।
- क्वांटम सिद्धांत परमाणु और उप-परमाणु स्तरों पर ऊर्जा और सामग्री के व्यवहार की व्याख्या करता है।
- यह उप-परमाण्विक कृदंतों (subatomic participles) की अद्वितीय क्षमता का उपयोग करता है, जो उन्हें एक ही समय में एक से अधिक राज्यों अर्थात 1 और 0 में मौजूद रहने की अनुमति देता है।

क्वांटम कंप्यूटिंग का अवलोकन

- क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम भौतिकी की दो विशेषताओं पर आधारित है: सुपरपोजिशन और उलझाव।
- सुपरपोजिशन का अर्थ है एक ही समय में कई राज्यों में मौजूद क्वांटम सिस्टम की क्षमता।
- दूसरी ओर, उलझाव एक जोड़ी (क्यूबिट्स) के दो सदस्यों की एक क्वांटम अवस्था में मौजूद रहने की क्षमता है।
- ये दोनों विशेषताएं क्वांटम कंप्यूटरों को कम मात्रा में ऊर्जा की खपत करते हुए पारंपरिक कंप्यूटरों की सीमा से परे संचालन को संभालने की अनुमति देती है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब यह पता चला कि कुछ कम्प्यूटेशनल समस्याओं को उनके शास्त्रीय समकक्षों के विपरीत क्वांटम एल्गोरिदम की मदद से कुशलता से हल किया जा सकता है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग से वित्त, सैन्य, खुफिया, दवा डिजाइन, खोज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल निर्माण के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी।

क्वांटम कम्प्यूटिंग और पारंपरिक कम्प्यूटिंग के मध्य अंतर

- क्वांटम कंप्यूटर सूचनाओं को अलग तरह से संसाधित करने में सक्षम हैं। जबकि शास्त्रीय कंप्यूटर अलग-अलग समय पर केवल 1 या 0 के रूप में डेटा संसाधित कर सकते हैं। विदित है कि क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में 1 या 0 को संसाधित कर सकते हैं। इसे क्यूबिट्स के नाम से जाना जाता है। जब क्यूबिट्स को आपस में जोड़ा जाता है, तो इससे क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता बहुत बढ़ जाती है।
- परंपरागत कंप्यूटर रोज़मर्रा के ऐसे कार्यों को पूरा करने में अच्छे होते हैं, जिनमें संसाधित होने के लिए जटिल मात्रा में डेटा शामिल नहीं होता है। क्वांटम कंप्यूटर जटिल सिमुलेशन, रासायनिक या दवा परीक्षण या किसी भी प्रकार के कार्यों को चलाने के लिए बेहतर हैं, जिसमें डेटा के जटिल स्तर को संसाधित करना शामिल है। हालांकि, क्वांटम कंप्यूटर अपेक्षाकृत महंगे होते हैं।
- क्वांटम कंप्यूटिंग कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए नई दवाओं के विकास में मदद कर सकती है या आवश्यक सिमुलेशन के माध्यम से ऐसी दवाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण कर सकते हैं।
- ये रडार को बेहतर बनाने और रासायनिक सेंसर का उपयोग करके पर्यावरण पर नजर रखने में भी मदद करते हैं।

क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है?

- यह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर जॉन प्रेस्किल द्वारा 2012 में प्रस्तावित एक शब्द है।
- यह उस बिंदु का वर्णन करता है, जहां क्वांटम कंप्यूटर वे चीजें कर सकते हैं, जो शास्त्रीय कंप्यूटर नहीं कर सकते।
- शोधकर्ताओं ने एक ऐसा प्रोसेसर विकसित करने का दावा किया है कि एक शास्त्रीय कंप्यूटर को जिस गणना को करने में 10,000 वर्ष का समय लगेगा, उस गणना को यह 200 सेकंड में पूरा करने में सक्षम है।

भारत और क्वांटम कंप्यूटिंग

- सरकार ने बजट 2020-2021 में देश में क्वांटम कंप्यूटिंग से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन (NM-QTA) की घोषणा की थी।
- मिशन दूसरी क्वांटम क्रांति के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी प्रौद्योगिकियों को विकसित करना चाहता है और भारत को अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाना चाहता है।
- NM-QTA मिशन मौलिक विज्ञान, अनुवाद, विकसित प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक गुणों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करेगा।
- मिशन अगली पीढ़ी की कुशल जनशक्ति तैयार करने, अनुवाद संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने और उद्यमिता और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।
- कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन, रसायन विज्ञान, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग और यांत्रिकी में अत्यधिक जटिल समस्याओं के इंजीनियरिंग समाधान के लिए क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत उन अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनमें एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, संख्यात्मक मौसम की भविष्यवाणी, सिमुलेशन, संचार, वित्तीय लेन-देन हासिल करना, साइबर सुरक्षा, उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा शामिल हैं।
- यह भारत को इस उभरते हुए क्षेत्र में स्थान दिलाने में सहायक होगा और इस क्षेत्र के शीर्ष देशों की सूची में खड़ा करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन (NM-QTA) और इसकी आवश्यकता

- क्वांटम प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-2021 में देश में क्वांटम कंप्यूटिंग से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन (NM-QTA) की शुरुआत की गई थी।
- यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत कार्य करेगा।
- यह समाज की लगातार बढ़ती तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखने में सक्षम होगा।
- मिशन अगली पीढ़ी की कुशल जनशक्ति तैयार करने, अनुवाद संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने और उद्यमिता और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।
- विकास के साथ कंप्यूटिंग, संचार, साइबर-सुरक्षा और एन्क्रिप्शन (encryption) क्षेत्र में अभिनव मार्ग प्रशस्त होगा। इस दिशा में आकलन व्यक्त किया जा रहा है कि इस अनुमानित क्षेत्र के विकास से बहुत सारे व्यावसायिक अनुप्रयोग सामने आएंगे।
- आर्थिक विकास और वैश्विक पटल पर प्रमुख नेतृत्व की भूमिका में अत्यधिक लाभ की संभावना है।

हाल के अनुप्रयोग

- हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) तकनीक का उपयोग करके अपनी दो प्रयोगशालाओं के बीच संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।
- जून 2020 में, चीन ने लगभग 1,120 किमी दूर दो ग्राउंड स्टेशनों के बीच एक गुप्त सम्मेलन आयोजित करके, उपग्रह माइकियस का उपयोग करके क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया।

- उन्होंने उपग्रह का उपयोग पूरे संचार को प्रसारित करने के लिए नहीं किया, बल्कि एक साथ दो ग्राउंड स्टेशनों पर गुप्त चाबियों की एक जोड़ी भेजने के लिए किया।
- अन्य संभावित अनुप्रयोगों में सुरक्षित संचार, तेज़ कंप्यूटर जो क्वांटम वर्चस्व स्थापित करते हैं, सेंसर और क्वांटम-प्रेरित डिवाइस शामिल हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए संभावित अनुप्रयोग

मशीन लर्निंग

- मशीन लर्निंग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्वांटम कंप्यूटिंग से मशीन लर्निंग तकनीक और इसकी सटीकता बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं।

कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान

- पदार्थ विज्ञान में क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग होने वाली क्वांटम यांत्रिक प्रक्रियाओं को अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है। संभावित अनुप्रयोगों में शामिल हैं: नई सामग्री ढूँढना, जो कमरे के तापमान के सुपरकंडक्टर को प्राप्त कर सके या एक उत्प्रेरक ढूँढना, जो कार्बन पृथक्करण की दक्षता में सुधार कर सके, एक नई बैटरी रसायन का विकास करना, जो आज की लिथियम-आयन बैटरी के प्रदर्शन में उल्लेखनीय रूप से सुधार कर सकती है।

वित्तीय पोर्टफोलियो अनुकूलन

- अनुमानित रिटर्न, जोखिम मूल्यांकन और अन्य कारकों के आधार पर एक टोकरी में निवेश के लिए इष्टतम मिश्रण ढूँढना वित्त उद्योग के भीतर एक दैनिक कार्य है।
- ज्ञातव्य है कि इन गणनाओं को करने के लिए क्वांटम तकनीक का उपयोग करके, समाधान की गुणवत्ता के साथ-साथ उन्हें विकसित करने के समय दोनों में सुधार प्राप्त किया जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स और शेड्यूलिंग:

- उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कई सामान्य अनुकूलन को लॉजिस्टिक्स और शेड्यूलिंग के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग रसद को और अधिक कुशल बना सकती है। उदाहरण के लिए: एयरलाइंस यह पता लगा सकती है कि सबसे कम कीमत पर सबसे अच्छी सेवा के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। कारखाना प्रबंधक लागत, समय को कम कर सकता है और उत्पादन को अधिकतम कर सकता है।

दवा क्षेत्र

- विदित है कि विकसित की जा रही कई दवाएं अभी भी परीक्षण और त्रुटियों के कारण महंगी हो जाती हैं।
- क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग से इस क्षेत्र में समय और धन की बचत होगी।

साइबर सुरक्षा:

- साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए क्वांटम मशीन लर्निंग दृष्टिकोणों का उपयोग करके विभिन्न तकनीकों को विकसित किया जा सकता है। जिससे इससे जुड़े खतरों का अधिक सटीक तरीके से पूर्वानुमान किया जा सकेगा और उनके द्वारा किए जाने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

- यद्यपि, उपरोक्त अनुप्रयोग अभी प्रारंभिक चरण में हैं।
- समय के साथ प्रत्येक अनुप्रयोगों की क्षमता का विस्तार करते हुए अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा।
- फलतः क्वांटम कम्प्यूटिंग विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है और इससे समय और लागत में कटौती की जा सकेगी।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

व्यापक विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधि निषेध) संशोधन विधेयक 2022

संदर्भ

- संसद ने व्यापक विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधि निषेध) संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया है।
- विदित है कि यह संशोधन विधेयक विदेश मंत्री एस.जयशंकर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे राज्यसभा में ध्वनिमत के साथ पारित किया गया।

पृष्ठभूमि

- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 को 5 अप्रैल, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।
- यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम 2005 में संशोधन करता है।
- ज्ञातव्य है कि 2005 का अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों (जैसे निर्माण, परिवहन, या हस्तांतरण) को प्रतिबंधित करता है।

व्यापक विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधि निषेध) संशोधन विधेयक 2022

- सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ केंद्र को आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, जब्त करने या संलग्न करने का अधिकार प्रदान करता है।
- विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्तपोषण पर रोकथाम लगाता है।
- व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण से रोकने के लिए, केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों (स्वामित्व, धारित या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित) को फ्रीज, जब्त या संलग्न कर सकती है। यह व्यक्तियों को किसी भी निषिद्ध गतिविधि के संबंध में अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी रोक लगा सकता है।
- उक्त अधिनियम में जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों को शामिल किया गया है और सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के संबंध में सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण रखने और रोकथाम के लिए एकीकृत कानूनी उपायों का प्रावधान है।

आवश्यकता

- केंद्र सरकार ने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा उनकी वितरण प्रणाली से संबंधित नियमों के विस्तार को संदर्भित करते हुए इसे प्रस्तुत किया।
- इसके अलावा, केंद्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की सिफारिशों का भी संज्ञान लिया।
- संशोधन विधेयक मौजूदा कानून में एक नई धारा 12ए को सम्मिलित करने का प्रयास करता है जिसमें उल्लिखित है कि "कोई भी व्यक्ति किसी भी गतिविधि को वित्तपोषित नहीं करेगा, जो इस अधिनियम के तहत या संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निषिद्ध है।

सामूहिक विनाश के हथियार

- "सामूहिक विनाश के हथियार" (WMD) शब्द का पहली बार उपयोग 1937 में चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेता, कैंटरबरी के आर्कबिशप ने जर्मन और इतालवी फासीवादियों द्वारा ग्वेर्निका में बम विस्फोटों का वर्णन करने के लिए किया था।
- एनबीसी हथियारों पर रोक लगाने के लिए दशकों से कई वैश्विक समझौतों और संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें जिनेवा प्रोटोकॉल, 1925 शामिल है, जिसने जैविक हथियार सम्मेलन, 1972 और रासायनिक हथियार सम्मेलन, 1992 के अंतर्गत रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

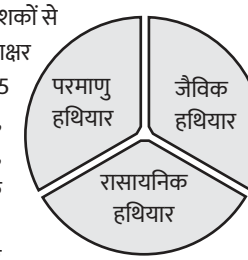

सामूहिक विनाश के 3 शस्त्र

- भारत ने 1972 और 1992 दोनों संधियों पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है।
- डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 4 (p) सामूहिक विनाश के हथियार को परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों को शामिल करने वाले हथियारों के एक वर्ग को दिए गए एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित करती है। सामान्य शब्दों में, डब्ल्यूएमडी को उन हथियारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो बेहद खतरनाक होते हैं और जिनमें आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म करने की क्षमता होती है।
- डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 4 (h) के अनुसार, परमाणु हथियार या उपकरण वे हैं, जिन्हें परमाणु क्षमता वाले और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि, सामान्य तौर पर, ये मशीनरी और हथियार विस्फोट की सुविधा के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं।
- भारत का 2005 का डब्ल्यूएमडी अधिनियम "रासायनिक हथियारों" को "विषाक्त रसायनों और उनके अग्रदूतों" के रूप में परिभाषित करता है, सिवाय इसके कि जहां शांतिपूर्ण, सुरक्षात्मक और कुछ निर्दिष्ट सैन्य और कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

सामूहिक विनाश के सबसे अधिक हथियार रखने वाले देश

- सोवियत संघ ने 1945 से 1949 तक चार वर्षों के लिए पहली और एकमात्र परमाणु शक्ति का उत्पादन किया था।
- रूस के पास दुनिया में सामूहिक विनाश के सबसे अधिक हथियार हैं।
- रूस के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके पास परमाणु हथियारों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022

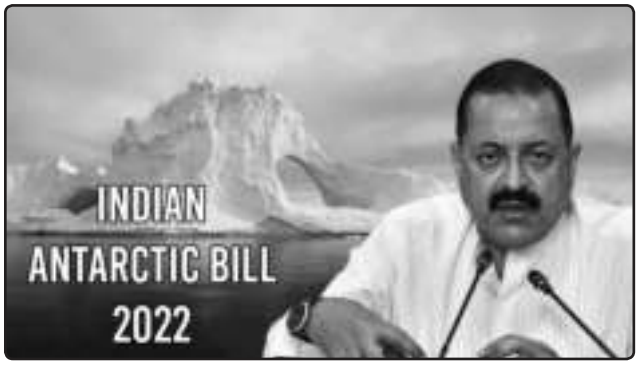

संदर्भ

- संसद ने अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्रों पर राष्ट्रीय स्तर पर उपाय करने की मंशा से भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को पारित किया।
- विदित है कि उच्च सदन में संचालित भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा ने 22 जुलाई को विधेयक को स्वीकृति प्रदान की थी।

उद्देश्य

- अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्रों पर राष्ट्रीय स्तर पर उपाय करना।
- इसका प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र को खनन या अवैध गतिविधियों से छुटकारा दिलाने के साथ-साथ इसका असैन्यीकरण सुनिश्चित करना है।
- इसका उद्देश्य यह भी है कि इस क्षेत्र में कोई परमाणु परीक्षण/विस्फोट नहीं होना चाहिए।'

आवश्यकता और महत्व

- इस विधेयक में सुस्थापित कानूनी व्यवस्था के जरिए भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण नीति और नियामकीय फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है और इससे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के व्यवस्थित एवं वैकल्पिक या ऐच्छिक संचालन में मदद मिलेगी।
- यह विधेयक बढ़ते अंटार्कटिक पर्यटन के समुचित प्रबंधन और अंटार्कटिक महासागर में मत्स्य संसाधनों के सतत विकास में भारत की रुचि एवं सक्रिय भागीदारी को भी सुविधाजनक बनाएगा।
- इससे ध्रुवीय क्षेत्र के प्रशासन में भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जिससे वैज्ञानिक और रसद क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन एवं सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।
- अंटार्कटिक अध्ययन और संवेदनशील अंटार्कटिक परिवेश के संरक्षण के लिए समवर्ती प्रतिबद्धता के साथ अंटार्कटिक स्थित अनुसंधान केंद्रों में भारतीय वैज्ञानिकों की निरंतर और बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए अंटार्कटिक संधि प्रणाली के एक सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के अनुरूप अंटार्कटिक पर घरेलू कानून को अपनाना आवश्यक हो गया है।
- इस तरह के कानूनों को लागू करने से अंटार्कटिक के कुछ हिस्सों में किए गए किसी भी विवाद या अपराधों से निपटने के लिए भारत की अदालतों को क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाएगा।
- इस तरह का कानून नागरिकों को अंटार्कटिक संधि प्रणाली की नीतियों से जोड़ देगा।
- यह विश्व स्तर पर विश्वसनीयता कायम करने के साथ-साथ देश की साख बढ़ाने में भी काफी उपयोगी होगा।

भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण (आईएए)

- इस विधेयक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण (आईएए) की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है, जो निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होगा और यह इस विधेयक के तहत अनुमत प्राप्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा।
- यह अंटार्कटिक अनुसंधान और अभियानों के प्रायोजन और पर्यवेक्षण के लिए एक स्थिर, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया प्रदान करेगा, अंटार्कटिक में पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करेगा और अंटार्कटिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में संलग्न भारतीय नागरिकों द्वारा संबंधित नियमों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव आईएए के अध्यक्ष होंगे और आईएए में भारत के संबंधित मंत्रालयों के आधिकारिक सदस्य होंगे और निर्णय आम सहमति से लिए जाएंगे।

अंटार्कटिका में भारत के परिचालन अनुसंधान केंद्र और वैज्ञानिक अभियान का संचालन

- वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 'मैत्री' (वर्ष 1989 में चालू) और 'भारती' (वर्ष 2012 में चालू) नामक दो परिचालन अनुसंधान केंद्र हैं।
- भारत ने अब तक अंटार्कटिका में 40 वार्षिक वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किए हैं।
- एनवाई-एलेसंड, स्वालबार्ड, आर्कटिक में हिमाद्री केंद्र के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके कई शोध केंद्र ध्रुवीय क्षेत्रों के भीतर हैं।

अंटार्कटिक संधि क्या है?

- अंटार्कटिक संधि पर 01 दिसंबर, 1959 को 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे:

1.	अर्जेंटीना	2.	ऑस्ट्रेलिया	3.	बेल्जियम
4.	चिली	5.	फ्रांस	6.	जापान
7.	न्यूजीलैंड	8.	नॉर्वे	9.	दक्षिण अफ्रीका
10.	यूएसएसआर	11.	यूके	12.	यूएस

- उनका उद्देश्य अंटार्कटिका का विसैन्यीकरण करना, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय संप्रभुता विवादों को अलग करना था।
- बाद के वर्षों में, अन्य देश अंटार्कटिक संधि में शामिल हुए।
- वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं, जिनमें से 29 देशों को वार्षिक आयोजित अंटार्कटिक सलाहकार बैठकों में सलाहकार (मतदान) का दर्जा प्राप्त है और 25 देशों के पास गैर-परामर्शी सदस्यता है।
- भारत 19 अगस्त 1983 को अंटार्कटिक संधि का सदस्य बना और उसी वर्ष 12 सितंबर को इसे सलाहकार का दर्जा प्राप्त हुआ।
- अंटार्कटिक संधि के बाद, सदस्य देशों ने 1980 में कैनबरा में 'अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन' पर हस्ताक्षर किए, जिसकी भारत ने 1985 में पुष्टि की।
- देशों ने 1991 में अंटार्कटिक संधि (मैड्रिड प्रोटोकॉल) के लिए 'पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल' पर भी हस्ताक्षर किए, जो महाद्वीप को 'एक प्राकृतिक रिजर्व, शांति और विज्ञान के लिए समर्पित' के रूप में नामित करता है।

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक

- विधेयक कानूनी तंत्र के माध्यम से भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करता है, जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के कुशल संचालन में मदद करेगा।

- यह अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों और विवादों से निपटने के लिए भारतीय अदालतों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।
- बिल की योजना अंटार्कटिक में पर्यटन के प्रबंधन और मत्स्य पालन के सतत विकास में भारत की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने की है।
- इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन और रसद में सहयोग के लिए ध्रुवीय शासन में भारत की अंतरराष्ट्रीय दृश्यता और विश्वसनीयता को बढ़ाना भी है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के रूप में भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण (IAA) स्थापित करने की योजना है।
- आईएए अंटार्कटिक पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करेगा, और अंटार्कटिक कार्यक्रमों और गतिविधियों में लगे भारतीय नागरिकों द्वारा प्रासंगिक नियमों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।
- बिल अंटार्कटिक महाद्वीप को दूषित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाता है, जिसमें परमाणु विस्फोट और रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान, समुद्र में प्लास्टिक, कचरा और अन्य पदार्थ का निर्वहन शामिल है।

मंकीपॉक्स पर वीके पॉल टास्कफोर्स का गठन

संदर्भ

- भारत में मंकीपॉक्स के मामलों पर नजर रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
- विदित है कि यह कार्यबल देश में संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच केंद्रों में विस्तार को लेकर सरकार का मार्गदर्शन करेगा और इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण संबंधी पहलुओं पर नजर रखेगा।

पृष्ठभूमि

- हाल में संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटे 22 वर्षीय पुरुष की कथित रूप से मंकीपॉक्स के कारण मृत्यु हो गई।
- भारत में अब तक इस संक्रमण के चार मामले सामने आए हैं।
- टास्क फोर्स के गठन का निर्णय देश में चल रही जनस्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए 26 जुलाई को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था।
- नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल इस कार्यबल का नेतृत्व करेंगे।
- विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल में मंकीपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।
- वैश्विक स्तर पर, 75 देशों में मंकीपॉक्स के 16,000 से अधिक मामले पाए गए हैं।

मंकीपॉक्स

- मंकीपॉक्स एक ऑर्थोपॉक्सवायरस संक्रमण दुर्लभ बीमारी है, जो कि चेचक या चिकनपॉक्स के सामान दिखाई देती है।
- यह बीमारी सबसे पहले वर्ष 1958 में बंदरों में दिखाई दी थी, जिसके कारण इसे मंकीपॉक्स नाम दिया गया।
- पहला मानव मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में चेचक को खत्म करने के तीव्र प्रयास की अवधि के दौरान दर्ज किया गया था।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, चार महाद्वीपों के 15 देशों ने अब तक मनुष्यों में मंकीपॉक्स के मामलों की पुष्टि की है।
- मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य, गैबॉन, कैमरून, नाइजीरिया, कोटे डी आइवर, लाइबेरिया और सिएरा लियोन में स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामलों की पुष्टि की गई है।
- अफ्रीका में दक्षिण सूडान और बेनिन और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, इज़राइल और सिंगापुर में आयातित मामले पाए गए हैं।

मंकीपॉक्स चेचक से किस प्रकार भिन्न है?

- मंकीपॉक्स का संबंध ऑर्थोपॉक्सवायरस परिवार से है, जो चेचक की तरह दिखाई देती है। इसमें वैरियोला वायरस भी शामिल है। इस वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स अर्थात छोटी चेचक होती है।
- मंकीपॉक्स चेचक के समान लक्षणों का कारण बनता है, हालांकि वे कम गंभीर होते हैं।
- साथ ही दोनों बीमारियों के लक्षण भी अलग-अलग होते हैं।
- मंकीपॉक्स से पीड़ित जानवर या व्यक्ति के शरीर से निकले संक्रमित फ्लूइड के संपर्क में आने, संक्रमित जानवर के काटने, छूने आदि कारणों से मंकीपॉक्स फैलता है। विशेषकर, चूहों, गिलहरियों और बंदरों द्वारा यह अधिक फैलता है।
- यद्यपि, चेचक का टीका मंकीपॉक्स के खिलाफ काम करता है और लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- 1977 में भारत में चेचक का उन्मूलन किया गया था।

एक जिला-एक उत्पाद

संदर्भ

- हाल ही में ओडीओपी उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया गया।
- विदित है कि यह अनावरण 5 अगस्त, 2022 को वाणिज्य भवन में निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के साथ बैठक के दौरान किया गया।

ओडीओपी उपहार सूची में शामिल उत्पाद

- ओडीओपी उपहार सूची में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे सुगंधित पदार्थ और तेल, भारतीय स्प्रिट, घर सजाने के उत्पाद, कपड़े और रेशम एवं शॉल आदि शामिल हैं।

महत्व

- एचसीआईएम ने उन तरीकों पर प्रकाश डाला, जिसमें ओडीओपी उपहार सूची भारत के सभी जिलों की क्षमता को सामने लाने की दिशा में एक कदम के रूप में शामिल है।
- यह देश के विविध स्वदेशी उत्पादों को दुनिया भर में मान्यता प्रदान करेगा।
- इससे जुड़े सभी मंत्रालयों, उद्योग संघों और निर्यात संवर्धन परिषदों से डिजाइन और ब्रांडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए सूची से उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया गया।
- यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और किसानों और कारीगरों के भरण पोषण और आजीविका को बढ़ाने में मदद करेगा।
- इस सूची से अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थानीय उत्पादों के प्रचार को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप "मेक इन इंडिया" और "मेक फॉर वर्ल्ड" के दृष्टिकोण को गति मिलेगी।

एक जिला-एक उत्पाद

- वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) एक पहल है, जिसे जिले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में संदर्भित किया जाता है ।

- विदित है कि ओडीओपी पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
- इसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले (एक जिला - एक उत्पाद) से एक उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग और प्रचार पर बल दिया जाता है।
- देश के सभी 761 जिलों से ओडीओपी के तहत चुने गए उत्पादों की श्रंखला कई क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों तक विस्तृत है।

कार्यान्वयन

- ओडीओपी पहल को डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- 'डिस्ट्रिक्ट्स एज़ एक्सपोर्ट हब ' पहल के साथ एक प्रमुख हितधारक के रूप में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ मिला दिया गया है।
- वाणिज्य विभाग डीजीएफटी के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद की पहल को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ संबद्ध हो रहा है।

उद्देश्य

- जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके देश के प्रत्येक जिले को निर्यात हब में परिवर्तित करना ।
- इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, विनिर्माण को बढ़ाने के लिए स्थानीय निर्यातकों / निर्माताओं का समर्थन करना।
- निर्यात को बढ़ावा देने, जिले में विनिर्माण और सेवा उद्योग को बढ़ावा देने और जिले में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से भारत के बाहर संभावित खरीदारों की खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका में कार्य कर रहा है।

परवाज योजना

संदर्भ

- अभिनव बाजार लिंकेज स्कीम- परवाज केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।
- विदित है कि प्रदेश सरकार ने स्थानीय कृषकों और बागवानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए परवाज योजना को गत वर्ष स्वीकृति प्रदान की थी।
- यह योजना सरकार द्वारा एयर कार्गो के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में काटे जा रहे कृषि और बागवानी के लिए बाजार लिंकेज समर्थन बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में काटे गए फलों को एयर कार्गो के माध्यम से शिपमेंट के लिए ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।
- ज्ञातव्य है कि किसानों को सब्सिडी डीबीटी मोड के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (जेकेएचपीएमसी), योजना की कार्यान्वयन एजेंसी नियमित रूप से इस योजना के महत्व के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा कर रही है, ताकि उनमें से पर्याप्त संख्या में इसका लाभ उठा सकें।
- इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में पैदा होने वाले कृषि व बागवानी उत्पाद विशेषकर जो ज्यादा समय तक संरक्षित नहीं किए जा सकते, एयरकार्गो के जरिए देश-विदेश की मंडियों में पहुंचाने में किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें मुख्यत: जैविक फल सब्जियां ही शामिल हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम

संदर्भ

- हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने 2014-2022 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी से संबंधित 515 धन शोधन मामलों में लगभग 47,099 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- विदित है कि उपरोक्त 515 मामलों में से 137 मामले बैंक धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिसमें प्रत्येक मामले में शामिल राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है।
- ऋण भगोड़ों के कुछ मामलों में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 29 जुलाई, 2022 तक 19,312 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की है।
- यह आंकड़ा इन मामलों में 22,586 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की राशि का 85.5% है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, सार्वजनिक और निजी बैंकों ने 2014-15 से 2021-22 तक गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) खातों में 8,39,452 करोड़ रुपये की वसूली की, जिसमें धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किए गए खाते भी शामिल हैं।

मामले से संबद्ध उच्चतम न्यायालय का हाल का निर्णय

- उच्चतम न्यायालय के जस्टिन एएम खानविलकर, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने जुलाई 2022 को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention Of Money Laundering Act) को लेकर एक अहम निर्णय सुनाया है।
- न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को पीएमएलए के तहत मिले अधिकारों को उचित ठहराया। शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में उल्लिखित किया कि पीएमएलए कानून में किए गए परिवर्तन उचित है और ईडी की गिरफ्तारी करने की शक्ति भी सही है।
- शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में पीएमएलए कानून के तहत अपराध से अर्जित की गई संपत्ति, उसकी तलाशी और जब्ती, आरोपी की गिरफ्तारी की शक्ति जैसे पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को सही ठहराया है।
- ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं।

धन शोधन

- धन शोधन से आशय गैर-कानूनी तरीकों से अर्जित धन को वैद्य तरीके से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए धन को छिपाने का एक तरीका है।
- विदित है कि इस प्रकार के गैर-कानूनी धन की हेरा-फेरी करने वाले व्यक्ति को लाउन्डर कहा जाता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम

- पीएमएलए 2002 में अधिनियमित किया गया था और यह 2005 में प्रभावी हुआ था।
- इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया से लड़ना है।
- यह अधिनियम सरकारी अधिकारियों को अवैध स्रोतों से और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अर्जित संपत्ति और/या संपत्ति को जब्त करने में सक्षम बनाता है।
- पीएमएलए के तहत, सबूत का भार आरोपी पर होता है, जिसे यह साबित करना होता है कि संदिग्ध संपत्ति / संपत्ति अपराध की आय के माध्यम से प्राप्त नहीं की गई है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय की है।

पीएमएलए के उद्देश्य

- मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना।
- धन को अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में लगाने से रोकना।
- मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती के लिए प्रदान करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग के कार्य से संबंधित या प्रासंगिक किसी अन्य मामले के लिए प्रदान करना।

पीएलएमए के तहत अपराध की श्रेणी

- भाग ए में अधिनियमों के तहत अपराध शामिल हैं: भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम , कॉपीराइट अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम।
- भाग बी में ऐसे अपराध शामिल हैं, जिनका उल्लेख भाग ए में किया गया है, लेकिन जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।
- भाग सी में सीमा पार अपराध शामिल हैं।

पीएमएलए के तहत दंड का प्रावधान

- मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए गए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है।
- इसके अंतर्गत अपराध के माध्यम से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाता है।
- इसके तहत कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा का प्रवाधान है, जिसे 7 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है।
- वहीं, अगर इसके साथ-साथ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 से जुड़े अपराध भी शामिल हैं तो जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय

- प्रवर्तन निदेशालय 1 मई, 1956 को अस्तित्व में आई।
- ध्यातव्य है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के प्रभावी निदान के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था।
- वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया।
- वर्तमान में, यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का हिस्सा है।
- इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022

संदर्भ

- लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया है।
- विदित है कि यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करेगा।

उद्देश्य

- अधिनियम ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- यह उपकरण, भवन और उद्योगों द्वारा ऊर्जा खपत के नियमन का प्रावधान करता है।

विधेयक के तहत प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं

ऊर्जा के गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग की बाध्यता

- 2001 का अधिनियम केंद्र सरकार को ऊर्जा खपत मानकों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- बिल में कहा गया है कि सरकार को नामित उपभोक्ताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा खपत के न्यूनतम हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है ।
- नामित उपभोक्ताओं में शामिल हैं:
  - खनन, इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, रसायन और पेट्रोकेमिकल जैसे उद्योग,
  - रेलवे सहित परिवहन क्षेत्र, और
  - वाणिज्यिक भवन, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है।
- गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उपयोग के दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

कार्बन ट्रेडिंग

- बिल केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- कार्बन क्रेडिट का तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन की एक निर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन करने के लिए एक व्यापार योग्य परमिट है।
- केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी योजना के तहत पंजीकृत और अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।
- संस्थाएं प्रमाणपत्र खरीदने या बेचने की हकदार होंगी।

इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड

- 2001 का अधिनियम केंद्र सरकार को भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- कोड क्षेत्र के संदर्भ में ऊर्जा खपत मानकों को निर्धारित करता है।
- बिल 'ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ बिल्डिंग कोड' प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है ।
- यह नया कोड ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और हरित भवनों के लिए अन्य आवश्यकताओं के मानदंड प्रदान करेगा।

आवासीय भवनों के लिए प्रयोज्यता

- 2001 के अधिनियम के तहत, ऊर्जा संरक्षण कोड वाणिज्यिक भवनों पर लागू होता है।

- 100 किलो वाट (किलोवाट) का न्यूनतम कनेक्टेड लोड या 120 किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) का अनुबंध भार होना।
- विधेयक के तहत, उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले कार्यालय और आवासीय भवनों पर भी नया ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन कोड लागू होगा।
- बिल राज्य सरकारों को लोड थ्रेसहोल्ड को कम करने का भी अधिकार देता है।

वाहनों और जहाजों के लिए मानक

- 2001 के अधिनियम के तहत ऊर्जा खपत मानकों को उन उपकरणों और उपकरणों के लिए निर्दिष्ट किया गया है, जो ऊर्जा का उपभोग, उत्पादन, संचार या आपूर्ति करते हैं।
- विधेयक वाहनों और जहाजों (जहाजों और नौकाओं सहित) को शामिल करने के दायरे का विस्तार करता है।
- ईंधन की खपत के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहन निर्माताओं को बेचे जाने वाले वाहनों की प्रति यूनिट 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

SERCs की नियामक शक्तियाँ

- 2001 का अधिनियम राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) को अधिनियम के तहत दंड का निर्णय करने का अधिकार देता है।
- विधेयक में कहा गया है कि एसईआरसी अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम भी बना सकते हैं ।

बीईई गवर्निंग काउंसिल की संरचना

- 2001 के अधिनियम के तहत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की शासी परिषद में सदस्यों की संख्या 20 से 26 के बीच है।
- विधेयक में यह प्रावधान है कि सदस्यों की संख्या 31 से 37 के बीच होगी।
- यह उद्योगों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम सात सदस्यों को भी प्रदान करता है।

वज्र प्रहार 2022

- हाल ही में भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण का अभ्यास "वज्र प्रहार, 2022" स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल (एसएफटीएस), बकलोह (हिमाचल प्रदेश) में शुरू हुआ।

अभ्यास वज्र प्रहार का 12वां संस्करण

- इस अभ्यास का 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लेविस मैकॉर्ड, वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था।
- विदित है कि भारत और अमेरिकी नौसेना के संयुक्त निर्देशन में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में दो दिवसीय 'पैसेज सैन्य अभ्यास' का आयोजन किया गया था।

अभ्यास संबद्ध जानकारियां

- इस अभ्यास के अलावा, भारत-अमेरिकी सेना अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्र में आयोजित होने वाला है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के मध्य क्षेत्र में आता है।
- अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व 1 विशेष बल समूह (एसएफजी) और अमेरिकी विशेष बलों के विशेष रणनीति स्क्वाड्रन (एसटीएस) के कर्मियों द्वारा किया जाता है और भारतीय सेना दल का गठन एसएफटीएस के तत्वावधान में विशेष बल कर्मियों द्वारा किया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि अगले 21 दिनों के दौरान, दोनों सेनाओं की टीमें संयुक्त रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में सिम्युलेटेड पारंपरिक और अपरंपरागत परिदृश्यों में विशेष ऑपरेशन, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, एयर बोर्न ऑपरेशन की एक श्रृंखला को प्रशिक्षित, योजना और निष्पादित करेंगी।

उद्देश्य

- संयुक्त अभ्यास की वज्र प्रहार श्रृंखला का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना और दोनों राष्ट्रों के विशेष बलों के बीच अंतर-संचालन में सुधार करना है।

अभ्यास वज्र प्रहार

- यह भारत और अमेरिका के विशेष बलों के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है।
- वज्र प्रहार का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना और एक-दूसरे की सेनाओं के अनुभवों के समृद्ध भंडार को भुनाना है।
- यह दोनों बलों के मध्य अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाने में सहयोगी है।
- यह दोनों बलों के बीच परस्पर रणनीति का आदान-प्रदान करता है।
- दोनों सेनाओं के मध्य सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं को साझा करने में सहायक है।
- इसके अतिरिक्त संयुक्त रणनीति विकसित करने के साथ आतंकवाद विरोधी वातावरण में संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विदित है कि यह अभ्यास दोनों देशों के मध्य वार्षिक आधार पर क्रमश: आयोजित की जाती है।
- भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2010 में शुरू हुआ था
- 2012 से 2015 के बीच और वर्ष 2020 में वज्र प्रहार का आयोजन नहीं किया गया।

भारत छोड़ो आंदोलन

- उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उल्लिखित किया कि यह आंदोलन समृद्ध, समावेशी, शांतिपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण भारत के निर्माण का संकल्प लेने का अवसर है।
- विदित है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस निर्णायक आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त, 1942 को हुई थी।

भारत छोड़ो आंदोलन

- भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है।
- यह आधिकारिक तौर पर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) द्वारा शुरू किया गया था।
- आंदोलन में 'भारत छोड़ो' और 'करो या मरो' का नारा दिया गया।
- कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप, इसे एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन माना जाता था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का आग्रह करना था।

- 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी को आंदोलन के नेता के रूप में नामित किया गया था।

भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प

- भारत पर ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत।
- सभी प्रकार के साम्राज्यवाद और फासीवाद से अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा।
- ब्रिटिश वापसी के बाद भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन।
- ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकृति।

भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व

- सरकार द्वारा भारी दमन के बावजूद लोग अचंभित थे और अपना संघर्ष जारी रखा।
- भले ही सरकार ने कहा कि स्वतंत्रता युद्ध की समाप्ति के बाद ही दी जा सकती है, इस आंदोलन ने इस बात को रेखांकित किया कि भारतीयों के समर्थन के बिना भारत पर शासन नहीं किया जा सकता है।
- आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वतंत्रता आंदोलन के शीर्ष एजेंडे में रखा।
- जनता का मनोबल और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं में बढ़ोतरी हुई।

स्माइल 75-पहल

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में 'स्माइल-75 पहल' की शुरूआत की गई है।
- विदित है कि "स्माइल-75 इनिशिएटिव" नामक स्माइल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज) के अंतर्गत 75 नगर निगमों की पहचान भिक्षावृत्ति के काम में संलग्न लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास परियोजना को लागू करना है।
- स्माइल-75 पहल के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से 75 नगर निगम भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप से कवर किया जाना है, जिनमें परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुस्कान परियोजना

- यह पहल मंत्रालय के निर्देशन में संचालित मुस्कान परियोजना (आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन) का हिस्सा है, जिसके लिए 2025-2026 तक ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- इस परियोजना के माध्यम से, मंत्रालय भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों का समग्र पुनर्वास करने के लिए एक समर्थन तंत्र विकसित करने और एक ऐसे भारत का निर्माण करने की परिकल्पना करता है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करने और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भीख मांगने के लिए विवश न हो।

स्माइल-75 का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य शहरों/ कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना और विभिन्न हितधारकों के समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निरंतर चले आ रहे इस सामाजिक मुद्दे का समाधान ठोस प्रयासों के माध्यम से करने के लिए स्थानीय शहरी निकायों, नागरिक समाज संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है।

निहितार्थ

- भारत सरकार ने निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या की गंभीरता को समझते हुए स्माइल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज) नामक एक व्यापक योजना तैयार की है।
- विदित है कि इसमें भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक उप-योजना शामिल है जो पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श और शिक्षा, सम्मानित नौकरी तथा स्वरोजगार/ उद्यमिता के लिए कौशल विकास को कवर करती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहल

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रमुख नगर निगमों के साथ मिलकर लॉकडाउन शुरु होने के बाद से (10.04.2020 तक) 1.27 करोड़ से अधिक निराश्रित/भिक्षुक/बेघर लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की है।
- मंत्रालय एक परियोजना के तहत भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के पुनर्वास के लिए पहले से ही एक व्यापक योजना लागू करने हेतु दस (10) शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, नागपुर, पटना और इंदौर का चयन कर चुका है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकारों/ संघशासित प्रदेशों/ स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों आदि के सहयोग से ऐसे लोगों की पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास का प्रावधान शामिल होगा।
- ज्ञातव्य है कि इस योजना के तहत राज्यों / संघशासित प्रदेशों को इसके कार्यान्वयन के लिए 100% सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत में भिक्षावृत्ति

- फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और पांच राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और बिहार) से भीख मांगने से संबंधित एक याचिका पर जवाब मांगा।
- इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 (जनगणना 2011) है और यह संख्या पिछली जनगणना से बढ़ी है।
- विदित है कि याचिका में दावा किया गया है कि भीख मांगने को अपराध के दायरे में लेने का फैसला संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।
- याचिका में अगस्त 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया गया है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिक मामलों की पहचान और जांच के उद्देश्यों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों का माप लेने के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है।
- विदित है कि इस वर्ष की शुरुआत में इससे जुड़ा कानून बनाया गया था, गृह मंत्रालय ने इसे 4 अगस्त, 2022 से लागू होने के लिए अधिसूचित किया था।
- यह कैदियों की मौजूदा पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लेगा।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक क्या है?

- यह विधेयक आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्य से दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप लेने के लिए अधिकृत करने, रिकॉर्ड को संरक्षित करने और उससे संबद्ध प्रासंगिक मामलों को संबोधित करता है।

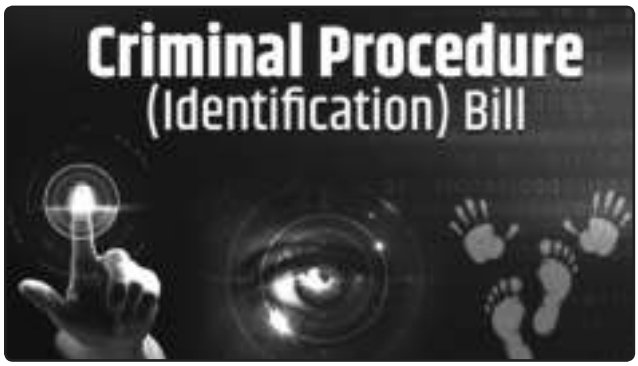

- यह विधेयक अपराधियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पुलिस को उनके अंगों और निशानों की माप लेने का अधिकार प्रदान करता है।
- इसके अंतर्गत उंगली के निशान, पैरों और हथेली के निशान, फोटोग्राफ, रेटिना स्कैन, जैविक नमूने, दस्तखत, लिखावट व आंख की पुतली से जुड़े सबूतों को संरक्षित रखा जाएगा।
- विदित है कि इस विधेयक में पुलिस और जेल अधिकारियों को रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों के एकत्रण, संग्रहण और विश्लेषण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920

- यह विधेयक 102 वर्ष पुराने 'कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920' को निरस्त करने और इसे एक नए कानून के साथ परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता है। यह पुलिस अधिकारियों को पहचान और जांच के उद्देश्यों के लिए दोषियों की "माप" लेने की अनुमति प्रदान करता है।
- विदित है कि पूर्ववर्ती अधिनियम में केवल उंगलियों के निशान और पांव के निशान लेने की अनुमति थी।
- नई प्रौद्योगिकी आने के बाद इसमें संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी।
- संशोधन से जांच एजेंसियों को जरूरी सूचनाएं हासिल होंगी और दोषसिद्धि भी बढ़ेगी।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022- कार्यान्वयन क्षेत्र

- किसी भी कानून के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए लोग।
- यह संहिता की धारा 107, 108, 109 या 110 के तहत कार्यवाही के लिए सीआरपीसी की धारा 117 के तहत अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने का आदेश देता है।
- यह अपराध को रोकने की दृष्टि से "संदिग्ध अपराधियों" या "आदतन अपराधियों" से जुड़े प्रावधान करता है।
- ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी कानून के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार या किसी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम शामिल होगा।
- इसके अतिरिक्त, विधेयक में उल्लिखित है कि किसी महिला या बच्चे के खिलाफ किए गए अपराधों या सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के आरोपियों को छोड़कर, किसी अन्य अपराध का आरोपी व्यक्ति जैविक नमूनों को लेने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक की धारा 2 (1) (बी)

- उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक और जैविक नमूने और उनके विश्लेषण, हस्ताक्षर और लिखावट सहित व्यवहार संबंधी विशेषताओं को शामिल करने के लिए "माप" को परिभाषित करता है।
- यह विधेयक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 53 अथवा धारा 53ए में संदर्भित अन्य परीक्षण को भी विश्लेषित करता है।
- सर्वविदित है कि धारा 53 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा जांच से संबंधित है।

आंकड़ों का एकत्रीकरण

- विधेयक में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) कानून के अंतर्गत किसी भी अपराध के रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के हित में जैविक डेटा एकत्र करेगा।
- एनसीआरबी संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अथवा किसी अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों से माप का रिकॉर्ड एकत्र कर सकता है।
- इसमें राष्ट्रीय स्तर पर माप के रिकॉर्ड को संग्रहीत, संरक्षित और नष्ट करने और ऐसे रिकॉर्ड साझा और प्रसारित करने की शक्ति सन्निहित होगी।
- चूंकि पुलिसिंग राज्य का विषय है, फलतः कोई राज्य इस जानकारी को साझा करने से इनकार कर सकता है। यद्यपि विधेयक पुलिस को तकनीक का प्रभावी उपयोग कर निगरानी करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है।
- डेटा के संग्रह, भंडारण अथवा उपयोग के तौर-तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा।
- माप का रिकॉर्ड डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में तारीख से 75 साल की अवधि के लिए रखा जाएगा।

विधेयक से जुड़े मुद्दे

- विधेयक में कई प्रावधानों को परिभाषित नहीं किया गया है। यह मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून के लिए चिंता बढ़ा सकता है।
- यह "दोषियों और अन्य व्यक्तियों" के लिए माप के संग्रह का प्रावधान करता है, किन्तु "अन्य व्यक्तियों" के अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है।
- विधेयक, जिसमें जैविक जानकारी के संग्रह में बल का प्रयोग निहित है, नार्को विश्लेषण और मस्तिष्क मानचित्रण का कारण बन सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के साथ-साथ के.एस. पुट्टस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है।
- अनुच्छेद 20(3) स्व-अभिसंशन से संरक्षण का प्रविधान करता है, अर्थात इसके अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है।
- इसमें कुछ अपराधों के आरोपियों को शामिल किया गया हैं, यद्यपि यह तर्क दिया जा सकता है कि पुलिस कानून का उपयोग अन्यों तक इसका विस्तार करने के लिए कर सकती है।
- राजनीतिक दलों और आंदोलनकारियों की इस आशंका को भी दूर किया जाना चाहिए कि थाना प्रभारियों और हेड कांस्टेबलों के जरिए कानून का दुरूपयोग नहीं होगा और कोई मामला दर्ज होते ही पुतलियों की छाप और डीएनए की जांच कर उन्हें हमेशा के लिए आशंकित नहीं रखा जाएगा।
- विधेयक कैदियों के अधिकारों और भूल जाने के अधिकार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। विधेयक में बायोमेट्रिक डेटा को 75 वर्षों तक संग्रहीत किए जाने का प्रविधान है।
- भारत में 'भूल जाने का अधिकार' के आसपास का न्यायशास्त्र अभी भी प्रारंभिक चरण में है, पुट्टस्वामी निर्णय इसे निजता के मौलिक अधिकार के एक पहलू के रूप में चर्चा करता है।
- वर्ष 2018 में पुट्टस्वामी II मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को बरकरार रखा और राज्य को कल्याणकारी योजनाओं के लिए उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन एकत्र करने की अनुमति दी थी।
- विधेयक उन लोगों को "अपने अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करने अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 117 के तहत शांति बनाए रखने का आदेश देने के लिए धारा 107 या धारा 108 या धारा 109 या उक्त संहिता की धारा 110 के तहत बॉयोमीट्रिक डेटा साझा करने के लिए विवश करने की अनुमति देता है।

अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)

- सीसीटीएनएस भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है।

- सीसीटीएनएस का उद्देश्य ई-गवर्नेंस के सिद्धांत को अंगीकार करने और आईटी सक्षम अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली विकसित करना है।
- विदित है कि आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 जून 2009 को परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी।

राष्ट्रीय ध्वज

- 'हर घर तिरंगा' भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'आज़ादी के अमृत' महोत्सव के तत्वावधान में संचालित किया गया एक अभियान है।

हर घर तिरंगा

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में 22 जुलाई को इस अभियान की घोषणा की गई थी।
- इस अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 13 से 15 अगस्त तक घरों के ऊपर कम से कम 20 करोड़ झंडे फहराना है।

राष्ट्रीय ध्वज

- मैडम भीकाजी कामा ने अगस्त 1907 में, जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। इसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज नाम दिया गया।
- वर्ष 1917 में एक नया झंडा अपनाया गया। इसमें 5 लाल और 5 हरी आड़ी धारियां और सप्तऋषि के आकार में 7 तारे थे।
- अप्रैल 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखे से एक ध्वज बनवया। इस ध्वज में लाल और हरे रंग के साथ सफेद रंग भी शामिल किया गया। इस ध्वज के सेंटर में चरखा बनाया गया।
- इसके बाद कराची में वर्ष 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में तीन रंगों के एक राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसमें लाल रंग बलिदान, सफेद रंग पवित्रता और हरा रंग आशा का प्रतीक माना गया।
- वर्तमान स्वरूप का तिरंगा 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया।
- हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
- वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में शीर्ष पर केसरिया रंग है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इसके मध्य में सफेद रंग है, जो शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग है, जो भूमि की उर्वरता, और विकास का सूचक है।
- राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान रूप के केंद्र में 24 तीलियों वाला चक्र है। यह जीवन के गति को बताता है।
- नए नियम के तहत अब देश के नागरिकों द्वारा झंडा दिन के साथ रात में भी फहराया जा सकता है। शाम में इसे उतारने की आवश्यकता नहीं है।
- पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी। लेकिन दिसंबर 2021 में इसकी अनुमति दे दी गई।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51ए

- संविधान के भाग IV(A) के अंतर्गत अनुच्छेद 51 A में शामिल 'मौलिक कर्तव्यों' में संविधान का पालन करने और इसके आदर्शों तथा संस्थानों का सम्मान करने, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन विचारों ने प्रेरित किया, उनका सम्मान करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

भारतीय ध्वज संहिता 2002

- 'भारतीय झंडा संहिता 2002', 26 जनवरी 2002 से लागू की गई थी। इसके तहत भारतीय झंडा संहिता को तीन भागों में बांटा गया है।
- पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण शामिल हैं।
- वहीं दूसरे भाग में आम लोगों, शैक्षिक संस्थाओं और निजी संगठनों के लिए झंडा फहराए जाने से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
- संहिता के तीसरे भाग में राज्य और केंद्र सरकार, उनके संगठनों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा संहिता में यह भी उल्लेख किया गया है कि तिरंगे का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।
- ध्वज का उपयोग किसी उत्सव के रूप में या किसी भी तरह के सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यही नहीं, अगर कहीं आधिकारिक प्रदर्शन होना है तो केवल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्देशित विनिर्देशों के अनुरूप चिह्न वाले झंडे का ही उपयोग किया जा सकता है।

भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन

- 30 दिसंबर, 2021 के आदेश के जरिये भारत ध्वज संहिता 2002 को संशोधित किया गया और राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते, हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/रेशम/खादी से बनाया जाएगा अर्थात संशोधन करके पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंडे को भी अनुमति दी गई।
- 20 जुलाई, 2022 को एक अन्य संशोधन के तहत केंद्र ने ध्राष्ट्रीय ध्वज को दिन के साथ-साथ रात में भी फहराने की अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन यह तब ही होगा जब झंडा किसी खुले स्थान पर किसी के घर पर फहराया जाएगा। विदित है कि इसके पहले के नियमों के अनुसार तिरंगा केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराने का नियम था।

अरबिंदो घोष

- 15 अगस्त को अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती मनाई गई।

अरबिंदो घोष

- इन्हे भारत की ऋषि परम्परा (संत परम्परा) की नवीन कड़ी के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है।
- यह एक क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, कवि, शिक्षाविद और दार्शनिक थे।
- इसका जन्म 15 अगस्त, 1872 को हुआ था।

योगदान

- 1893 में वे राज्य सेवा के अधिकारी बने।
- उन्होंने बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया।

क्रांतिकारी

- वह एक क्रांतिकारी समाज में शामिल हुए और भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की गुप्त तैयारी में अग्रणी भूमिका निभाई।
- वह भारत के पहले राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने अपने अखबार बंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुलकर सामने रखा।
- वह 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा से 20 साल पहले 'पूर्ण स्वराज' के पहले प्रस्तावक थे।

साहित्यिक कार्य

- वह एक पत्रकार भी थे और उनकी पहली दार्शनिक पत्रिका आर्य नामक 1914 में प्रकाशित हुई थी।
- 5 दिसंबर 1950 को अरबिंदो घोष का निधन हो गया।

लोक अदालत

- हाल ही में, देशभर की अदालतों में आयोजित हुई वर्ष 2022 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 83 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया गया।
- ज्ञातव्य है कि 35 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में एक साथ आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 18 लाख लंबित और 63 लाख प्री लीटिगेशन के मुकदमों का निस्तारण किया गया।
- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष भारत के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने महाराष्ट्र और राजस्थान में 'डिजिटल लोक अदालत' आयोजित करने के लिए तकनीकी प्लेटफार्मों का इस्तेमाल किया।
- 74 लाख से अधिक निपटाए गए मामलों में से 16.45 लाख विवाद लंबित थे और अन्य 58.33 लाख मुकदमे पूर्व चरणों में थे।
- नालसा के अनुसार "निपटान राशि का कुल मूल्य लगभग ₹5,039 करोड़ है।
- विदित है कि इससे पूर्व द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 95,78,209 प्रकरणों का निस्तारण ₹9,422 करोड़ की कुल राशि के साथ किया गया था।

महत्व

- लोक अदालतें न केवल "निवारण की तलाश के लिए एक कुशल विकल्प बन गई हैं, बल्कि बैकलॉग और लंबित मामलों से संबंधित अदालतों के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं"।
- न्याय मांगना अब विलासिता नहीं , अधिकार है।

लोक अदालत

- लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां अदालत में लंबित मामले या मुकदमेबाजी पूर्व चरण में समझौता या सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है
- विदित है कि लोक अदालत सुलह कराने की मंशा से शुरू किया गया एक ऐसा तंत्र है, जिसके माध्यम से कानूनी विवादों को अदालत के बाहर निस्तारित कर लिया जाता है।
- यह मामलों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसे सामान्य शब्दों में 'लोगों की अदालत' भी कहते हैं।
- यह कम से कम वक्त में विवादों को निपटाने के लिए एक आसान और अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन करता है।
- लोक अदालत सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति विवाद, श्रम विवाद आदि गैर-आपराधिक मामलों का निपटारा करती है।

वैधानिक स्थिति

- स्वतंत्रता के बाद पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था ।
- विवादों के निपटारे में यह पहल काफी सफल साबित हुई। फलतः लोक अदालत की संस्था देश के अन्य हिस्सों में विस्तार हुआ।
- इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस संस्था को वैधानिक समर्थन प्रदान करने और लोक अदालतों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की मांग उठी।
- इसलिए, लोक अदालत की संस्था को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

- समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन किया गया है।
- न्यायमूर्ति एन.वी. रमण, भारत के मुख्य न्यायाधीश संरक्षक-इन-चीफ हैं।
- नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश करते हैं जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-इन-चीफ हैं।
- जिले में विधिक सेवा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित है और संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है।

भारतीय सेना को सौंपी गई नई रक्षा प्रणाली

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने सेना को निपुण माइंस, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट (LCA) और F-INSAS सिस्टम प्रदान किया।
- ज्ञातव्य है कि नए स्वदेशी हथियार मिलने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ गई है। इन हथियारों में माइंस, पर्सनल वेपंस और लड़ाई में काम आने वाले वाहन हैं।

F-INSAS से आशय

- F-INSAS का पूरा नाम 'फ्यूचर इन्फैंट्री सोल्जर ऐज अ सिस्टम' है।
- यह एक तरह का प्रोग्राम है, जो थल सैनिकों के आधुनिकीकरण के लिए बनाया गया है। इससे एक सैनिक की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
- इस प्रॉजेक्ट के तहत सैनिक को हल्के वजन के आधुनिक सिस्टम से लैस किया जाता है।
- ये हर मौसम में काम करने सक्षम होते हैं, कम रख-रखाव मांगते हैं और किफायती होते हैं।

F-INSAS किस पर आधारित है?

- 2000 के दशक में परिकल्पित, F-INSAS विश्वभर में कई सैनिक आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में से एक है।
- विदित है कि अमेरिका के पास लैंड वॉरियर है, जबकि यूके के पास FIST (फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी) है।
- एक अनुमान के अनुसार, विश्वभर में 20 से अधिक सेनाएं ऐसे कार्यक्रमों का पालन कर रही हैं।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने F-INSAS को सेना के इन्फैंट्री सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लक्ष्यों के अनुरूप एक सैन्य अभियान के पूरे स्पेक्ट्रम और अवधि में सैनिक के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के उद्देश्य से तैयार किया था।

निपुन माइंस

- ये देश में विकसित बारूदी सुरंग हैं।
- यह घुसपैठियों और दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति की भांति कार्य करती है।
- इन्हें ऐंटी पर्सनेल माइंस इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि इन्हें इंसानों के खिलाफ उपयोग किया जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में बिछाए जा सकते हैं।

एलसीए

- एलसीए का पूरा नाम लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है।
- ये उन नावों का स्थान लेंगे, जो अभी पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग सो झील में गश्त करती हैं और सीमित क्षमता रखती हैं।
- एलसीए को गोवा की एक्वेरियस शिप यार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है।
- इनकी गति तेज होती है और हर तरह की परेशानी के बावजूद पानी में काम करने की क्षमता रखते हैं।
- ये नावें एक समय में 35 लड़ाकू सैनिकों को ले जा सकती हैं और बहुत ही कम समय में झील के किसी भी क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

- डीआरडीओ का आशय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है।
- इसकी स्थापना 1958 में भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) के तहत की गई थी।
- 1958 में इसे तीन प्रमुख रक्षा संगठनों को मिलाकर स्थापित किया गया था: रक्षा विज्ञान संगठन (डीएसओ) रक्षा तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (डीटीडीई) और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (डीटीडीपी)
- डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का आर एंड डी विंग है, जो भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ सशक्त बनाने और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक मिशन के साथ, हमारे सशस्त्र बलों को राज्य के साथ तीन सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और उपकरण से लैस करता है।

भारत में बाल मृत्यु दर

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने एक कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में सूचित किया कि भारत ने वर्ष 2014 के बाद से बाल मृत्यु दर को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं।
- विदित है कि भारत में बाल मृत्यु दर वर्ष 2019 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 45 से 35 प्रति 1,000 जीवित जन्म हो गया है।
- कार्यक्रम के दौरान 'पालन 1000' राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप लॉन्च किया गया।

- केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने मुंबई में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में वस्तुतः 'पालन 1000' राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप लॉन्च किया।
- कार्यक्रम में, पहले 1,000 दिनों में गर्भाधान के साथ-साथ बढ़ते बच्चे के जीवन के पहले दो वर्ष शामिल होते हैं और इस अवधि के दौरान बच्चे को सही पोषण, उत्तेजना, प्यार और समर्थन की आवश्यकता होती है।
- पहले 1,000 दिन बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक ठोस और प्रभावी मंच स्थापित करते हैं।
- बच्चे के अस्तित्व को अलग-थलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मां के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
- फलतः 'निरंतर देखभाल' की अवधारणा, जो बच्चे के अस्तित्व में सुधार के लिए महत्वपूर्ण जीवन चरणों के दौरान देखभाल पर बल देती है, का पालन राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।

पालन 1000

- 'पालन 1000 - पहले 1000 दिनों की यात्रा', अपने जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है।
- इसमें बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेरेंटिंग ऐप भी शामिल है।
- ऐप देखभाल करने वालों को व्यावहारिक सलाह देगा कि वे अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या कर सकते हैं और संदेह को दूर करने में मदद करेंगे।
- ऐप परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई सेवाओं के साथ माता-पिता, परिवारों और अन्य देखभाल करने वालों के लिए कोचिंग को जोड़ती है।
- कार्यक्रम को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के मिशन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें पहले 1,000 दिनों के दौरान उत्तरदायी देखभाल और केंद्रित हस्तक्षेप पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम है, जिससे सभी बच्चे अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें।
- इसका उद्देश्य 4 'डी' को कवर करने के लिए जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप करना है -
- जन्म के समय दोष , कमियां , रोग , विकास में देरी (विकलांगता सहित)।
- चयनित चयनित स्वास्थ्य स्थितियों के निदान वाले बच्चों को जिला स्तर पर प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं और अनुवर्ती देखभाल प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), एक नवोन्मेषी और महत्वाकांक्षी पहल है, जिसमें बाल स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं की परिकल्पना की गयी है।
- यह चिकित्सीय स्थितियों की प्रारंभिक पहचान और देख-भाल तथा सहयोग एवं उपचार के बीच संबंध के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। यह कार्यक्रम स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम को शामिल करता है।
- इसका उद्देश्य जन्म से लेकर अठारह (0 से 18) वर्ष तक के बच्चों में विशिष्ट रोग सहित 4डी अर्थात् चार प्रकार की व्याधियों के लिए शीघ्र पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप करना है।
- विदित है कि इन चार व्याधियों में जन्म के समय जन्म दोष, बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रूकावट की जांच शामिल है।
- ये सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, इस प्रकार उनके परिवारों को इलाज पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलती है।
- बच्चों की स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए, निम्नलिखित के साथ एक मजबूत अभिसरण है:
  - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनबाडी केंद्रों में नामांकित 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की स्क्रीनिंग
  - सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय।

जल जीवन मिशन

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक सम्बोधन में सूचित किया कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत गत तीन वर्षों में सात करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से जल कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे देश को अब तक गांवों में 10 करोड़ कनेक्शन का मील का पत्थर हासिल करने में सहायता मिली है।
- विदित है कि गोवा सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति कवरेज को चिह्नित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
- ज्ञातव्य है कि गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य है।
- दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव हर घर जल वाला पहला केंद्र-शासित प्रदेश बन गया है।
- मात्र 3 वर्ष में 7 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से जल की सुविधा प्रदान की गई है।
- आजादी के 7 दशक के बाद केवल 3 करोड़ घरों में ही यह सुविधा थी।

जल जीवन मिशन

- जल जीवन मिशन (JJM), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया था।
- वर्ष 2019 में प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन की शुरूआत की गई थी।
- जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
- कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों को लागू करने पर बल देता है, जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुन: उपयोग।
- जल जीवन मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- विदित है कि मिशन जल शक्ति मंत्रालय का एक हिस्सा है, जो योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।
- जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का एक संशोधित और उन्नत संस्करण है।
- भारत सरकार ने 2024 तक हर घर नल से जल (HGNSJ) नामक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक होम टैप कनेक्शन (FHTC) की प्रस्तुति के उद्देश्य से एनआरडीडब्ल्यूपी को जल जीवन मिशन (JJM) में पुनर्गठित किया है।

जल जीवन मिशन की विशेषताएं

- यह मिशन नल कनेक्शनों की सहायता से नल के पानी के कनेक्शन की कमी को दूर करेगा।
- यह स्थानीय प्रबंधन पर आधारित है अर्थात कितना पानी उपयोग किया जाता है और कितना उपलब्ध है।
- 2024 तक ग्रामीण घर के प्रत्येक व्यक्ति को नल कनेक्शन से प्रतिदिन 55 लीटर पानी मिल सकेगा।
- मिशन समुदाय को पानी के लिए एक योजना के साथ आने में मदद करता है, जिसमें व्यापक जानकारी, शिक्षा और संचार शामिल है।
- इस योजना में 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
- हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए, फंड को केंद्र और राज्य के बीच 90:10, बाकी राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए 100% विभाजित किया गया है।

जेजेएम के तहत प्रगति

- 15 अगस्त, 2019 को मिशन की घोषणा होने के समय भारत में 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में ही पानी का कनेक्शन था।
- गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, पुदुच्चेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में हर ग्रामीण घर में नल से जलापूर्ति हो रही है।
- पंजाब (99 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (92.4 प्रतिशत), गुजरात (92 प्रतिशत) और बिहार (90 प्रतिशत) जैसे कई अन्य राज्य भी 2022 में 'हर घर जल' के मुहाने पर पहुंच गये हैं।
- विदित है कि पांच वर्षों की अवधि में हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने के इस भगीरथी कार्य को पूरा करने के लिये 3.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
- केंद्रीय बजट 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिये 'हर घर जल' को 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2021-22 में राज्यों को 26,940 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों को जल तथा स्वच्छता सम्बंधी अनुदान दिये जाने की 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से जुड़ा है।
- अगले पांच वर्षों अर्थात 2025-26 तक के लिये 1,42,084 करोड़ रुपये के आश्वस्त वित्तपोषण का प्रावधान है।
- विदित है कि देश के ग्रामीण इलाकों में होने वाले इस भारी निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तथा आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। साथ ही गांवों में रोजगार के अवसर का भी सृजन हो रहा है।
- जल जीवन मिशन के तहत गुणवत्ता-प्रभावित गांवों, आकांक्षी जिलों, अजा/अजजा बहुल गांवों, कम पानी वाले इलाकों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के गांवों को प्राथमिकता के आधार पर नल से जल प्रदान किया जा रहा है।
- गत 24 महीनों में नल से जलापूर्ति में चार गुना वृद्धि हुई है तथा वह 117 आकांक्षी जिलों में 24 लाख (9.3 प्रतिशत) से बढ़कर लगभग 1.36 करोड़ (40 प्रतिशत) घरों तक पहुंच गई।
- अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, आंध्रप्रदेश, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पुदुच्चेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड ने प्रत्येक स्कूल में नल से जल की व्यवस्था कर ली है।
- केंद्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे बाकी बचे स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में जल्द से जल्द साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों के लिये बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ-सफाई की व्यवस्था बन सके।

निष्कर्ष

- जल जीवन मिशन 'सोपान' (बॉटम-अप) दृष्टिकोण का पालन करता है, जहां समुदाय योजना बनाने से लेकर उसे कार्यान्वित करने, प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव के काम में अहम भूमिका निभाते हैं।
- इसे प्राप्त करने के लिये ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्लूएससी)/पानी समिति का गठन किया जा रहा है तथा उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है।
- साथ ही समुदाय की संलग्नता से ग्रामीण कार्य-योजना विकसित की गई है, कार्यान्वयन समर्थन एजेंसियों को साथ लाया गया, ताकि कार्यक्रम के क्रार्यान्वयन में ग्रामीण समुदायों का समर्थन किया जा सके तथा लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है।

- अब तक देशभर में 4.69 लाख जल समितियों का गठन किया गया है और 3.81 लाख ग्राम कार्य-योजनायें विकसित की गई हैं।

वीएलसी मीडिया प्लेयर पर प्रतिबंध

- हाल ही में, वीडियोलैन क्लाइंट (वीएलसी) मीडिया प्लेयर की वेबसाइट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- वीएलसी के आंकड़ों के अनुसार भारत में फरवरी 2022 से उसकी वेबसाइट पर बैन लगा हुआ है।
- कुछ रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर को देश में बैन किया गया, क्योंकि इस प्लेटफार्म का उपयोग चीन के हैकिंग ग्रुप सिकाडा द्वारा साइबर हमलों के लिए किया जा रहा था।

वीएलसी के बारे में

- वीएलसी ने 90 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में लोकप्रियता हासिल की, जब सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण भारतीय घरों में पर्सनल कंप्यूटरों का प्रवेश हुआ।
- मुक्त और खुला स्रोत होने के अलावा, वीएलसी आसानी से अन्य प्लेटफार्मों और स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ एकीकृत होता है और अतिरिक्त कोडेक की आवश्यकता के बिना सभी फ़ाइल स्वरूपों का समर्थन करता है।

वीएलसी पर प्रतिबंध

- सबसे लोकप्रिय डिजिटल मीडिया प्लेयर में से एक पीसी और मैक के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप का मोबाइल संस्करण अभी भी ऐप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
- जो प्रतिबंध लगाया गया है, वह उचित प्रतिबंध नहीं है, अपितु एक नरम प्रतिबंध है।
- मूल रूप से, सरकार ने आधिकारिक वीएलसी मीडिया प्लेयर वेबसाइट तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है, जहां से उपयोगकर्ता पीसी और मैक के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर का नवीनतम संस्करण डाउनलोड कर सकते थे।
- उपयोगकर्ता अभी भी लोकप्रिय होस्टिंग साइटों और अन्य तृतीय-पक्ष वेबसाइटों से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डाउनलोड में आमतौर पर संक्रमित फ़ाइलों को ले जाने का जोखिम होता है जो दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं को कुछ गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं।
- जिन लोगों के पास अपने स्थानीय डिवाइस या क्लाउड स्टोरेज पर इंस्टॉलेशन फाइलें हैं, वे अभी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन लोगों के सिस्टम पर एप्लिकेशन इंस्टॉल है वे अभी भी सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं।
- इस वर्ष अप्रैल में, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि चीन से बाहर स्थित सिकाडा नामक एक हैकर समूह चीनी सरकार द्वारा समर्थित साइबर हमले अभियान के हिस्से के रूप में सिस्टम में मैलवेयर पहुंचाने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर का उपयोग कर रहा था।
- ये हैकर्स मुख्य रूप से उन यूजर्स को टारगेट करते थे जो Videolan.org वेबसाइट से अपनी फाइल्स डाउनलोड कर रहे थे।
- विदित है कि सिकाडा द्वारा साइबर हमले को तीन महाद्वीपों में फैला हुआ माना जा रहा है और इसका उद्देश्य जासूसी करना है। साथ ही इसने राजनीतिक, कानूनी और धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) में शामिल कई समूहों को लक्षित किया है।
- अमेरिकी सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी ब्रॉडकॉम की एक शाखा सिमेंटेक के शोधकर्ताओं ने पाया कि लक्ष्य पीसी तक पहुंच प्राप्त करने के बाद, हमलावर ने लोकप्रिय वीएलसी मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल समझौता उपकरणों पर एक संशोधित लोडर स्थापित करने के लिए किया।
- चूंकि मोबाइल ऐप्स Google के PlayStore और Apple के ऐप स्टोर सर्वर पर होस्ट किए जाते हैं, न कि उन सर्वरों पर जहां डेस्कटॉप संस्करण होस्ट किए जाते हैं, उन्हें सुरक्षित माना जाता है और इसलिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- यह संभावना है कि मंच को 54 चीनी ऐप्स के साथ प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसे भारत सरकार ने इस वर्ष फरवरी में प्रतिबंधित कर दिया था।
- यद्यपि, वीएलसी चीन आधारित सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि समर्थित और विकसित फ्रेंच समूह है।

12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया

- मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने भोपाल के रवींद्र भवन में 12वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की मेजबानी किया ।
- यह भारत का अपनी तरह का पहला फिल्म समारोह है जहां लोकप्रिय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों पर वृत्तचित्र (डाक्यूमेंट्री) और लघु फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।
- यह पहली बार है कि जब यह उत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा गया है।
- पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए, प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को क्रमशः गोल्डन बीवर, सिल्वर बीवर और ब्रॉन्ज़ बीवर से सम्मानित किया जाएगा।
- यह ब्रह्मांड की बेहतर सार्वजनिक समझ विकसित करने के लिए फिल्म निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों के साथ बातचीत करने का एक मंच है।
- यह आयोजन नागरिक विज्ञान और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा और विज्ञान फिल्मों की सराहना को बढ़ावा देगा।
- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी, विज्ञान प्रसार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के प्रावधान को रद्द किया

- 1988 के बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम में बेनामी लेनदेन में लिप्त लोगों के लिए अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।
- मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने इस प्रावधान को मनमाना होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 3 (2) को असंवैधानिक घोषित किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2016 का संशोधित कानून केवल भावी रूप से लागू होगा, न कि पूर्वव्यापी रूप से।
- सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील पर आया है।

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988:

- यह 5 सितंबर 1988 को लागू हुआ और यह कुछ प्रकार के वित्तीय लेनदेन को प्रतिबंधित करता है।
- यह एक 'बेनामी' लेन-देन को एक ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित करता है जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए हस्तांतरित की जाती है।
- काले धन पर अंकुश लगाने के प्रयास के रूप में इसे 2016 में संशोधित किया गया था।

गरबा को भारत द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया

- 2021 में, 'दुर्गा पूजा' को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था।
- यूनेस्को की अगली बैठक नवंबर में है और शायद गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जाएगा।
- यूनेस्को ने जुलाई में भारत को 2022-2026 चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा देने के लिए चुना था।
- समिति में जगह पाने के लिए भारत को 155 देश दलों से 110 वोट मिले।
- 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में 24 सदस्य शामिल हैं।
- वर्तमान में, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में 630 धरोहर हैं।
- 2021 तक, भारत की 14 सांस्कृतिक विरासतों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में रखा गया है।

केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की।
- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं की संख्या 2009 में 2,258 से घटकर 2021 में 509 हो गई है।
- 2009 में चरमपंथी हिंसा में 1,005 लोग मारे गए थे जबकि 2021 में 147 लोग मारे गए थे।
- केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में सभी गांवों के पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा हुई।
- बैठक में पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 को महिला हेल्प लाइन नंबर 181 और चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 के साथ जोड़ने पर भी चर्चा हुई।
- बैठक में महिलाओं से जुड़े मामलों को वास्तविक समय के आधार पर सखी-वन स्टॉप सेंटर में स्थानांतरित करने पर भी चर्चा हुई।
- केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
- छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 22 वीं बैठक आयोजित की गई थी।

आंचलिक परिषद/ क्षेत्रीय परिषद:

- ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
- पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं अर्थात उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदें। इन परिषदों की स्थापना 1957 में की गई थी। जबकि नॉर्थईस्ट काउंसिल की स्थापना 1971 में नॉर्थईस्ट काउंसिल एक्ट, 1971 के तहत की गई थी।
- इन परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

भारत ने एक लाख से अधिक (1,01,462) ओडीएफ प्लस गांवों की उपलब्धि हासिल की

- हाल ही में, भारत ने एक लाख से अधिक (1,01,462) ओडीएफ प्लस गांवों की उपलब्धि हासिल की है, इसमें शीर्ष पांच प्रदर्शन करने वाले राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं।
- इन राज्यों में अधिकतम गांवों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) प्लस घोषित किया गया है।
- ओडीएफ प्लस गांव अपना ओडीएफ दर्जा बनाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इन गांवों में ठोस और/या तरल कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था है।
- 2014 में, पीएम मोदी ने देश को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की।

- 2 अक्टूबर 2019 को, ग्रामीण भारत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो गया।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को 2020 में मंजूरी दी गई थी।
- एसबीएम-जी का दूसरा चरण सभी प्रकार के कचरे के उचित प्रबंधन के बारे में है।
- पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने एक गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती चरणों की शुरुआत की थी।

मध्यवर्ती चरण/श्रेणी	श्रेणी में गांवों की संख्या	मानदंड
ओडीएफ प्लस - आकांक्षी	54734 गांव	सभी घरों और संस्थानों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के माध्यम से स्वच्छता उपलब्ध कराने के अलावा, एसडब्ल्यूएम या एलडब्ल्यूएम की व्यवस्था है।
ओडीएफ प्लस - राइजिंग	17121 गांव	आकांक्षी श्रेणी के मानदंड के अलावा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) दोनों की व्यवस्था है।
ओडीएफ प्लस-मॉडल	29607 गांव	इस श्रेणी में उपरोक्त सभी मानदंड शामिल हैं और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेशों को प्रमुखता से प्रसारित और प्रदर्शित किया जाता है।

सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के लिए मौद्रिक सीमा, अभियोजन और जमानत संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 16 अगस्त को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान और प्रत्यक्ष तस्करी के मामले में 50 लाख रुपये के जुर्माने की सीमा होगी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के लिए यह 2 करोड़ रुपये होगी।
- सामान और प्रत्यक्ष तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के लिए पिछली सीमा क्रमश: 20 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये थी।
- सीमा शुल्क अधिनियम गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई मूल्य सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।
- सीबीआईसी द्वारा उन स्थितियों की अधिक विस्तृत सूची भी उपलब्ध कराई गई है जिनमें अपराध के परिणामस्वरूप गिरफ्तारी हो सकती है।
- शुल्क चोरी और 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सामान की गलत घोषणा से गिरफ्तारी हो सकती है।
- इसी तरह, सोने जैसे उच्च मूल्य के सामानों की तस्करी और 50 लाख रुपये से अधिक के सामानों के अनधिकृत आयात पर मुकदमा चलाया जा सकता है और गिरफ्तारी हो सकती है।
- सीमा शुल्क अधिनियम 1962 आयात और निर्यात प्रक्रियाओं, माल के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध, दंड और अपराधों से संबंधित है।

इंदौर जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा

- प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीजा डिवीजन के सचिव औसाफ सईद द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- यह प्रवासी भारतीयों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।
- 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था।

प्रवासी भारतीय दिवस:

- यह 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।
- यह 2003 से मनाया जा रहा है।
- इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
- 2015 से, यह हर दो साल में एक बार मनाया जाता है।

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार

- प्रस्तावित विधेयक मौजूदा भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को निरस्त करेगा और उसका स्थान लेगा।
- भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022 का मसौदा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए जारी किया गया है।
- भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908, 110 वर्ष से अधिक पुराना है।
- समुद्री उद्योग के विकास को सुसंगत और सुव्यवस्थित करने के अलावा, प्रस्तावित विधेयक अनावश्यक देरी, असहमति और जिम्मेदारियों को परिभाषित करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार करने में आसानी) को बढ़ावा देगा।
- राज्य समुद्री बोर्डों को राष्ट्रीय ढांचे में शामिल किया जाएगा।

प्रस्तावित विधेयक के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- विशुद्ध रूप से परामर्शी और अनुशंसात्मक ढांचे के माध्यम से आपस में राज्यों और केन्द्र-राज्यों के बीच एकीकृत योजना को बढ़ावा देना।
- अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत भारत के दायित्वों को शामिल करते हुए भारत में सभी बंदरगाहों के लिए प्रदूषण उपायों की रोकथाम सुनिश्चित करना।
- बढ़ते बंदरगाह क्षेत्र के लिए आवश्यक विवाद समाधान ढांचे में कमियों को दूर करना।
- डेटा के उपयोग के माध्यम से विकास और अन्य पहलुओं में पारदर्शिता और सहयोग की शुरूआत करना।
- भारत में 7,500 किमी लंबी तटरेखा, जहाजों के चलने योग्य 14,500 कि.मी. संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर सामरिक ठिकाने हैं।
- मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार और मूल्य के हिसाब से 65 प्रतिशत व्यापार बंदरगाहों द्वारा सुगम समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।

गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा 'निदान' पोर्टल विकसित किया गया है।
- गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के अपराधियों के लिए यह अपनी तरह का पहला डेटाबेस है। इसका उपयोग विभिन्न केंद्रीय और राज्य अभियोजन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

- यह नारकोटिक्स समन्वय तंत्र (एनसीओआरडी) पोर्टल का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 30 जुलाई को लॉन्च किया गया था।
- यह नशीले पदार्थों के अपराधियों से संबंधित डेटा के लिए वन-स्टॉप समाधान है और नशीले पदार्थों के मामलों की जांच करते समय एक प्रभावी टूल के रूप में कार्य करेगा।
- इसमें 'क्रिमिनल नेटवर्क' नाम का फीचर है, जो एक आरोपी के अन्य अपराधों और पुलिस की एफआईआर के बारे में एजेंसियों को जानकारी मुहैया कराता है।
- कोई भी एजेंसी इस प्लेटफॉर्म पर अपराधी से संबंधित आपराधिक इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, उंगलियों के निशान, अदालती मामलों आदि की खोज कर सकती है।
- 'निदान' पोर्टल इंटरऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली और ई-जेल रिपॉजिटरी से डेटा एकत्र करता है।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नज़र रखने और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

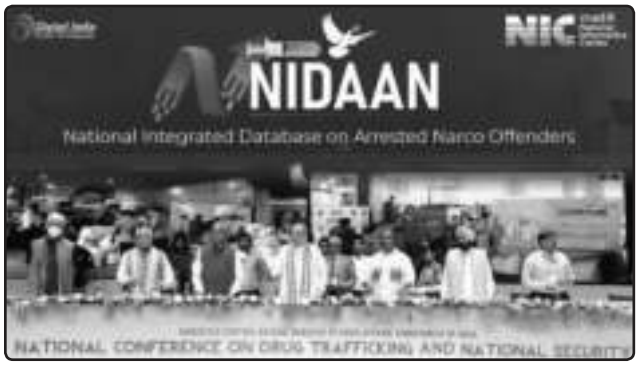

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने "अमृत काल के पांच प्रण" का आह्वान किया

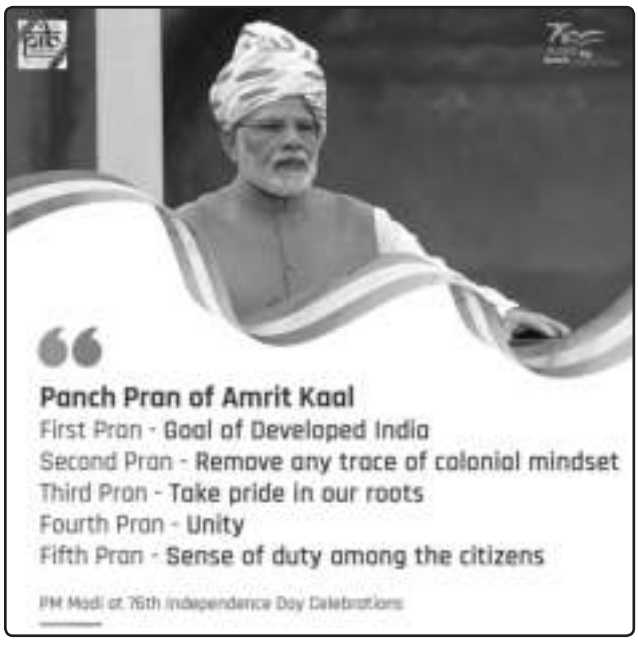

- स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए पांच प्रण लेने का आह्वान किया।
- पीएम मोदी ने कहा कि पांच "प्रण" (संकल्प) भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। उन्होंने आने वाले 25 साल को 'अमृत काल' कहा।
- अमृत काल के पंच प्रण हैं: विकसित भारत का लक्ष्य, औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को दूर करना, अपनी जड़ों पर गर्व करना, एकता, और नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना ।
- पहला प्रण भारत को एक विकसित देश बनाना है, जबकि दूसरा प्रण यह है कि गुलामी हमारे दिमाग या आदतों के सबसे गहरे कोने में भी नहीं होनी चाहिए।
- तीसरे प्रण में कहा गया है कि हमें अपनी विरासत पर गर्व महसूस करना चाहिए। चौथा प्रण एकता और एकजुटता के बारे में है, जबकि पांचवां प्रण राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्तव्य के बारे में है।
- उन्होंने 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान' का नारा भी दिया।
- 2047 में, भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा।

सरकार ने 'नमस्ते' (मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना) शुरू की

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना (नमस्ते) शुरू की।
- इसे व्यावसायिक सुरक्षा, सुरक्षा गियर और मशीनों तक पहुंच, कुशल मजदूरी के अवसरों और निरंतर क्षमता निर्माण में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है।
- यह सीवर/सेप्टिक टैंक श्रमिकों, कौशल, सफाई मित्र के आश्रितों के लिए उद्यमिता कार्यक्रम, और स्वच्छता से संबंधित वाहनों और उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सफाई मित्रों को स्वास्थ्य बीमा के साथ कवर किया गया हो।
- 500 शहरों ने खुद को "सफाई मित्र सुरक्षित शहर" घोषित किया है। सरकार प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक खुद को 'सफाई मित्र सुरक्षित' घोषित करेंगे।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत, शहर और राज्य हर 'मैनहोल' को 'मशीन होल' में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन 'यात्री सुरक्षा' शुरू किया

- यात्रियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) 'यात्री सुरक्षा' ऑपरेशन के तहत कई कदम उठाएगा।
- आरपीएफ स्टेशनों पर सीसीटीवी, सक्रिय अपराधियों की जांच, ट्रेन को एस्कॉर्ट करने, ब्लैक स्पॉट की पहचान आदि के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी हितधारकों द्वारा नियमित समन्वय किया जाएगा।
- जुलाई 2022 में, आरपीएफ ने अपराधियों के खिलाफ एक महीने का अखिल भारतीय अभियान शुरू किया था। आरपीएफ ने अवैध गतिविधियों के लिए 365 संदिग्धों को पकड़ा।

- सेवा ही संकल्प पहल के तहत, आरपीएफ ड्राइव, प्रश्नों के त्वरित प्रतिक्रिया और प्रौद्योगिकी की मदद से यात्रियों की सुरक्षा बनाए रखता है।

रेलवे सुरक्षा बल:

- रेलवे पुलिस का गठन 1854 में हुआ था और इसे पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कानूनी दर्जा दिया गया था।
- इसे रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत आरपीएफ के रूप में स्थापित किया गया था।
- बल के पास रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित अपराधों से बचाने का कार्य है।

एनएचए ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन-आधारित निधि आवंटन की घोषणा की।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों की रजिस्ट्री (एचपीआर) में डेटा रिकॉर्ड करने में उनके प्रदर्शन के आधार पर निधि आवंटित करेगा।
- प्रदर्शन-आधारित निधि आवंटन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के व्यवस्थित कार्यान्वयन में मदद करेगा।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (HFR) और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR) की अधिक संख्या आवश्यक है।
- पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एबीडीएम कार्यालयों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
- एनएचए ने डॉक्टरों, नर्सों आदि की संख्या और अस्पतालों, क्लीनिकों और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को निधि आवंटित करने का निर्णय लिया है।
- एनएचए ने निधि आवंटन के लिए नए मानदंड परिभाषित किए हैं, जो नीचे दिए गए हैं:
  - 31 दिसंबर 2022 तक एचएफआर और एचपीआर में प्रत्येक सत्यापित प्रविष्टि के लिए 100 रुपये
  - 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच एचएफआर और एचपीआर में प्रत्येक सत्यापित प्रविष्टि के लिए 50 रुपये।
  - 31 मार्च 2023 के बाद एचएफआर और एचपीआर में सत्यापित प्रविष्टियों के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।

भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज या पारसी नव वर्ष मनाया गया

- नवरोज पारसी समुदाय का सबसे व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे शांति और समृद्धि के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है।
- नवरोज के अवसर पर, पारसी प्रार्थना करने के लिए अग्यारी या अग्नि मंदिरों में जाते हैं। वे नवरोज के दिन गरीबों को खाना खिलाते हैं।
- पारसी नव वर्ष वसंत विषुव (स्प्रिंग इक्विनॉक्स) पर शुरू होता है। भारत का पारसी समुदाय शहंशाही कैलेंडर का उपयोग करके नया साल मनाता है।
- उत्तर भारत में नवरोज की परंपरा मुगल साम्राज्य से पहले की है।
- नवरोज हैदराबाद की रियासत में निज़ाम के शासन के तहत चार आधिकारिक छुट्टियों में से एक था।

सभी PACS को नियंत्रित करने के लिए सरकारों द्वारा मॉडल नियम शुरू किए जाएंगे

- अमित शाह ने कहा कि बीमार और निष्क्रिय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को सक्रिय किया जाना चाहिए या उनका परिसमापन किया जाना चाहिए।
- उन्होंने सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (NAFSCOB) द्वारा आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।
- श्री शाह ने पैक्स को सहकारिता आंदोलन का स्तंभ बताया और पैक्स को उनकी गतिविधियों में विविधता लाकर उन्हें मजबूत करने का आह्वान किया।
- अमित शाह ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) के लिए पांच वर्ष की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है।
- कामकाज की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दी गई है।
- श्री शाह ने सहकारी समितियों के माध्यम से 10 लाख रुपये के कृषि-वित्त प्रदान करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश भर में 2 लाख से अधिक नए पैक्स स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया।

सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियम बदले

- सरकार ने अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता में बदलाव को अधिसूचित किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे।
- नए नियमों के मुताबिक, एक अक्टूबर 2022 से कोई भी इनकम टैक्सपेयर अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।
- 4 जून तक, लगभग 5.33 करोड़ ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की सदस्यता ली है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई):

- इसे 2015 में लॉन्च किया गया था।
- इसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- एपीवाई सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹1000 से ₹5000 प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी।
- एपीवाई 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है।

- सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद पेंशन का भुगतान सब्सक्राइबर के पति या पत्नी को किया जाएगा।

संरक्षकता और बाल हिरासत पर संसदीय पैनल की सिफारिशें

- एक संसदीय स्थायी समिति ने 'अभिभावकता और दत्तक ग्रहण कानूनों की समीक्षा' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- समिति ने एचएमजीए (हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956) में तत्काल संशोधन की सिफारिश की है।
- समिति ने माता और पिता दोनों को प्राकृतिक अभिभावक के रूप में समान सलूक करने का भी सुझाव दिया।
- पैनल ने कहा कि वैवाहिक विवाद के मामले में अदालतों को दोनों माता-पिता को बच्चों की संयुक्त हिरासत देने या दूसरे को मिलने के अधिकार के साथ एक माता-पिता को एकमात्र हिरासत देने का अधिकार होना चाहिए।
- पैनल ने गोद लेने पर सिफारिशें भी दी हैं।
- समिति का कहना है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम (HAMA), 1956 के बीच तालमेल के लिए नए कानून की आवश्यकता है।
- नए कानून में एलजीबीटी समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- भारतीय कानून के अनुसार, एक हिंदू नाबालिग का नैसर्गिक अभिभावक पिता होता है और उसके बाद माता होती है।
- शरीयत या धार्मिक कानून के अनुसार, पिता प्राकृतिक अभिभावक होता है, लेकिन जब तक बेटा सात साल का नहीं हो जाता और बेटी यौवन तक नहीं पहुंच जाती, तब तक उसकी हिरासत मां के पास रहती है।
- दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 एलजीबीटी के गोद लेने पर मौन है न तो उन्हें बच्चे को गोद लेने की अनुमति देता है और न ही निषेध करता है।

31 दिसंबर 2024 तक पीएमएवाई-शहरी को जारी रखने की मंजूरी

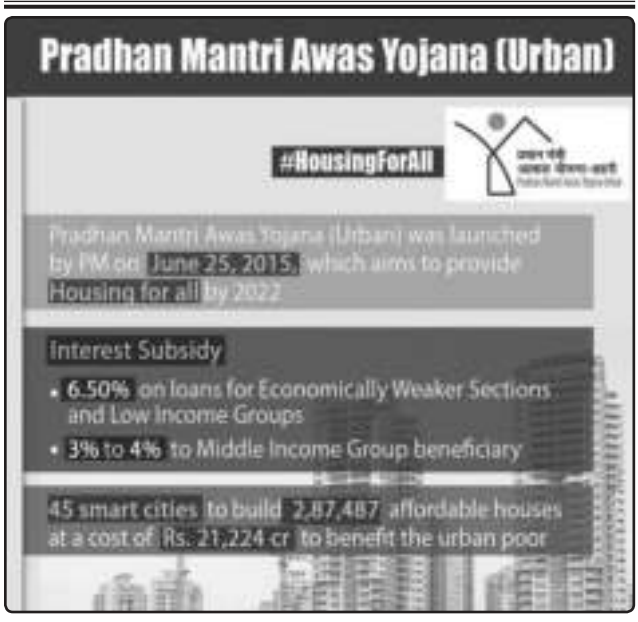

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) - सभी के लिए आवास मिशन शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को हर मौसम में पक्के मकान उपलब्ध कराने की प्रमुख योजना है।
- योजना के जारी रहने से लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण, साझेदारी में किफायती आवास और इन-सीटू स्लम पुनर्विकास वर्टिकल के तहत पहले से ही स्वीकृत घरों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- योजना के तहत पहले से स्वीकृत 122.69 लाख घरों को 31 मार्च, 2022 तक पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):

- इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था।
- यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- यह योजना चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), इन-सीटू (स्व-स्थाने) स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)।

मुंबई में 22वें 'भारत रंग महोत्सव' का उद्घाटन

- पांच दिवसीय नाटक महोत्सव 'भारत रंग महोत्सव' का आयोजन 9 से 13 अगस्त तक मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में किया गया ।
- इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया ।
- 22वें 'भारत रंग महोत्सव' में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और बलिदान पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन किया गया ।
- महोत्सव का समापन भोपाल स्थित कारवां थिएटर ग्रुप के हिंदी नाटक 'रंग दे बसंती चोल' के साथ हुआ ।
- 22वें भारत रंग महोत्सव, 2022 के हिस्से के रूप में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में 30 नाटकों का प्रदर्शन किया गया ।

भारत रंग महोत्सव:

- भारत रंग महोत्सव या राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव 1999 में शुरू हुआ था।
- यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD), नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक वार्षिक रंगमंच उत्सव है।
- भारत रंग महोत्सव भारत में रंगमंच के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उप-राष्ट्रपति चुने गए

- मौजूदा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त होने के एक दिन बाद 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली।
- श्री धनखड़ राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे।
- श्री धनखड़ ने अल्वा के 182 मतों की तुलना में 528 मतों के साथ 74.36 प्रतिशत के भारी मतों से जीत हासिल की।
- उन्हें पिछले छह उप-राष्ट्रपति चुनावों में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं।

उप-राष्ट्रपति:

- भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं।

- संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से युक्त एक निर्वाचक मंडल भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली चुनावी प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें गुप्त मतपत्र के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय वोट डाला जाता है।
- उपराष्ट्रपति संसद के सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होता है।
- भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
- इसके अलावा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार दो कार्यकाल के लिए चुने गए हैं।

भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के दल ने डोर्नियर 228 विमान पर उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया।

- मिशन को गुजरात के पोरबंदर में नौसेना एयर एन्क्लेव स्थित नौसेना की एयर स्क्वाड्रन-आई.एन.ए.एस.- 314 की पांच महिला अधिकारियों ने पूरा किया।
- मिशन की कप्तानी लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की।
- उनकी टीम में पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते शामिल थीं।
- लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत ने सामरिक और सेंसर अधिकारियों के रूप में मिशन में सहायता की।
- आई.एन.ए.एस.- 314 नौसेना की प्रमुख स्क्वाड्रन है। यह गुजरात के पोरबंदर में स्थित है। यह वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के तहत परिचालित है।

सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू की गई

- इसे एक मजबूत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए संरचित तरीके से राज्य और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है।
- स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस (SURE) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) की एक अभिनव योजना है।

- इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक वैधानिक निकाय है।
- नई योजना विश्वविद्यालय प्रणाली को मुख्यधारा के अनुसंधान में एकीकृत करने में सहायता करेगी और युवा संकाय को अत्याधुनिक अनुसंधान में भाग लेने में सक्षम बनाएगी।
- यह योजना 45 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के राज्य विश्वविद्यालय के संकायों को बहुत आवश्यक अनुसंधान अवसर प्रदान करेगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने 17 वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दी

- हर साल के 1 जनवरी को 18 साल के होने वाले मतदाताओं को अब मतदाता सूची में नामांकन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
- 17 साल से ऊपर के लोग अब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग ने आरपी अधिनियम 1950 की धारा 14(बी) में कानूनी संशोधनों और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 में परिणामी संशोधनों के अनुसरण में, विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची को तैयार/संशोधित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया शुरू की है।
- निर्वाचन आयोग ने आधार विवरण को फॉर्म से जोड़ने के लिए वैकल्पिक प्रावधान दिया है। ये नए संशोधित फॉर्म 1 अगस्त 2022 से लागू हो गए हैं।
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ने भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है।

'इंडिया @ 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप' जारी

- पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ' इंडिया @ 100 के लिए रोडमैप' जारी किया है ।

- 'इंडिया @ 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप' 2047 तक भारत को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक रूपरेखा है।
- रोडमैप को ईएसी-पीएम के अध्यक्ष डॉ बिबेक देबरॉय और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की उपस्थिति में जारी की गई है।
- 'इंडिया @ 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप' आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डॉ क्रिश्चियन केटेल्स का एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- यह प्रोफेसर माइकल ई. पोर्टर द्वारा विकसित प्रतिस्पर्धात्मकता ढांचे पर आधारित है।

'इंडिया @ 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप' के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- यह '4 एस' मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। '4 एस' मार्गदर्शक सिद्धांत समृद्धि की वृद्धि को सामाजिक प्रगति के अनुरूप बनाने, भारत के भीतर सभी क्षेत्रों में साझा किए जाने, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाने तथा बाहरी आघातों के समक्ष सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर बल देते हुए समृद्धि हासिल करने पर आधारित है।
- रोडमैप में सिफारिशें नए मार्गदर्शक सिद्धांतों, नीति लक्ष्यों और कार्यान्वयन संरचना पर आधारित हैं।
- यह भारत के वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मकता स्तर, सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों और विकास के अवसरों का गहन विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है।
- यह आवश्यक क्षेत्रों में सुझाव देता है, जिनमें श्रम उत्पादकता में सुधार और श्रम संघटन में वृद्धि करना, रोजगार के प्रतिस्पर्धी अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना और विभिन्न मंत्रालयों में व्यापक समन्वय के माध्यम से नीतिगत कार्यान्वयन में सुधार करना शामिल हैं।
- यह भारत की वृद्धि और विकास रणनीति का एक नया दृष्टिकोण है।

2021 में आत्महत्या से होने वाली मौतें अपने उच्चतम स्तर पर: एनसीआरबी

- हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने "भारत में दुर्घटना मृत्यु और आत्महत्या" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है ।
- एनसीआरबी के अनुसार, 2020 की तुलना में आत्महत्याओं की संख्या में 7.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डेटा से पता चलता है कि 2021 में कुल 164,033 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई।
- 2021 में आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या प्रति मिलियन 120 लोगों तक पहुंच गई, जो 1967 के बाद से उच्चतम दर है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में लगभग 42,004 दैनिक वेतन भोगियों ने आत्महत्या की।
- आत्महत्या के शिकार लोगों में दैनिक वेतन भोगियों का अनुपात (25.6 प्रतिशत) सबसे बड़ा पेशा बना रहा।

- 2021 में, खेती क्षेत्र में लगे व्यक्तियों द्वारा 10,881 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें 5,318 किसान और 5,563 खेतिहर मजदूर शामिल हैं।
- स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति द्वारा लगभग 20231 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। कुल आत्महत्याओं में स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति की हिस्सेदारी 11.3 प्रतिशत से बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गई है।
- बेरोजगार लोगों द्वारा आत्महत्या करने की संख्या 2020 में 15,652 से घटकर 2021 में 13,714 हो गई है।
- "गृहिणी" श्रेणी में आत्महत्या करने वालों की संख्या 2020 में 22,374 से बढ़कर 2021 में 23,179 हो गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में दर्ज की गईं, इसके बाद तमिलनाडु (18,925) और मध्य प्रदेश (14,956) का स्थान है।
- आत्महत्या की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि तेलंगाना (26.2 प्रतिशत), यूपी (23.5 प्रतिशत) और पुडुचेरी (23.5 प्रतिशत) में दर्ज की गई।

भारत का पहला 3डी प्रिंटेड डाकघर

- बेंगलुरू में भारत का पहला डाकघर होगा जो 3डी प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित होगा।
- एक महीने में डाकघर बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हलासुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थापित किया जाएगा।
- 1,000 वर्ग फुट में बने इस भवन को बनाने में 25 लाख रुपये का खर्च आएगा।
- आईआईटी-मद्रास के साथ भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा संरचनाओं की 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) को प्रौद्योगिकी अनुमोदन दिया गया है।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद नई निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

- हाल ही में भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के साथ यूरोपीय संघ-भारत के 60 वर्ष की राजनयिक संबंधों का उत्सव मनाया।
- विदित है कि रणनीतिक साझेदारी के वर्ष भर चलने वाले समारोहों को चिन्हित करने के लिए, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 'यूरोपीय संघ-भारत भागीदारी के लिए लिंकेज और अवसर' नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की।
- यूरोपीय संघ, यूरोपीय देशों से मिलकर बना एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- इसका गठन 1993 में किया गया था।
- यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं।
- यह चीन और भारत के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- समृद्ध रूप से विविध, यूरोपीय संघ (इसके 'सदस्य राज्य') बनाने वाले देश सभी समान मूल मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें शांति, लोकतंत्र, कानून का शासन और मानवाधिकारों का सम्मान. एक सीमा-मुक्त एकल बाजार और एकल मुद्रा (यूरो) आदि प्रमुख है और 19 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है।
- यूरोपीय संघ ने व्यापार और रोजगार को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है.

यूरोपीय संघ - उद्देश्य

- राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- एकल मुद्रा यूरो बनाकर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
- एकीकृत सुरक्षा और विदेश नीति
- सामान्य नागरिकता अधिकार
- न्यायपालिका, आप्रवास और शरण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना ।

भारत-ई.यू संबंधों का विकास

- दोनों पक्षों द्वारा 1994 में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जो व्यापार और आर्थिक सहयोग से से जुड़ा हुआ था।
- जून 2000 में पहले भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ने संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया।
- 2004 में पांचवें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में, संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' में उन्नत किया गया था ।
- दोनों पक्षों ने 2005 में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में संवाद और परामर्श तंत्र को मजबूत करने , व्यापार और निवेश बढ़ाने और लोगों और संस्कृतियों को एक साथ लाने की दिशा में एक संयुक्त कार्य योजना को अपनाया।
- जुलाई 2020 में 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ने संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करने और अगले पांच वर्षों में साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान किया ।
- यह रोड मैप पांच क्षेत्रों से संबद्ध था:
  - विदेश नीति और सुरक्षा सहयोग
  - व्यापार और अर्थव्यवस्था
  - सतत आधुनिकीकरण साझेदारी
  - वैश्विक शासन
  - लोगों से लोगों के संबंध ।

दोनों पक्षों के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

आर्थिक साझेदारी

- दोनों पक्षों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 116 अरब डॉलर के स्तर से ऊपर पहुँच गया।
- विदित है कि यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
- देश में 6,000 यूरोपीय कंपनियां हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 6.7 मिलियन नौकरियों का सृजन करती हैं।

जलवायु साझेदारी

- भारत और यूरोपीय संघ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते है।
- भारत और डेनमार्क के मध्य 'हरित रणनीतिक साझेदारी' का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण को संबोधित करना है।
- मई में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हरित प्रौद्योगिकियों और उद्योग परिवर्तन पर केंद्रित है, जो सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

रक्षा साझेदारी

- रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग में भी काफी वृद्धि हुई है।
- भारत और यूरोपीय संघ नियमित रूप से संयुक्त सैन्य और नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करते हैं, जो इंडो-पैसिफिक में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित आदेश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।
- 2021 में दोनों के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता समुद्री डोमेन जागरूकता, क्षमता निर्माण और संयुक्त नौसैनिक गतिविधियों में सहयोग पर केंद्रित थी ।
- फ्रांस द्वारा 36 राफेल लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी और भारतीय नौसेना को बाराकुडा परमाणु हमले की पनडुब्बियों की पेशकश करने की इच्छा उनके संबंधों में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।
- प्रमुख यूरोपीय रक्षा उपकरण निर्माता 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के साथ गठबंधन की गई रक्षा परियोजनाओं के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने के इच्छुक हैं।

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र

- भारत और यूरोप में स्टार्ट-अप और इनोवेशन इकोसिस्टम है ।
- इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संयुक्त संचालन समिति दोनों के बीच स्वास्थ्य देखभाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है।
- 2020 में, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय और भारत सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता हुआ था ।

चुनौतियां

- दोनों पक्षों के कुछ क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मत और हित हैं।
- यूक्रेन में रूस के हस्तक्षेप की स्पष्ट रूप से निंदा करने के लिए भारत की अनिच्छा और रूस के साथ देश के बढ़ते आर्थिक सहयोग में दोनों पक्षों के मध्य भिन्न मत है।
- भारत ने यूरोपीय संघ के दोहरे मानकों का आह्वान किया है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने 2021 में रूस से अपने गैस आयात का 45% क्रय किया।
- चीन की बढ़ती प्रभाविता को संतुलित करने में भी यूरोपीय संघ की रणनीति अस्पष्ट रही है।
- गलवान संघर्ष के दौरान इसकी मौन प्रतिक्रिया इसका एक उदाहरण है।

निष्कर्ष

- भारत और यूरोपीय संघ विभिन्न मतभेदों के बावजूद सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- विदित है कि वर्ष 2021 में महत्वाकांक्षी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार और निवेश समझौते की सक्रिय बहाली इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है ।
- साथ ही, यूरोपीय साझेदार भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्वीकार करते हैं।

भारत ने नाविकों के सुगम आवाजाही के लिए ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरान के शहरी विकास मंत्री रोस्तम घासेमी ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।
- यह समझौता ज्ञापन नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (STCW), 1978 के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों के नाविकों की आवाजाही में मदद करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी पर बुनियादी आवश्यकताओं को स्थापित करने वाला पहला कन्वेंशन था।
- केंद्रीय मंत्री ने व्यापार और वाणिज्य के लिए चाबहार बंदरगाह की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में छह मोबाइल हार्बर क्रेन को भी कमीशन किया।
- भारत के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और ईरानी हितधारकों के बीच सहयोग क्षेत्र की विशाल व्यापार क्षमता का उपयोग करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
- भारत और ईरान दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के बीच कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में ईरान भारत के लिए एक प्रमुख देश है।

ईरान

- यह पश्चिमी एशिया में स्थित है।
- इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर तेहरान है।
- यह अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है।
- सैय्यद अली होसैनी खामेनेई ईरान के वर्तमान सर्वोच्च नेता हैं।
- इब्राहिम रायसी वर्तमान राष्ट्रपति हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेक्सिको यात्रा के दौरान पांडुरंग खानखोजे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किया

- हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मेक्सिको यात्रा संपन्न हुई है, इस क्रम में उन्होंने कनाडा के हैलिफ़ैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भी भाग लिया। मेक्सिको यात्रा के दौरान ओम बिरला ने पांडुरंग खानखोजे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किया।

पांडुरंग खानखोजे:

- वह महाराष्ट्र में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक थे।
- वह ग़दर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
- उनका मेक्सिको के साथ घनिष्ठ संबंध था, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता ग़दर पार्टी से जुड़े होने के कारण शरण मांगी थी।
- वह फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े प्रशंसक थे।
- उन्हें मेक्सिको के चैपिंगो में नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने फसलों की ठंढ और सूखा प्रतिरोधी किस्में विकसित कीं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं का समुद्री साझेदारी अभ्यास (एमपीएक्स)

- 20 अगस्त को भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं का समुद्री साझेदारी अभ्यास (एमपीएक्स) संपन्न हुआ, इस अभ्यास में आईएनएस सुमेधा और एचएमएएस अंजाक की भागीदारी ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच मजबूत संबंध और अंतःक्रियाशीलता की पुष्टि की।
- 15 अगस्त को, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुमेधा को भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में डॉक किया गया था।
- आईएनएस सुमेधा वर्तमान में भारतीय नौसेना के परिचालन परिनियोजन (ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट) के हिस्से के रूप में दक्षिणपूर्वी हिंद महासागर में तैनात है।

- आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, वह सभी महाद्वीपों (अंटार्कटिका को छोड़कर) पर 'तिरंगा' फहराने की भारतीय नौसेना की पहल का एक हिस्सा है।
- आईएनएस सुमेधा एक नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है जिसका निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है और इसे बेड़े के संचालन के समर्थन में कई भूमिकाओं के लिए तैनात किया गया है।
- वह भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी बेड़े के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के संचालन कमान के तहत कार्य करती हैं।

ब्रिटेन से सात कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर

- हाल ही में ब्रिटेन के ग्लासगो संग्रहालय और भारत सरकार ने सात कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ।
- 18 महीने की बातचीत के बाद, यूके के ग्लासगो संग्रहालय और भारतीय उच्चायोग, लंदन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- सात कलाकृतियों में 14वीं सदी की इंडो-फ़ारसी तलवार, 10वीं सदी के भारत के तीन नक्काशीदार पत्थर के खंभे, पत्तेदार डिज़ाइन वाला एक जड़ा हुआ संगमरमर का खंभा, सूर्य और हिंदू देवी उमा या दुर्गा की 10वीं सदी का काला क्लोराइट स्टील शामिल हैं।
- इनमें से अधिकांश कलाकृतियाँ 19वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के मंदिरों और तीर्थस्थलों से चुराई गई थीं। उनमें से एक को मालिक से चोरी के बाद खरीदा गया था।
- चोरी की ये कलाकृतियां कानपुर, कोलकाता, ग्वालियर, बिहार और हैदराबाद की बताई जा रही हैं।
- ग्लासगो लाइफ के अनुसार, एक धर्मार्थ संगठन जो शहर के संग्रहालयों को चलाता है, सभी सात कलाकृतियों को बाद में ग्लासगो संग्रहालय को उपहार में दिया गया था।
- ग्लासगो सिटी काउंसिल ने अन्य देशों को भी कुल 51 वस्तुओं को वापस करने का फैसला किया है, जिसमें नाइजीरिया से 19 बेनिन कांस्य शामिल हैं।

ग्रीस ने यूरोपीय संघ के 'उन्नत निगरानी' ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की

- ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोताकिसो ने यह घोषणा की। यह नीति निर्माण में अधिक स्वतंत्रता देगा और 12 वर्षों के दर्द को समाप्त करेगा।
- 2010 में पहले बेलआउट के बाद, ग्रीस ने पेंशन में कटौती, खर्च की कमी, कर में वृद्धि और बैंक नियंत्रण को लागू किया है।
- ग्रीस के आर्थिक विकास और नीति पर 2018 से लगातार नजर रखी जा रही है।
- ढांचे से बाहर निकलने से ग्रीस को "निवेश ग्रेड" क्रेडिट रेटिंग हासिल करने में मदद मिलेगी।
- निगरानी ढांचे का उद्देश्य स्थायी आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए आर्थिक कठिनाई के संभावित स्रोतों और संरचनात्मक सुधारों से निपटने के उपायों के अपनाने को सुनिश्चित करना है।

ग्रीस:

- यह दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है।
- यह अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया और बुल्गारिया और तुर्की के साथ भूमि सीमा साझा करता है।
- भूमध्यसागरीय बेसिन में इसकी सबसे लंबी तटरेखा है।
- क्यारीकोस मित्सोताकिसो वर्तमान प्रधान मंत्री हैं।
- एथेंस ग्रीस की राजधानी है और मुद्रा यूरो है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय-फ्रांस परिवहन क्षेत्र समझौते को अपनी मंजूरी दी

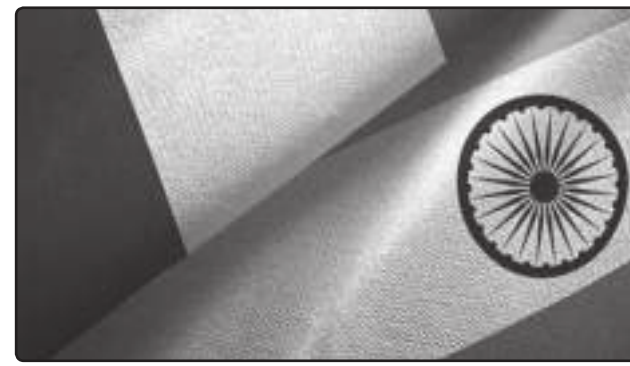

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, फ्रांस और प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद (TIFAC), भारत के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- यह भारतीय परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) की गतिविधियों का समर्थन करेगा।
- आधिकारिक बयान के अनुसार, अनुबंध पर 6 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे।
- इस अनुबंध के तहत नई गतिविधियां जैसे नए वैज्ञानिक परिणाम और परिवहन क्षेत्र के डीकार्बराइजेशन के लिए प्रौद्योगिकी की पहचान मुख्य उद्देश्य होंगे।
- यह नई नीतिगत दृष्टिकोण और वैज्ञानिक संवाद के माध्यम से क्षमता निर्माण में भी मदद करेगा।
- पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की।
- भारत और फ्रांस ने 1998 में एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ):

- यह ओईसीडी प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी संगठन है।

- यह परिवहन नीति के मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल विधेयक पर हस्ताक्षर किए

- विधेयक को दवाओं की कीमतों को कम करने; मेडिकेयर लाभों में वृद्धि करने; अक्षय ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए पेश किया गया है।
- इस बिल से दवा की कीमत का तरीका बदल जाएगा। यह मेडिकेयर प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रति वर्ष $ 2,000 आउट-ऑफ-पॉकेट पर चिकित्सकीय दवा की लागत को सिमित करेगा।
- नया कानून लगभग 13 मिलियन अमेरिकियों को उनके स्वास्थ्य बीमा का भुगतान करने में भी मदद करेगा।
- यह कुछ निगमों पर करों में भी वृद्धि करेगा। निगमों पर कम से कम 15 फीसदी टैक्स लगेगा।
- यह संघीय घाटे को कम करेगा और धन कर चोरों को पकड़ने के लिए आंतरिक राजस्व सेवा को अधिक शक्ति प्रदान करेगा।
- बिल स्वच्छ बिजली को प्रोत्साहन देगा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए अनुदान, ऋण और कर क्रेडिट बढ़ाएगा।
- सरकार अगले दशक में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए लगभग 375 अरब डॉलर का निवेश करेगी।
- मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में घाटे को लगभग 275 बिलियन डॉलर कम करना है।

भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को पहला डोर्नियर निगरानी विमान दिया

- 16 अगस्त को, भारत ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में एक समारोह के दौरान श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान दिया।
- भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले और भारतीय नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने द्वीप राष्ट्र की दो दिवसीय यात्रा पर विमान को सौंपा।
- जनवरी 2018 में आयोजित रक्षा वार्ता के दौरान, श्रीलंका को अपनी समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत से दो डोर्नियर विमान हासिल करने की उम्मीद थी।
- डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक-ऑफ और लैंडिंग (STOL) क्षमता वाला एक मल्टीरोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है।
- यह 1981 से उत्पादन में है और भारतीय नौसेना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मिशन, समुद्री निगरानी और आपदा राहत प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाता है।
- डोर्नियर एयरक्राफ्ट का हैंडओवर चीनी जहाज युआन वांग 5 के श्रीलंकाई बंदरगाहों पर एक सप्ताह के लिए डॉक करने से एक दिन पहले हुआ।

मैक्सिकन राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा

- मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर ने संयुक्त राष्ट्र को पांच साल के लिए तीन विश्व नेताओं का एक आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया है।
- आयोग में पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं।
- आयोग का उद्देश्य दुनिया भर में युद्धों को रोकना और कम से कम पांच साल के लिए एक समझौते पर पहुंचना है।
- मेक्सिको के राष्ट्रपति ने चीन, रूस और अमेरिका को शांति की तलाश और युद्ध जैसी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए आमंत्रित किया है।
- ओब्रेडोर के अनुसार, प्रस्तावित संघर्ष विराम ताइवान, इज़राइल और फिलिस्तीन के मामले में एक समझौते पर पहुंचने में मदद करेगा।

आसियान ने म्यांमार के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया

- आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने म्यांमार के शासक जनरल को शांति योजना पर प्रगति होने तक किसी भी बैठक में भाग लेने से मना करने पर सहमति व्यक्त की है।

- सेना प्रमुख और तख्तापलट नेता मिन आंग हलिंग ने म्यांमार में हिंसा को तत्काल समाप्त करने और सभी पक्षों के बीच बातचीत के लिए जकार्ता में 24 अप्रैल 2021 को पांच सूत्री सहमति पर सहमति व्यक्त की थी।
- वे सभी संबंधित पक्षों के साथ वार्ता प्रक्रिया की मध्यस्थता के लिए आसियान के विशेष दूत पर भी सहमत हुए।
- म्यांमार संकट तब शुरू होता है जब सेना ने निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में लिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया।
- फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद, पूरे देश में बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन और विरोध शुरू हुआ।
- पिछले सैन्य शासन के तहत, म्यांमार 1997 में आसियान में शामिल हुआ था।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ (आसियान)

- इसका गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था।
- इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार (बर्मा), कंबोडिया और लाओस आसियान के सदस्य हैं।
- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है।

भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक आधार वाले संबंधों के लिए मालदीव के साथ छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए

- नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।
- साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे सहित क्षेत्रों में छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत-मालदीव ने अड्डू सड़क परियोजना की प्रगति, 34 द्वीपों पर पानी और सीवरेज सुविधाओं के प्रावधान और हुकुरु मिस्की (शुक्रवार मस्जिद) के जीर्णोद्धार की समीक्षा की।
- पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पड़ोसी राष्ट्र के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा की।

मालदीव:

- यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
- यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप एशियाई देश है और एशिया का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश है।
- **राजधानी:** माले
- **मुद्रा:** मालदीवियन रूफिया
- **मालदीव के राष्ट्रपति:** इब्राहिम मोहम्मद सोलिह

अमेरिका ने अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को मारने के लिए 'हेलफायर आर 9एक्स' मिसाइल का इस्तेमाल किया

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमले में 'हेलफायर आर 9एक्स मिसाइल' का उपयोग करके मार गिराया है।

- अमेरिका ने अपने एमक्यू -9 रीपर ड्रोन से 'हेलफायर आर 9एक्स' मिसाइलों को लॉन्च किया।
- अयमान अल-जवाहिरी ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी था।
- एमक्यू-9 रीपर ड्रोन का निर्माण जनरल एटॉमिक्स द्वारा किया गया है।

हेलफायर 9 एक्स मिसाइल क्या है?

- इसे औपचारिक रूप से AGM-114R9X के नाम से जाना जाता है। इसे 'फ्लाइंग जिंसु' और 'निंजा बम' के नाम से भी जाना जाता है।
- इसमें ब्लेड होते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इमारतों या कार की छतों को काट सकते हैं।
- इसमें छह ब्लेड होते हैं जो तेज गति से उड़ते हैं और बिना किसी विस्फोट के लक्ष्य को भेदते हैं।
- इसका उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब एक आतंकवादी लीडर को चिन्हित किया गया हो और लक्ष्य के आसपास निर्दोष नागरिक होते हैं।
- यह लगभग पांच फीट लंबा है और इसका वजन 100 पाउंड से अधिक है। इसके सिरे पर 45 किलो का प्रबलित धातु होता है।

भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न

- डॉ श्रीकर के रेड्डी ने 1-3 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति के पहले सत्र की सह-अध्यक्षता की।
- भारत और मॉरीशस के बीच उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का गठन व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) के तहत किया गया है।
- समिति भारत और मॉरीशस के बीच सीईसीपीए के सामान्य कामकाज और कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। भारत और मॉरीशस के बीच सीईसीपीए 1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ।
- दोनों पक्ष सीईसीपीए में सामान्य आर्थिक सहयोग (जीईसी) अध्याय और स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र (एटीएसएम) को शामिल करने पर सहमत हुए।
- जीईसी अध्याय निवेश, वित्तीय सेवाओं, वस्त्र, लघु और मध्यम उद्यमों, हस्तशिल्प आदि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा।

- दोनों पक्ष सीमा शुल्क पारस्परिक प्रशासनिक सहायता समझौते (सीएमएमए) पर चर्चा शुरू करने पर भी सहमत हुए।
- दोनों देशों ने द्विपक्षीय संस्थागत सहयोग में सुधार के लिए द्विपक्षीय केंद्र बिन्दुओं की भी पहचान की।
- भारत और मॉरीशस के बीच व्यापार 2019-20 में 690.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 786.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

"विनबैक्स 2022" अभ्यास

- 1 अगस्त को, वियतनाम और भारत के बीच चंडीमंदिर(हरियाणा) में "विनबैक्स 2022" द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ।
- यह अभ्यास 20 अगस्त तक चला।
- यह अभ्यास 2019 में पहले वियतनाम में आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
- एक्स विनबैक्स 2022 का विषय "शांति सेनाओं के संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम की नियुक्ति और तैनाती" है।
- भारतीय सेना और वियतनाम पीपुल्स आर्मी आपसी विश्वास और अंतःक्रियाशीलता का निर्माण करेगी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगी।
- 105 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिक भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह-IV

- अल नजाह-IV भारतीय सेना की टुकड़ियों और ओमान की शाही सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

- अल नजाह-IV की शुरुआत 01 अगस्त 2022 को राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुई है। इसका समापन 13 अगस्त को हुआ ।
- इसका उद्देश्य भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है।
- भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन के सैनिक कर रहे हैं।
- अभ्यास अल नजाह-IV का पिछला संस्करण मस्कट में 12 से 25 मार्च 2019 तक आयोजित किया गया था।

मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का 4 दिवसीय भारत दौरा

- मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 1 अगस्त से 4 दिवसीय भारत दौरा पर थें, उनके साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक टीम और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया था ।
- उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत भी संपन्न हुई ।
- उनकी यात्रा के दौरान दोनों देश ने साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा किया ।
- भारत ने 1965 में मालदीव को उसकी स्वतंत्रता के बाद मान्यता दी।

भारत-मालदीव संबंध:

- भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 300 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया।
- भारत की पड़ोस प्रथम नीति में मालदीव का विशेष स्थान है।
- फरवरी 2022 में, भारत और मालदीव ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए तीसरी रक्षा सहयोग वार्ता का आयोजन किया।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया

- मुंबई में आयोजित चाबहार दिवस सम्मेलन में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
- चाबहार बंदरगाह भारत को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर नेटवर्क का हिस्सा होगा।
- चाबहार बंदरगाह भारत और यूरेशियाई देशों के लिए नए रास्ते खोलेगा और यह हिंद महासागर क्षेत्र को यूरेशिया से जोडने के लिए भारत के इंडो-पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

चाबहार बंदरगाह:

- चाबहार ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित एक बंदरगाह है।
- इसमें शाहिद कलंत्री और शाहिद बेहेश्ती नाम के दो अलग-अलग बंदरगाह हैं।
- यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए ईरान और अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- यह भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

विश्वविद्यालयों के आसियान-भारत नेटवर्क का शुभारंभ

- 28 अगस्त को, विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री (MoS) डॉ राजकुमार रंजन सिंह, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) सचिवालय की अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए इंडोनेशिया गए थे।

- यह राजकुमार रंजन की आसियान सचिवालय और इंडोनेशिया की पहली यात्रा थी।
- डॉ. सिंह ने आसियान महासचिव लिम जॉक होई और नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति सुनैना सिंह के साथ विश्वविद्यालयों के आसियान-भारत नेटवर्क (एआईएनयू) का भी उद्घाटन किया।
- उन्होंने कहा कि एआईएनयू भारतीय विश्वविद्यालयों और आसियान सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करके इस क्षेत्र में एक ज्ञान केंद्र के निर्माण में योगदान देगा।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान के प्रतिष्ठित संस्थानों के एक संघ के रूप में एआईएनयू की घोषणा की थी।
- इसका उद्देश्य अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों और आसियान सदस्य राज्यों के बीच सहयोग के माध्यम से भारत में ज्ञान पूंजी का एक मुख्य नेटवर्क बनाना है।
- एआईएनयू को क्रमशः भारत और आसियान से नालंदा विश्वविद्यालय और आसियान विश्वविद्यालय नेटवर्क द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वर्ष 2022 को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है।
- भारत ने 1992 में आसियान के साथ "क्षेत्रीय संवाद भागीदार" के रूप में औपचारिक बातचीत शुरू की और फिर 1996 में "डायलॉग पार्टनर" बन गया।

सैन्य अभ्यास 'एम्पल स्ट्राइक' शुरू किया गया

- 29 अगस्त से 16 सितंबर तक, चेक गणराज्य नौवें सैन्य अभ्यास, "एम्पल स्ट्राइक 2022" की मेजबानी कर रहा है।
- एम्पल स्ट्राइक 2022 अभ्यास में सात अलग-अलग देशों के लगभग 900 सैनिक शामिल हैं।
- अभ्यास नेमस्ट नाद ओस्लावौ, कास्लाव, और केबली हवाई क्षेत्रों के साथ-साथ बोलेटिस, लिबवा और सेस्के बुदेजोविस शहर के क्षेत्रों में हो रहे हैं।
- अभ्यास का मुख्य उद्देश्य लक्ष्यीकरण इकाइयों, वायु सेना और जमीनी कमांडरों के बीच समन्वय में सुधार करना है।
- अभ्यास में चेक सैनिकों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, जर्मनी, लातविया और एस्टोनिया के सैनिक शामिल होंगे।

पहली बार, भारत ने "ताइवान जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के सैन्यीकरण" का उल्लेख किया

- भारत ने पहली बार ताइवान के प्रति चीन की कार्रवाई पर टिप्पणी की है।
- श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी किया जिसमें भारत ने चीन पर "ताइवान जलडमरूमध्य का सैन्यीकरण" करने का आरोप लगाया।
- एक सप्ताह के लिए श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर एक चीनी सैन्य अनुसंधान पोत के डॉक किए जाने के बाद भारत ने यह बयान दिया।
- हाल ही में, चीन ने अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास पूरा किया।
- भारत ने 1949 से "एक चीन नीति" का पालन किया और ताइवान के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे।
- भारत ने 2008 के बाद से अपने आधिकारिक बयानों में इस नीति का जिक्र करना बंद कर दिया था।

ताइवान जलडमरूमध्य:

- यह दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है।
- यह एक 180 किमी लंबी जलडमरूमध्य है, जो ताइवान और मुख्य भूमि चीन को अलग करती है।
- चीन ताइवान जलडमरूमध्य पर अधिकार क्षेत्र का दावा करता है।
- वैश्विक व्यापार का लगभग 20% भाग इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।

भारत नेपाल में दो जलविद्युत संयंत्रों का निर्माण करेगा

- भारत नेपाल में वेस्ट सेती जलविद्युत परियोजना और सेती नदी जलविद्युत परियोजना का विकास करेगा।

- सेती नदी पर दो परियोजनाओं को विकसित करने के लिए नेपाल के निवेश बोर्ड और भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 2.4 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
- परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कुल 1,200 मेगावाट का उत्पादन होगा और यह चार जिलों बजहांग, डोटी, दडेलधुरा और अछाम में फैला होगा।
- भारत को बिजली बेचकर नेपाल 2030 तक प्रति वर्ष 31,000 करोड़ रुपये और 2045 तक प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन रुपये तक कमा सकता है।
- चीनी कंपनियां दो बार वेस्ट सेती प्रोजेक्ट से हट चुकी हैं।
- 2009 में, चीनी कंपनियों ने परियोजना को विकसित करने के लिए नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और दो साल के भीतर पीछे हट गए।
- 2017 में, चीन के थ्री गोरजेस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने परियोजना को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की और 2018 में परियोजना से हट गए।
- सेती नदी या सेती खोला या सेती गंडकी नदी, त्रिशूली नदी की एक बाएँ किनारे की सहायक नदी है जो पश्चिमी नेपाल में बहती है। यह अन्नपूर्णा मासिफ के आधार से निकलती है, और दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में पोखरा और दमौली से बहती हुई देवघाट के पास त्रिशूली नदी में मिल जाती है।

भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (JRC) की 38वीं बैठक

- भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (JRC) की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने तीस्ता, गंगा और अन्य नदियों के जल बंटवारे की संधियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.
- उन्होंने आपसी हित की चल रही परियोजनाओं पर भी चर्चा की, जिसमें साझा नदी जल का साझाकरण, बाढ़ पर डेटा साझा करना, नदी प्रदूषण का मुकाबला करना, तलछट प्रबंधन पर संयुक्त सर्वेक्षण आदि शामिल हैं।

- बांग्लादेश के जल संसाधन राज्य मंत्री जाहिद फारूक ने बैठक में 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
- भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर एक समझौता ज्ञापन के कंटेंट को भी अंतिम रूप दिया।
- संयुक्त नदी आयोग की बैठक 12 साल बाद हुई। जेआरसी फ्रेमवर्क के तहत दोनों देशो के बीच द्विपक्षीय तकनीकी चर्चा और परामर्श जारी थी।
- भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियाँ हैं, जिनमें से 7 नदियों को प्राथमिकता के आधार पर जल बंटवारे समझौते के फ्रेमवर्क के लिए पहले चुना गया था।
- बांग्लादेश के साथ भारत के सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक वास्तविक समय में बाढ़ के आंकड़ों को साझा करना है।
- गंगा जल संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 2026 में नवीनीकृत किया जाएगा।
- बांग्लादेश और भारत ने खुलना- दरसना के बीच एक नई ब्रॉड-गेज लाइन के निर्माण और पार्बतीपुर और कौनिया के बीच मीटर गेज लाइन को ड्यूल-गेज लाइन में बदलने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

भारत और चीन के बीच तनाव अंतरिक्ष परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है

- भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव विकासशील चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग पर भारत निर्मित स्पेक्ट्रोस्कोप स्थापित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रभावित कर सकता है।
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA), बेंगलुरु के वैज्ञानिक, उन नौ समूहों में शामिल थे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली पहल के हिस्से के रूप में चुना गया था।
- चीनी अंतरिक्ष एजेंसी तियांगोंग को अंतरराष्ट्रीय प्रयोग भेजने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय बाहरी अंतरिक्ष मामलों (यूएनओओएसए) के साथ काम कर रही है।
- नेबुलर गैस स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच (SING) परियोजना आईआईए में शोध छात्रों द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है।
- यह खगोल विज्ञान संस्थान और रूसी विज्ञान अकादमी की एक सहयोगी परियोजना है।
- 'सिंग' (SING) परियोजना भारत और चीन को शामिल करने वाली पहली अंतरिक्ष सहयोग परियोजना होगी।
- भारत और चीन ने पूर्व में जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जैसी अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग किया था।
- 'सिंग' (SING) परियोजना का उद्देश्य विकासशील चीनी अंतरिक्ष स्टेशन - तियांगोंग पर एक स्पेक्ट्रोस्कोप स्थापित करना है।
- यह पराबैंगनी विकिरण के अध्ययन के लिए एक स्पेक्ट्रोग्राफ भेजने और लगाने से जुड़ा है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्षेत्र में अंतरतारकीय गैस के स्रोतों का विश्लेषण करने में मदद करेगा।
- टी-आकार के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में तीन मॉड्यूल होंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाद यह केवल दूसरा ऐसा स्टेशन होगा।

साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी" का आयोजन

- 31 अगस्त को भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) के सहयोग से 13 देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय रैनसमवेयर विरोधी पहल- रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप - के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी" की रूपरेखा तैयार करके उसका सफलतापूर्वक संचालन किया। रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व भारत द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के नेतृत्व में किया जा रहा है।
- इस अभ्यास का विषय "रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना" था। इस अभ्यास परिदृश्य वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से लिया गया था, जिसमें घरेलू स्तर की (सीमित प्रभाव वाली) रैनसमवेयर की एक घटना बड़ी होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का रूप ले लेती है।
- सीईआरटी-इन द्वारा अभ्यास "सिनर्जी" का आयोजन अभ्यास से संबंधित अपने सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर किया गया था। प्रत्येक राज्य ने एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय सीईआरटी/सीएसआईआरटी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), संचार तथा आईटी/आईसीटी मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लोग शामिल थे।
- इस अभ्यास का विशिष्ट उद्देश्य रैनसमवेयर और जबरन वसूली की नीयत से किए गए साइबर हमलों के खिलाफ सुदृढ़ नेटवर्क बनाने हेतु सदस्य-देशों के बीच विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यप्रणालियों का आकलन व आदान - प्रदान करना और उन्हें बेहतर बनाना था।
- अभ्यास "सिनर्जी" अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा और इसने सीआरआई के सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय एवं सहयोग से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान की ताकि नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया जा सके और रैनसमवेयर हमलों से कारगर तरीके से निपटा जा सके।

क्या है रैनसमवेयर?

- रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर (Malware) है। यह कंप्यूटर में ई-मेल या अन्य माध्यमों से पहुँचकर डेटा को ब्लॉक कर देता है। इससे यूज़र तब तक मौजूदा डेटा तक नहीं पहुँच पाता, जब तक कि वह उसे 'अनलॉक' करने के लिये रैनसम (फिरौती) नहीं दे देता। यह फिरौती डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में मांगी जाती है। भुगतान न करने पर डेटा को सार्वजनिक करने या नष्ट करने की धमकी दी जाती है।

रैनसमवेयर निम्नलिखित प्रकार से राष्ट्र की साइबर सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करता है:

- वर्तमान डिजटलीकरण के युग में जब सभी महत्त्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं, ऐसे में यह साइबर सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है।
- देश के महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील संस्थाओं की सूचनाएँ चोरी कर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को क्षति पहुँचाने की संभावना। जैसे इसरो, सेना एवं डीआरडीओ से जुड़ी सूचनाएँ।
- वर्तमान में साइबर वार (WAR) को युद्ध के पाँचवें क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे में रैनसमवेयर हमला अधिक घातक हो सकता है।

जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने से सम्बन्धित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों को फिर से शुरू करना तथा ज्ञान एवं सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने सहित वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय को बढ़ाना एवं मजबूत करना है।
- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों को फिर से शुरू करने तथा ज्ञान और सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने सहित वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

एफपीआई सलाहकार समिति (एफएसी)

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने देश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।

एफपीआई सलाहकार समिति (एफएसी) का गठन और कार्य

- एफपीआई सलाहकार समिति (FAC) की अध्यक्षता पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम करेंगे और इसमें विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी और आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य शामिल होंगे।
- एफएसी को वित्तीय बाजारों में एफपीआई के निवेश और संचालन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने का काम सौंपा गया है, जिसमें भारत में एफपीआई द्वारा व्यापार करने में सुगमता के उपाय शामिल हैं।
- समिति एफपीआई के लिए उपलब्ध निवेश के तरीकों की समीक्षा करेगी और नए निवेश मार्गों की व्यवहार्यता पर सलाह देगी।
- यह बांड बाजार में एफपीआई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपायों का भी सुझाव देगा।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

- जब किसी अन्य देश के निवेशक प्रतिभूतियां या कुछ अन्य वित्तीय संपत्ति खरीदते हैं, तो इसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) कहा जाता है।
- स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर), वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के कुछ उदाहरण हैं।

विदेशी निवेश

- विदेशी निवेशक दो प्रकार से निवेश कर सकते हैं- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआइ)।
- किसी भी दूसरे देश की परियोजना या कंपनी में किया जाने वाला निवेश एफडीआइ है। यह प्रत्यक्ष निवेश होता है और दीर्घावधि के लिए होता है।
- विदेशी कंपनी इसके माध्यम से मेजबान देश की कंपनी में अहम हिस्सेदारी खरीदकर अपनी उपस्थिति दर्ज करती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआइ)

- किसी विदेशी राष्ट्र की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश जैसे स्टॉक या किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध बांड को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- चूंकि पोर्टफोलियो निवेश को आसानी से बेचा जा सकता है। इसलिए इसे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश की अपेक्षा धन सृजन के लिए एक अल्पकालिक प्रयास के रूप में माना जाता है। इस प्रकार के निवेश को कभी-कभी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में कम सकारात्मक रूप से देखा जाता है।
- प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में पोर्टफोलियो निवेश में सामान्यतः परिपक्वता के लिए कम समय होता है।
- पोर्टफोलियो परिसंपत्तियों की तरलता, उन्हें प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में बेचना आसान बनाती हैं, क्योंकि प्रतिभूतियों का व्यापक रूप से कारोबार होता है।
- चूंकि वे प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में काफी कम निवेश नकदी और उचित परिश्रम की मांग करते हैं, विशिष्ट निवेशक के लिए पोर्टफोलियो निवेश बहुत अधिक किफायती होते हैं।
- प्रत्यक्ष निवेश के विपरीत, निवेशक का उस व्यावसायिक फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें निवेश किया जाता है।
- संपत्ति के एक पोर्टफोलियो में निवेश करना और बंद करना या निष्क्रिय रखना, रिटर्न पाने की उम्मीद के साथ किया जाता है। ये प्रतिभूतियां विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निवेशक के देश के बाहर से मुख्यालय वाले निगमों की इक्विटी या वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें हो सकती हैं।
- होल्डिंग में म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) भी शामिल हैं, जो विदेशी या अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों में निवेश करते हैं, साथ ही इन व्यवसायों या विदेशी सरकारों द्वारा जारी बांड या अन्य ऋण भी शामिल हैं।
- एक व्यक्तिगत निवेशक द्वारा अपने देश के बाहर स्थित संभावनाओं में निवेश करने के लिए एफपीआई का उपयोग करने की संभावना अधिक होती है।
- बड़े पैमाने पर, किसी देश का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश उसके पूंजी खाते (बीओपी) के हिस्से के रूप में उसके भुगतान संतुलन पर प्रतिबिंबित होता है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश व्यक्तियों, कंपनियों या यहां तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा भी किया जा सकता है। इस तरह के निवेश से उद्यमियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़त मिलती है।

ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड

- एफडीआइ का स्वरूप कई प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के लिए 'ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड'।
- जब एक विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर अपना नया कारखाना स्थापित करती है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैसेलिटी बनाती है या नया स्टोर शुरू करती है तो उसे 'ग्रीनफील्ड' एफडीआइ कहते हैं।
- वहीं जब विदेशी कंपनी भारत में नया कारखाना लगाने के बजाय पहले से ही संचालित कारखाने या ब्रांड में हिस्सेदारी खरीदकर या अधिग्रहण कर उसके प्रबंधन पर अपना नियंत्रण हासिल कर लेती है तो उसे 'ब्राउनफील्ड' एफडीआइ कहते हैं।

ऑटोमेटिक रूट या गवर्नमेंट रूट

- विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों में दो रास्तों से निवेश कर सकते हैं- ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट।
- ऑटोमेटिक रूट के तहत विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति नहीं लेनी होती है। इसमें सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है, जिनका उल्लेख विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के नियमों के तहत किया गया है।

- दूसरी ओर जो क्षेत्र ऑटोमेटिक रूट के दायरे में नहीं आते, उनमें निवेश के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, इसलिए इस व्यवस्था को गवर्नमेंट रूट के तौर पर जाना जाता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लाभ

- यह एफपीआई निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम बनाता है।
- यह विदेशी देशों में ऋण तक पहुंच प्रदान करता है।
- यदि किसी निवेशक के पास अपने देश की तुलना में अधिक मजबूत मुद्रा वाले किसी विदेशी देश में एफपीआई है, तो दोनों देशों के बीच विनिमय दरों में अंतर से निवेशक को लाभ हो सकता है।
- खुदरा निवेशकों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विकल्प संभव है, क्योंकि धन की राशि एफडीआई की तुलना में बहुत कम है और इसमें सामान्य रूप से सरल वैधता शामिल है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफडीआई की तुलना में जल्दी रिटर्न देते हैं।
- मूल रूप से, निवेशक अपने पोर्टफोलियो निवेश को उस परिसंपत्ति की मौजूदा कीमतों पर बिना किसी बाध्यता के बेच सकता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से जुड़ी चुनौतियाँ

- एफडीआई के विपरीत, एफपीआई में निवेशक का उस फर्म या व्यावसायिक इकाई के प्रबंधन या कामकाज पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसकी संपत्ति खरीदी जाती है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए अधिक अस्थिर हैं और इस प्रकार उनकी संपत्ति की कीमतों में हर समय उतार-चढ़ाव होता है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एक विश्वसनीय विकल्प नहीं है, क्योंकि यह शीघ्रता से बेचने या व्हेल/शार्क की बिक्री के लिए प्रवण होता है, जिससे परिसंपत्ति की कीमत कम हो जाती है और बड़े पैमाने पर धन की कमी हो जाती है जो अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकती है।

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस और सहकारी समितियां Eco

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर सहकारिताओं की ऑनबोर्डिंग को ई-लॉन्च किया।
- ज्ञातव्य है कि पोर्टल पर 300 सहकारी समितियों की शुरुआत की गई।
- प्रथम चरण में, सभी पात्र सहकारी समितियां, जिनका टर्नओवर या जमा राशि 100 करोड़ रूपए है, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पर ऑर्डर देने के पात्र होंगे।
- विदित है कि सहकारी समितियों को GeM प्लेटफॉर्म पर स्वयं को विक्रेता के रूप में पंजीकृत करने के लिए भी कहा गया था।
- यह अपने उत्पादों को सरकारी खरीदारों के एक बड़े पूल के रूप में विक्रय हेतु एक बड़ा मंच प्रदान करेगा।
- मंत्री ने सहकारिताओं से कहा है कि वे अपनी चुनाव प्रक्रिया, भर्ती और खरीद गतिविधियों में पारदर्शिता लाकर खुद को बदलें।
- इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला गया। इनमें शामिल हैं:
  - एक नई सहकारी नीति तैयार करना, प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करना और निर्यात गृहों की स्थापना करना।

सहकारिता क्या हैं?

- सहकारिताएं को जन-केंद्रित उद्यम के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- इनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- सहकारी समितियों के सिद्धांतों में शामिल हैं - स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी आदि।

सहकारी समिति से आशय

- सहकारी समिति सामान्य तौर पर वंचितों या कमजोर वर्गों द्वारा गठित एक स्वैच्छिक संगठन है।
- यह एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक संघ है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों के लिए कार्य करना है।
- इस तरह के समिति का निर्माण समान लक्ष्य वाले समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा किया जाता है।

सहकारिताओं का विनियमन

- "सहकारी समितियां" राज्य सूची का विषय है।
- यद्यपि, यह बहुराज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 द्वारा विनियमित होती हैं।
- राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी बहुराज्य सहकारी समितियों पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है।
- 2002 में, तत्कालीन सरकार ने सहकारी समितियों के प्रचार और विकास का समर्थन करने के लिए सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की।
- केंद्र सरकार शीघ्र ही नई सहकारी नीति लाने की योजना बना रही है।
- जुलाई 2021 में, देश में सहकारी समितियों के लिए सहयोग का एक नया मंत्रालय बनाया गया था।
- इसे 'सहकार से समृद्धि' (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) की दृष्टि से बनाया गया है ।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न संगठनों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है।
- GeM का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद में दक्षता, गति और पारदर्शिता को बढ़ाना है। यह भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य को भी पूरा करता है।
- यह आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (DGS&D) के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
- यह पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम-संचालित ई-मार्केटप्लेस है, जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है।

भारत की 7% से अधिक आबादी के पास डिजिटल मुद्रा : अंकटाड

- संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास संगठन अंकटाड के अनुसार, भारत की 7% से अधिक आबादी के पास 2021 में डिजिटल मुद्रा है, जो जनसंख्या के हिस्से के रूप में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के लिए शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सातवें स्थान पर है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग अभूतपूर्व दर से बढ़ा है।
- प्रतिवेदनानुसार, यूक्रेन 12.7% के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद रूस 11.9%, वेनेजुएला 10.3%, सिंगापुर 9.4%, केन्या 8.5% और अमेरिका 8.3% के साथ शीर्ष पर है।
- वर्ष 2021 में सात प्रतिशत से अधिक भारतीयों के पास डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी के रूप में) थी।
- रिपोर्ट में, भारत सूची में सातवें स्थान पर है। वर्ष 2021 में कम से कम 7.3 प्रतिशत भारतीयों के पास क्रिप्टोकरेंसी थी।
- शीर्ष स्थान युद्धग्रस्त यूक्रेन का है, जिसमें 12.7 प्रतिशत लोग क्रिप्टोकरेंसी के स्वामी हैं।
- रूस 11.9 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर था।
- वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका छठे स्थान पर था।
- अंकटाड के अनुसार, डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के कुछ अनुमानों के दृष्टिगत, वर्ष 2021 में इस क्षेत्र की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में से 15 उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थीं।
- रिपोर्ट में कहा गया कि यद्यपि कुछ लोगों को इन निजी डिजिटल मुद्राओं से लाभ हुआ है और उन्होंने प्रेषण को आसान बना दिया है।
- क्रिप्टोकरेंसी एक अस्थिर वित्तीय संपत्ति हैं, जो सामाजिक जोखिम और लागत भी वहन करती हैं। यदि यह भुगतान के एक सामान्य रूप के रूप में प्रचलित होती है, तो राष्ट्रों की मौद्रिक संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है और यह अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय मुद्राओं को विस्थापित कर सकती है, जिसे क्रिप्टोकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग के कारण

- चूंकि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग मूल्य और गति के संदर्भ में एक आकर्षक चैनल है, जिसके माध्यम से प्रेषण भेजा जाता है।
- महामारी के दौरान, पारंपरिक प्रेषण सेवाओं की पहले से ही उच्च लागत संबंधित व्यवधानों के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान इसके उपयोग में वृद्धि हुई।
- क्रिप्टोकरेंसी, वित्तीय निवेश और अनुमानों के हिस्से के रूप में, मुख्य रूप से विकासशील देशों में मध्यम-आय वाले व्यक्तियों द्वारा आयोजित की जाती है और विशेष रूप से मुद्रा मूल्यह्रास और बढ़ती मुद्रास्फीति (कोविड -19 संकट से ट्रिगर या उच्चारण) का सामना करने वाले देशों में, क्रिप्टोकरेंसी का प्रचलन बढ़ा है।

चिंताए और सुझाव

- हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाले नुकसान और जोखिमों को भी रेखांकित किया है।
- अगर देशों में मुद्रा मूल्यह्रास होता है, तो वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए मौद्रिक अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है।
- यह महत्वपूर्ण रूप से विकासशील देशों में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग हेतु अवैध वित्तीय प्रवाह के लिए एक नया चैनल प्रदान करता है।
- अगर क्रिप्टोकरेंसी को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो यह भुगतान का एक व्यापक साधन बन सकता है और यहां तक कि अनौपचारिक रूप से घरेलू मुद्राओं को भी व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है।

क्रिप्टोकरेंसी

- क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल मुद्रा आभासी रुप से उपयोग की जाती है और किसी भी केंद्रीकृत संस्थान से संबद्ध नहीं है।
- क्रिप्टोकरेंसी अभी भी अपेक्षाकृत नई है और बहुत अस्थिर है।
- क्रिप्टोकरेंसी भौतिक रूप (जैसे पेपर मनी) के रूप में मौजूद नहीं है और यह सामान्य तौर पर केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है।
- यह आमतौर पर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के विपरीत विकेंद्रीकृत नियंत्रण का उपयोग करता है।

अंकटाड (UNCTAD)

- अंकटाड 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इस निकाय का कार्यालय न्यूयॉर्क और अदीस अबाबा में है।
- अंकटाड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है।
- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भी हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)

- हाल ही में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को 31 दिसम्बर, 2024 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।

- ज्ञातव्य है कि इसके तहत पहले से ही स्वीकृत 122.69 लाख आवासों को 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-यू को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)

- प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है, जिसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा किया जा रहा है।
- इसकी शुरूआत 25 जून, 2015 को की गई थी।
- इस मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य झुग्गी-झोपड़ी वासियों के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के लिए आवास की कमी को पूरा करते हुए वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाना है।

पीएमएवाई-यू के मुख्य हितधारक

- पीएमएवाई(यू) एक मांग संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें आवासो की कमी का आकलन राज्यों/ संघ-शासित प्रदेशों द्वारा मांग सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।
- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां (एसएलएनए), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/ कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए), केंद्रीय नोडल एजेंसियां (सीएनए) और प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) मुख्य हितधारक हैं, जो पीएमएवाई (यू) के कार्यान्वयन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी प्राधिकरण शामिल है, जिसे नगरीय नियोजन के कार्य सोंपे गये हैं।
- 'पीएमएवाई-यू : सभी के लिए आवास' भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को बारहमासी पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक अहम कार्यक्रम है।
- यह योजना देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्र, अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित कस्बों को कवर करती है।
- जहां एक ओर भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करते हैं।

चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन

- लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्धन (बीएलसी)
- साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)
- इन-सीटू (स्व-स्थाने) स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)।

मुख्य प्रावधान/महत्व

- पीएमएवाई (यू) के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।
- मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।
- विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वगों को प्राथमिकता दी जाती है।
- पीएमएवाई (यू) आवास लाभार्थियों को सुरक्षा तथा स्वामित्व के गौरव के साथ सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है।
- पीएमएवाई (यू) भौगोलिक स्थितियों, स्थलाकृति, आर्थिक स्थितियों, भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे आदि के आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक कैफेटेरिया दृष्टिकोण को अपनाता है।

योजना के अंतर्गत चार घटक

पृष्ठभूमि और प्रगति

- 2004-2014 की अवधि के दौरान शहरी आवास योजना के तहत 8.04 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया था।
- इस योजना के तहत सभी पात्र शहरी निवासियों को अधिक-से-अधिक संख्या में आवास उपलब्ध कराने के मुद्दे पर फोकस किया गया और 'पीएमएवाई-शहरी' योजना की परिकल्पना की गई।
- वर्ष 2017 में मूल अनुमानित मांग 100 लाख आवासों की थी।
- इस मूल अनुमानित मांग के मुकाबले 102 लाख मकानों का शिलान्यास किया गया/निर्माणाधीन बना दिया गया है। इसके अलावा, इनमें से 62 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- कुल स्वीकृत 123 लाख आवासों में से 40 लाख आवासों के प्रस्ताव राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से देर से (योजना के अंतिम 2 वर्षों के दौरान) प्राप्त हुए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए और दो साल की आवश्यकता है।
- अत: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पीएमएवाई-यू' के कार्यान्वयन की अवधि को 31.12.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- 2004-2014 के 20,000 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत केंद्रीय सहायता 2.03 लाख करोड़ रुपये है।
- 31 मार्च 2022 तक 1,18,020.46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता/सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है और 31 दिसंबर 2024 तक 85,406 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता/सब्सिडी के रूप में जारी किए जाएंगे।
- राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर 31 दिसंबर 2024 तक इस योजना को जारी रखने से बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर कार्यक्षेत्रों के तहत पहले से ही स्वीकृत आवासों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति

- भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापा जाता है, जुलाई के महीने में 5 महीने के निचले स्तर 6.71 प्रतिशत पर आ गई ।
- विदित है कि जून में यह 7.01 प्रतिशत थी।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के माध्यम से मापा गया भारत का कारखाना उत्पादन में जून में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
- फरवरी 2022 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर गिरावट के बावजूद, सीपीआई लगातार सातवें महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 6 प्रतिशत के ऊपरी मार्जिन से ऊपर बना हुआ है।
- सरकार ने केंद्रीय बैंक को मार्च 2026 को समाप्त होने वाली पांच साल की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया है।

- सीपीआई डेटा मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति बनाते समय फैक्टर किया जाता है। बढ़ती मुद्रास्फीति की जांच के लिए, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पिछले हफ्ते रेपो दर को 50 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत कर दिया।
- खुदरा मुद्रास्फीति असुविधाजनक रूप से उच्च बनी हुई है और मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक का मुद्रास्फीति अनुमान 2022-23 में 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।

भारतीय खान ब्यूरो

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुपालन में, खान मंत्रालय ने बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान) के माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को व्यक्तिगत पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी।

पृष्ठभूमि

- विदित है कि अब तक दो डेटा परतें बनाई गई हैं।
- पहली परत में खनिज रियायतों के स्थानिक आंकड़ों को शामिल किया गया है, जिसमें मौजूदा खनन पट्टा और नीलामी के माध्यम से दिए गए मौजूदा मिश्रित लाइसेंस शामिल हैं।
- दूसरी परत में खनिज नीलामी ब्लॉक शामिल हैं, जिनकी सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, लेकिन खनन पट्टे का निष्पादन लंबित है।
- पूरे देश में 297200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले लगभग 3154 खनन पट्टों (नीलामी ब्लॉकों सहित कार्यरत और गैर-कार्यरत दोनों) का स्थानिक डेटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की आवश्यकता

- देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य के दृष्टिगत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गति शक्ति - मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया।
- ज्ञातव्य है कि भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण में समन्वय की कमी सहित कई मुद्दों का सामना करना पड़ा था।
- विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ-साथ सूचना की कमी के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लागत और समय अधिक लगता है।
- यह मुद्दे न केवल सार्वजनिक असुविधा का कारण बना, बल्कि देश को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से भी वंचित कर दिया। इसे संबोधित करने के लिए, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने, वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सभी उपलब्ध और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए।
- अन्य मुद्दों जैसे समय लेने वाली अनुमोदन प्रक्रिया, नियामक मंजूरी की बहुलता आदि के समाधान के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
- इस दिशा में प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम को प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए हितधारकों के लिए समग्र योजना को संस्थागत बनाने के माध्यम से पिछले मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पीएम गति शक्ति छह स्तंभों पर आधारित है:
  - व्यापकता
  - प्राथमिकता
  - अनुकूलन
  - तुल्यकालन
  - विश्लेषिकी
  - गतिशील।
- परियोजनाओं को एक सामान्य दृष्टि से डिजाइन और निष्पादित किया जाएगा।
- इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
- यह बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित इसरो इमेजरी के साथ स्थानिक नियोजन उपकरण सहित प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से लाभ उठाएगा।

भारतीय खान ब्यूरो

- भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी ।
- प्रारंभ में भारतीय खान ब्यूरो को परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करने हेतु स्थापित किया गया था।
- यह विभिन्न नियमों जैसे खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948, खनिज रियायत नियमावली, 1949 और पेट्रोलियम रियायत नियमावली, 1949 को बनाने में सरकार की सहायता करता था।
- 1950 में भारतीय खान ब्यूरो को कार्य किए गए तथा इसके अनुसार खानों का निरीक्षण एवं खनिज संभावनाएं इसके नियमित क्रियाकलाप में शामिल हो गए ।
- 1953 तक भारतीय खान ब्यूरो को खनिज निक्षेपों के विस्तृत अन्वेषण का अतिरिक्त कार्य सौंप दिया गया। लोह अयस्क, चूनापत्थर, डोलोमाइट, कोयला, ताम्र, टंगस्टन भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अन्वेषण खनिज थे।
- बाद में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1955 एवं खनन पट्टे (निबंधों का आशोधन) 1976 बनाए गए ।
- 1955 में दिल्ली में एक अयस्क प्रसाधन प्रयोगशाला की स्थापना की गई ।
- समय के अंतराल में भारतीय खान ब्यूरो के क्रियाकलाप तकनीकी परामर्श एवं खनिज मानचित्रों की तैयारी की सीमा तक बढ़े, जो आगे चलकर खनिज संसाधनों की संपूर्ण सूची तक पहुंची।
- खनन अभियंताओं, भूविज्ञानियों और अयस्क प्रसाधन अभियंताओं के साथ यह खनन उद्योग की विस्तृत और विभिन्न जरूरतों को पूरा करता था ।
- खनन एवं खनिज उद्योगों से संबंधित विभिन्न प्रकाशन निकाले गए ।
- प्रमुख खनन केन्द्रों के नजदीक देश के विभिन्न भागों में कार्यालयों की स्थापना की गई ।
- पिछले दशक में सरकार की नीति में बदलाव के साथ भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया गया। प्रथम कार्य था देश में सभी खानों के लिए खनन योजनाओं एवं खनन स्कीमों का प्रक्रमण एवं अनुमोदन तथा दूसरा कार्य था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों का कार्यान्वयन । भारतीय खान ब्यूरो ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा 'खान पर्यावरण तथा संरक्षण सप्ताह' के माध्यम से खानों की पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा है ।
- भारतीय खान ब्यूरो ने खनन योजनाओं की तैयारी और अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी उद्योग कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया है ।
- आधुनिक खनिज प्रक्रमण प्रयोगशाला, विश्लेष्णात्मक प्रयोगशाला और प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना, नागपुर, अजमेर और बंगलोर में की गई है ।
- भारतीय खान ब्यूरो ने सूचना प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को समझने में देरी नहीं की तथा मुख्यालय और अपने चार आंचलिक एवं 13 क्षेत्रीय कार्यालयों में 'खनिज संसाधन आसूचना प्रणाली' और 'तकनीकी प्रबंधन सूचना प्रणाली' की स्थापना में फ्रांस के बीआरजीएम के साथ करार किया ।
- संक्षेप में, भारतीय खान ब्यूरो खनन उद्योग के सभी वर्गों के बीच सुव्यवस्थित खनन की आवश्यकता और लाभ, खनिजों के संरक्षण तथा पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढाने में सक्षम रहा है।

- इसके अयस्क प्रसाधन जांच के परिणामों ने नए वाणिज्यिक सञ्जीकरण संयंत्रों के आधार का निर्माण किया है तथा इस प्रकार खनिज संसाधन आधार को विस्तार दिया है।
- तकनीकी परामर्श की इच्छा रखने वाले भारतीय खान ब्यूरो के ग्राहक वृन्द छोटे और बड़े खानों तथा अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से आते हैं।
- भारतीय खान ब्यूरो अपने प्रकाशनों के माध्यस से उद्योग को उपयोगी सूचना प्रदान करने में सक्षम हुआ है तथा इसे देश के खान एवं खनिज डाटा बैंक के रूप में मान्यता मिली है।

भारतमाला परियोजना के तहत त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वी के सिंह की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- देश भर में भारतमाला परियोजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के तेजी से विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इसका उद्देश्य माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक्स की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- एमएमएलपी एक माल परिवहन सुविधा होगी जिसमें रेल और सड़क मार्ग से पहुंच होगी, जिसमें कंटेनर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल (थोक, ब्रेक-बल्क), गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, और अन्य संबद्ध सुविधाएं शामिल हैं।
- इसके अलावा, कस्टम क्लियरेंस क्वारंटाइन जोन, परीक्षण सुविधाएं और वेयरहाउसिंग प्रबंधन सेवाओं आदि जैसी मूल्य वर्धित सेवाएं शामिल हैं।
- 'हब एंड स्पोक मॉडल' के तहत विकसित, एमएमएलपी राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के कई मोड को एकीकृत करेगा।
- एनएचएलएमएल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है, जबकि आईडब्ल्यूएआई पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है।
- आरवीएनएल रेल मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

भारत गैस का बीपीसीएल के साथ एकीकरण को मंजूरी

- भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड (बीजीआरएल) को उसकी मूल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ मिला दिया गया है।

- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। यह एकीकरण 16 अगस्त को प्रभावी हुआ।
- बीजीआरएल को जून 2018 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य व्यवसाय गैस सोर्सिंग और खुदरा बिक्री है।
- इसकी स्थापना विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क को लागू करने के लिए की गई थी।
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) एक महारत्न तेल शोधन और विपणन कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

मिथिला मखाना को जीआई टैग

- किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया है।
- मिथिला मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों को अब उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा। मिथिला क्षेत्र के लगभग 5 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
- उत्पाद के जीआई पंजीकरण के कई लाभ हैं जिनमें उस वस्तु के लिए कानूनी सुरक्षा, दूसरों द्वारा अनधिकृत उपयोग के खिलाफ रोकथाम और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।
- भौगोलिक संकेतक (जीआई) एक नाम या संकेत है जो कुछ वस्तुओं पर दिखाई देता है और एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल को संदर्भित करता है।
- वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999, जीआई टैग वाले उत्पादों की सुरक्षा करता है।
- एक बार किसी उत्पाद को यह टैग मिल जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम के तहत वस्तु नहीं बेच सकता है और जीआई टैग 10 साल के लिए वैध होता है।
- जीआई रजिस्ट्री पोर्टल के अनुसार, बिहार में 15 उत्पादों और लोगो को जीआई टैग प्राप्त है। (जून 2022 तक)।

उत्पाद का नाम

- शाही लीची
- सिक्की घास काम
- भागलपुरी जरदालु
- भागलपुर रेशम

- कतरनी चावल
- मगही पानी
- सिलाओ खाजा
- मधुबनी पेंटिंग
- पिपली (खटवा) बिहार का काम
- सुजिनी कढ़ाई का काम
- पिपली (खटवा) काम
- सिक्की घास उत्पाद
- सुजिनी कढ़ाई कार्य
- मंजूषा कला
- मिथिला मखाना

सरकार ने रक्षा बलों को मेक इन इंडिया मार्ग के माध्यम से आपातकालीन हथियार खरीदने की अनुमति दी

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों को मेक इन इंडिया मार्ग के माध्यम से आपातकालीन हथियार खरीदने की अनुमति दी।
- यह रक्षा बलों को आवश्यकता के अनुसार किसी भी नए या सेवाकालीन उपकरण को फास्ट-ट्रैक आधार पर हासिल करने की शक्ति देगा।
- इस श्रेणी के तहत उपकरण 3 महीने से एक वर्ष की समय सीमा के भीतर पहुंचा दिए जाएंगे।
- रक्षा बलों को अपने बजट से धन का उपयोग करना होगा और धन के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
- अतीत में जब भी सशस्त्र बलों को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गईं, तो अधिग्रहण ने उनकी तैयारियों को मजबूत करने में मदद की।
- इन सौदों के तहत हासिल किए गए 'हेरॉन' मानव रहित हवाई वाहन को लद्दाख के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में निगरानी के लिए तैनात किया गया है।
- भारतीय सशस्त्र बलों ने ऐसी मिसाइलें भी खरीदी हैं जो बंकरों जैसे जमीनी लक्ष्यों को लंबी दूरी से मार सकती हैं।
- सशस्त्र बलों के पास इस श्रेणी के तहत खरीदने के लिए उपकरणों की एक लंबी सूची है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

- इस रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में, भारत में बैंकों ने सुशासन मानकों का पालन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- लेकिन, अनुपालन का वर्तमान स्तर, मौजूदा सुशासन संरचना को "सामाजिक रूप से कुशल" के रूप में चिह्नित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- यह रिपोर्ट 2008-09 से 2017-18 तक की प्रत्येक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेट सुशासन पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया गया है।
- इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली 2008-09 से 2012-13 तक मजबूत थी। परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में गिरावट 2013-14 में सामने आई।
- पिछले कुछ वर्षों में निजी बैंकों ने अपनी सुदृढ़ स्थिति में सुधार दिखाया है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए निम्न स्तर की सुदृढ़ता अभी भी एक चुनौती है।
- यह नोट करता है कि शासन और सुदृढ़ता के आयामों पर बैंकों की नीतिगत प्राथमिकताओं में ध्यान देने योग्य विषमताएं मौजूद हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, निजी बैंकों ने लेखापरीक्षा कार्य से संबंधित सुशासन मानदंडों का पालन करने, इसके बाद जोखिम प्रबंधन और बोर्ड की प्रभावशीलता में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया।
- लाभ-कुशल बैंक पूंजी बफर बनाए रखने और झटके को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, जो अस्थिर प्रभाव को कम कर सकते हैं।

तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज अनुदान को मंजूरी

- सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है।
- ब्याज अनुदान में इस वृद्धि के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता है।
- कैबिनेट ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाने को भी मंजूरी दी है।
- कैबिनेट ने पेटेंट आवेदकों और शोधकर्ताओं सहित उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने को भी मंजूरी दी है।

सरकार ने उद्योग के साथ अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए 'मंथन' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

- सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) कार्यालय ने 'मंथन' प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की।
- इसका उद्देश्य उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
- यह एनएसईआईटी द्वारा संचालित है जो हितधारकों के बीच संवाद बढ़ाने में मदद करेगा और अनुसंधान और नवाचार की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह प्लेटफॉर्म ज्ञान हस्तांतरण और आदान-प्रदान सत्रों, प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों में चुनौतियों को साझा करने में मदद करेगा।

- यह देश भर में नई अवधारणाओं, वैज्ञानिक विचारों और नई प्रौद्योगिकी के परिणामों को अपनाने में मदद करेगा।

2021 में, पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं भूखी रहीं: केयर रिपोर्ट

- 3 अगस्त 2022 को जारी केयर रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में पुरुषों की तुलना में 150 मिलियन अधिक महिलाएं भूखी रहीं हैं।
- रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा के बीच अंतर बढ़ गया है।
- 2021 में कुल 828 मिलियन लोग भुखमरी से प्रभावित हुए। यह पाया गया कि 109 देशों में लैंगिक असमानता बढ़ने से खाद्य सुरक्षा में कमी आई है।
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के हर कोने में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में कम भोजन है।
- महिलाएं कम भोजन करती हैं और पुरुषों की तुलना में अधिक बार भोजन छोड़ती हैं। 57 फीसदी पुरुषों की तुलना में 85 फीसदी महिलाएं कम मात्रा में भोजन करती हैं।
- उच्च लैंगिक असमानता वाले देशों में सबसे कम खाद्य सुरक्षा और पोषण है।
- केयर की रिपोर्ट के अनुसार, आपात स्थिति के दौरान महिलाओं को भोजन प्राप्त करने में पुरुषों की तुलना में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- महिला समानता और सशक्तिकरण 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से एक है।

आरबीआई ने डिजिटल उधार के लिए दिशानिर्देशों को जारी किया

- आरबीआई के अनुसार, डिजिटल ऋण सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खातों में, बिना किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से, जमा किया जाना चाहिए।
- आरबीआई ने यह भी कहा कि डिजिटल ऋण देने वाली संस्थाओं को न कि उधारकर्ताओं को क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) को देय शुल्क या शुल्क का भुगतान करना चाहिए।
- आरबीआई ने कहा कि ऋण अनुबंध को निष्पादित करने से पहले उधारकर्ता को एक मानकीकृत मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान किया जाना चाहिए।
- इसने यह भी कहा कि वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) के रूप में डिजिटल ऋण की सभी समावेशी लागत का खुलासा कर्जदारों को करना होगा।
- बैंकों और उनके द्वारा नियुक्त एलएसपी के पास डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक नोडल शिकायत निवारण अधिकारी होना चाहिए।
- नए मानदंड उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में स्वत: वृद्धि की अनुमति नहीं देते हैं।
- आरबीआई ने 13 जनवरी, 2021 को 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार' (डब्ल्यूजीडीएल) पर एक कार्य समूह का गठन किया।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश विभिन्न अनुमेय ऋण सुविधा सेवाओं का विस्तार करने के लिए आरबीआई-विनियमित संस्थाओं और उनके द्वारा नियुक्त ऋण सेवा प्रदाताओं पर लागू होते हैं।
- डिजिटल ऋण देने के लिए अधिकृत लेकिन आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होने वाली संस्थाओं के नियामक / नियंत्रण प्राधिकरण डब्ल्यूजीडीएल की सिफारिशों के आधार पर डिजिटल उधार पर नियम / विनियम तैयार करने पर विचार कर सकते हैं।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सीमा पार से आवक भुगतान स्वीकार करने में सक्षम की जाएगी

- आरबीआई के प्रस्ताव के अनुसार, प्रवासी भारतीय (एनआरआई) बीबीपीएस के माध्यम से भारत में अपने परिवारों के लिए यूटिलिटी, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान कर सकेंगे।
- विकास और नियामक नीतियों पर आरबीआई के द्विमासिक वक्तव्य के अनुसार, बीबीपीएस वर्तमान में केवल भारत के निवासियों के लिए उपलब्ध है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में अपने परिवारों की ओर से एनआरआई को यूटिलिटी, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए बीबीपीएस को सीमा पार से आवक भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव दिया है।
- आरबीआई ने क्रेडिट सूचना कंपनियों को आंतरिक लोकपाल ढांचे के तहत लाने का भी निर्णय लिया है।
- भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित एक भारतीय रिजर्व बैंक की अवधारणा है।
- एनपीसीआई अधिकृत भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करता है। बीबीपीएस पायलट को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था।

पीएम मोदी ने पानीपत में दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया

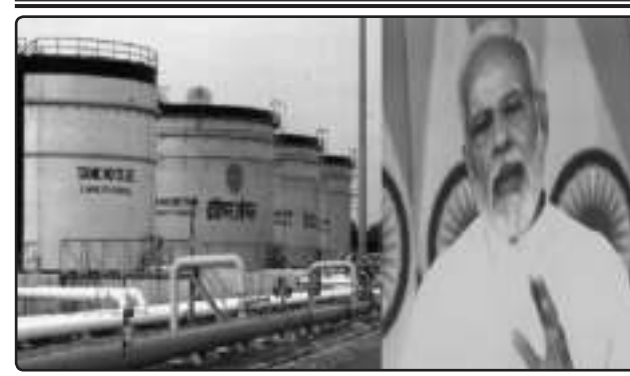

- विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी (2 जी) इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया ।

- यह दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है।
- इसे देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के हिस्से के रूप में बनाया गया है।
- यह संयंत्र लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे (पराली) का उपयोग करके सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करेगा।
- इस परियोजना में शून्य तरल निर्वहन होगा और प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा।
- यह संयंत्र धान के पुआल की कटाई, संभालने, भंडारण आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा।
- सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है।
- इथेनॉल एक जैव ईंधन है जो विभिन्न स्रोतों जैसे स्टार्च, शर्करा और वनस्पति तेलों से बनता है।

भारत का कॉफी निर्यात 2021-22 में 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर

- यह पहली बार है जब भारत का कॉफी निर्यात अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है।
- 2020-21 में, भारत का कॉफी निर्यात मूल्य 734.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि के दौरान कॉफी शिपमेंट में 42% की वृद्धि हुई है।
- भारत हर साल उत्पादित होने वाली कॉफी का लगभग दो-तिहाई निर्यात करता है।
- भारत दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में कॉफी का निर्यात करता है। इटली, जर्मनी, बेल्जियम और रूस भारत से कॉफी के सबसे बड़े आयातक हैं।
- भारत लीबिया, पोलैंड, जॉर्डन, मलेशिया, अमेरिका, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रेलिया को भी कॉफी निर्यात करता है।
- कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। यह भारत में उत्पादित कुल कॉफी का लगभग 70% उत्पादन करता है। केरल और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- अरेबिका और रोबस्टा प्रकार की कॉफी मुख्य रूप से भारत में उत्पादित की जाती है। अपने हल्के सुगंधित स्वाद के कारण, अरेबिका कॉफी का बाजार मूल्य रोबस्टा कॉफी की तुलना में अधिक है।
- ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी निर्यात करने वाला देश है। इसके बाद वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4.90% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया

- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.4% कर दिया। मई 2022 से रेपो रेट में 140 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई है।
- रेपो रेट में वृद्धि से मौजूदा होम लोन ग्राहकों की ईएमआई और उधार दरों में वृद्धि होगी।
- रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई पर काबू पाना है।
- चालू वित्त वर्ष के लिए, आरबीआई ने अपने सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 6.7 प्रतिशत बनाए रखा।
- आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र वैश्विक बाजारों और वैश्विक-राजनीतिक विकास पर निर्भर करेगा।
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.15 प्रतिशत होगी जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 5.65 प्रतिशत रहेगी।
- 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान Q1 - 16.2 प्रतिशत, Q2 - 6.2 प्रतिशत, Q3 - 4.1 प्रतिशत और Q4 - 4 प्रतिशत के साथ 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रहा।
- पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

गन्ना किसानों के लिए अब तक का उच्चतम उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 305 रुपये प्रति क्विंटल स्वीकृत

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने चीनी सीजन 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने की एफआरपी को मंजूरी दे दी है।
- चीनी सीजन 2022-23 के लिए एफआरपी मौजूदा चीनी सीजन 2021-22 की तुलना में 2.6% अधिक है।
- इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और चीनी मिलों और संबंधित गतिविधियों में कार्यरत पांच लाख श्रमिकों को लाभ होगा।
- पिछले आठ वर्षों में, उचित और लाभकारी मूल्य में 34% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- एफआरपी की घोषणा केंद्र सरकार करती है। इसकी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से और चीनी उद्योग संघों से प्रतिक्रिया लेने के बाद की जाती है।

उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के बारे में:

- अक्टूबर 2009 में गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 में संशोधन किया गया।
- गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) को 2009-10 और उसके बाद के चीनी सीजन के लिए गन्ने के एफआरपी से बदल दिया गया था।
- यह बेंचमार्क कीमत है। कोई भी चीनी मिल गन्ना किसानों से इस मूल्य से कम कीमत पर गन्ना नहीं खरीद सकती है।
- कुछ राज्य सरकारें राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की घोषणा करती हैं जो आमतौर पर एफआरपी से अधिक होता है। ये राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु हैं।

जुलाई 2022 में व्यापार घाटा 31 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर

- जुलाई 2022 में, भारत का व्यापार घाटा 31.02 बिलियन डॉलर के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। जुलाई 2021 में व्यापार घाटा 10.63 अरब डॉलर था।
- पिछले वर्ष की तुलना में जुलाई में निर्यात 0.76% घटकर 35.24 बिलियन डॉलर हो गया। आयात 46.2 अरब डॉलर से 43.6% बढ़कर 66.3 अरब डॉलर हो गया।

- पिछले महीने की तुलना में जुलाई में मर्चेंडाइज निर्यात 12.18% गिरा है।
- भारत के पेट्रोलियम निर्यात में पिछले साल की तुलना में 7 फीसदी की कमी आई है। इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में 2.5 फीसदी और हथकरघा उत्पादों में 28.3 फीसदी की कमी आई है।
- व्यापार घाटे के बढ़ने के पीछे उच्च वैश्विक कमोडिटी की कीमतें मुख्य कारक हैं।
- इसने रुपये की एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर पर दबाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रुपया 20 जुलाई 2022 को 80.05 प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया।
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642.45 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर से 70 अरब डॉलर घट गया है।

डीपीआईआईटी द्वारा 75000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई

- भारत ने में 75 हजार से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्यता देकर एक अहम पड़ाव हासिल कर लिया है।
- पिछले 10000 स्टार्टअप को 156 दिनों में मान्यता दिया गया है जबकि शुरुआती दस हजार स्टार्टअप को 808 दिनों में मान्यता मिली है।
- 75 हजार से अधिक स्टार्ट-अप को मान्यता देना आजादी के 75 साल के क्रम में एक मील का पत्थर है।
- प्रति दिन लगभग 80 स्टार्टअप को मान्यता मिल रही है, जो दुनिया में सबसे अधिक दर है।
- स्टार्टअप्स के लिए भारत में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा लगभग 7.46 लाख नौकरियां सृजित की गई हैं और 49% स्टार्टअप टियर II और टियर III शहरों से हैं।
- कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 12% आईटी सेवाओं से, 9% हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज से, 7% शिक्षा से और 5% पेशेवर और वाणिज्यिक सेवाओं से हैं।
- सरकार ने स्टार्टअप्स को फंडिंग से लेकर कर प्रोत्साहन तक में मदद की है।
- सरकार ने सार्वजनिक खरीद और अंतरराष्ट्रीय उत्सवों और कार्यक्रमों में भाग लेने के नियम में ढील दी।

मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक बढ़कर 56.4 हो गया

- वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक का मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर मार्च 2022 में 56.4 हो गया है। एफआई इंडेक्स के सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि देखी गई है।
- आरबीआई ने देश भर में वित्तीय समावेशन की पहुँच को मापने के लिए एक समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था।
- आरबीआई ने मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए अगस्त 2021 में इसे प्रकाशित किया था।

- सूचकांक का निर्माण बिना किसी 'आधार वर्ष' के किया गया है। यह एक ही वैल्यू में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है।
- वैल्यू 0 और 100 के बीच हो सकता है। 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण दिखाता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन दिखाता है।
- इसके तीन व्यापक मानदंड हैं: पहुंच (35 प्रतिशत भारांक के साथ), उपयोग (45 प्रतिशत भारांक के साथ) और गुणवत्ता (20 प्रतिशत भारांक के साथ)।

सही दाम 2.0 ऐप लॉन्च

- एनपीपीए की रजत जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सही दाम 2.0 ऐप लॉन्च किया।
- सही दाम 2.0 ऐप में स्पीच रिकग्निशन (वाक् पहचान), शेयर बटन और दवाओं को बुकमार्क करने जैसी कई नई सुविधाएं हैं।
- उपभोक्ता अब ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- उपभोक्ता एनपीपीए के पूर्व मूल्य अनुमोदन के बिना नई दवा की बिक्री, अनुपलब्धता, दवा की अधिक कीमत, आदि के लिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
- ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों वर्जन में उपलब्ध होगा। यह दवा के एमआरपी (वैट सहित) की जानकारी देगा।
- 'फार्मा सही दाम' दवाओं की खरीद के समय अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों की जांच करने के लिए एक ऑनलाइन सर्च टूल है।
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 29 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में अपनी रजत जयंती मनाई।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल क्रियान्वयन के आठ वर्ष पूर्ण

- प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) 28 अगस्त 2014 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह दुनिया में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है।
- इसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था।

- पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जो बैंकिंग / बचत और जमा खातों, भेजी गई रकम, क्रेडिट, बीमा इत्यादि जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
- पीएमजेडीवाई छह स्तंभों पर आधारित है जिसमें बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को जोड़ना, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
- पहले वर्ष के दौरान, 17.90 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोले गए। 10 अगस्त 2022 तक, कुल पीएमजेडीवाई खाते 46.25 करोड़ थे।
- कुल 46.25 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 37.57 करोड़ (81.2%) चालू हैं। पीएमजेडीवाई के 8.2 फीसदी खाते जीरो बैलेंस वाले खाते हैं।
- पीएमजेडीवाई खातों के तहत कुल जमा शेष राशि रु.1,73,954 करोड़ हैं। प्रति खाता औसत जमा 3,761 रुपये है।
- इसका उद्देश्य अब पीएमजेडीवाई खाताधारकों के बीच रुपे डेबिट कार्ड के उपयोग सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
- इसका उद्देश्य फ्लेक्सी-आवर्ती जमा आदि जैसे माइक्रो निवेश और माइक्रो-क्रेडिट तक पीएमजेडीवाई खाताधारकों की पहुंच को बेहतर बनाना है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी

- रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) ने 780 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट (एलआरयू), उप-प्रणालियों और घटकों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) को मंजूरी दी।
- ये घरेलू उद्योग से खरीदे जाएंगे और यह दो अन्य सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के क्रम में है।
- इससे पहले, एलआरयू, सब-सिस्टम, असेंबली, सब-असेंबली और घटकों की दो अन्य सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में प्रकाशित की गई थीं।
- इन सूचियों में 2,500 आइटम हैं, जो पहले से ही स्वदेशी हैं और 458 (351+107) आइटम हैं जिन्हें दी गई समय-सीमा के भीतर स्वदेशी बनाया जाएगा।
- 'मेक' श्रेणी के तहत विभिन्न मार्गों से आइटम्स का स्वदेशीकरण किया जाएगा।
- एलआरयू/उप-प्रणालियों/घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और डीपीएसयू पर निर्भरता कम होगी।
- डीपीएसयू जल्द ही रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करेंगे।

'वन नेशन वन फर्टिलाइजर' योजना

- केंद्र सरकार ने "भारत" ब्रांड के तहत 'वन नेशन वन फर्टिलाइजर' योजना को लागू किया
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों को 'भारत' के एक ही ब्रांड नाम के तहत बेचने का निर्देश दिया है।
- आदेश के बाद, यूरिया या डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) या म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) या एनपीके युक्त सभी उर्वरक बैग 'भारत' ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे।
- एकल ब्रांड नाम भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके आदि होगा।
- सरकार के निर्देशानुसार खाद की बोरियों पर एकल ब्रांड नाम और प्रधानमंत्री भारतीय जनुवरक परियोजना (पीएमबीजेपी) का लोगो इस्तेमाल किया जाए।
- यह पारगमन समय और माल ढुलाई शुल्क को कम करेगा और पूरे वर्ष उर्वरकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।
- खाद की नई बोरी 2 अक्टूबर से पेश की जाएगी। कंपनियों को अपने पुराने बैग खत्म करने के लिए 12 दिसंबर तक का समय दिया गया है।
- सरकार 26 उर्वरकों पर सब्सिडी देती है और यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य भी तय करती है।

गेहूं या मेसलिन आटा निर्यात नीति संशोधन को मंजूरी

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं या मेस्लिन आटे (एचएस कोड 1101) पर निर्यात प्रतिबंध/रोक से छूट की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- इस मंजूरी से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगना सुनिश्चित होगा और समाज के सबसे कमजोर तबकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- इस आशय की एक अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी की जाएगी।

नीति में संशोधन लाने का कारण:

- रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं, जिनकी कुल वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग एक-चौथाई हिस्सेदारी है।
- उनके बीच संघर्ष ने वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग में वृद्धि हुई है।
- नतीजतन, घरेलू बाजार में भी गेहूं की कीमत में वृद्धि देखी गई।
- देश में 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था।
- हालांकि, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग और भारत से इसके निर्यात में वृद्धि हुई है।

2024-25 तक कोयला उत्पादन को 1.23 अरब टन तक बढ़ाने का लक्ष्य: कोयला मंत्रालय

- कोयला मंत्रालय देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 (सीआईएल और गैर-सीआईएल कोयला ब्लॉकों सहित) तक 1.23 बिलियन टन (बीटी) के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया में है।
- इस विज़न का समर्थन करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने एक एकीकृत योजना का दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि एक अरब टन उत्पादन के लिए निकासी अवसंरचना को मजबूत किया जा सके और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक कोयले का निर्बाध परिवहन हो सके।
- उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र (नार्थ कर्णपुरा कोलफील्ड) झारखंड राज्य का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के प्रबंध-क्षेत्र में आता है और जिसके पास लगभग 19 बिलियन टन कोयला संसाधन का भण्डार है। सीसीएल ने वित्त वर्ष 25 तक लगभग 135 मिलियन टन के उत्पादन योगदान का अनुमान लगाया है, जिनमें से लगभग 85 मीट्रिक टन का उत्पादन उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के आम्रपाली (25 मीट्रिक टन), मगध (51 मीट्रिक टन), चंद्रगुप्त (15 मीट्रिक टन), संघमित्रा (20 मीट्रिक टन) आदि ग्रीनफ़ील्ड/ ब्राउनफ़ील्ड कोयला खनन परियोजनाओं से होने की संभावना है।

- वर्तमान में, उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र से कोयले की निकासी पूर्व मध्य रेलवे की बरकाकाना-डाल्टनगंज शाखा रेलवे लाइन द्वारा कवर की जाती है, जो बरकाकाना लूप के माध्यम से गोमो और डेहरी-ऑन-सोन को जोड़ती है। अतिरिक्त रेलवे लाइन, यानी टोरी-शिवपुर (44.37 किमी) डबल रेलवे लाइन सीसीएल द्वारा बनाई गई है। इसी मार्ग पर तीसरी रेलवे लाइन निर्माणाधीन है, जिसकी अतिरिक्त लागत 894 करोड़ रुपये है तथा जिसके मई, 2023 तक चालू होने की संभावना है।
- इसके अलावा, शिवपुर-कठौटिया, 49 किमी की नई रेल लाइन की परिकल्पना की गई है और इसका निर्माण परियोजना विशेष एसपीवी के गठन के माध्यम से किया जा रहा है, जो कोडरमा के माध्यम से हावड़ा-दिल्ली ट्रंक रेलवे लाइन तक कोयला निकासी के लिए एक और निकास लाइन की सुविधा प्रदान करेगी।
- पीएम-गति शक्ति पहल के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा परिकल्पना की गयी टोरी-शिवपुर-कठौटिया रेल लाइन के निर्माण से रेल द्वारा लगभग 125 एमटी कोयला निकासी क्षमता की सुविधा मिलेगी और सड़क मार्ग से कोयला परिवहन को समाप्त करने में इस लाइन द्वारा प्रमुख भूमिका निभाये जाने की सम्भावना है।

विज्ञान एवं तकनीकी

एसएसएलवी-डी1

- अंतरिक्ष एजेंसी ने सूचित किया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) में मौजूद उपग्रह एसएसएलवी-डी1 द्वारा उन्हें गोलाकार कक्षा की अपेक्षा अंडाकार कक्षा में स्थापित करने के बाद "अब प्रयोग करने योग्य नहीं हैं"।
- एसएसएलवी-डी1, भारत के सबसे छोटे प्रक्षेपण यान का पहला मिशन है, जिसे 7 अगस्त को लॉच किया गया था।
- इसे 356 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया जाना था। यद्यपि, उपग्रहों को इसके बजाय 356 किमी × 76 किमी अण्डाकार कक्षा में रखा गया है।
- इसरो ने कहा कि इस मुद्दे की यथोचित पहचान की गई है और "सेंसर की विफलता की पहचान करने और बचाव कार्रवाई के लिए एक तर्क की विफलता के कारण विचलन हुआ"।
- इसरो विफलता की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा। समिति विश्लेषण और सिफारिश करेगी। सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ इसरो शीघ्र ही एसएसएलवी-डी2 के साथ वापसी करेगा।

विवरण

- एसएसएलवी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से ईओएस-02 नामक एक पृथ्वी अवलोकन सूक्ष्म उपग्रह सहित दो उपग्रहों को ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- अपने तीन चरणों के सफल उत्थापन और पृथक्करण के बाद, उड़ान अपने मार्ग से भटक गई।

एसएसएलवी-डी1 और उद्देश्य

- एसएसएलवी एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस-02 और छात्रों के बनाये एक उपग्रह आजादीसैट लेकर गया है।
- इसरो का उद्देश्य तेजी से बढ़ते एसएसएलवी बाजार का बड़ा हिस्सा बनना है।
- करीब साढ़े सात घंटे की उलटी गिनती के बाद 34 मीटर लंबे एसएसएलवी ने उपग्रहों को निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए सुबह नौ बजकर 18 मिनट पर उड़ान भरी।
- इसरो ने इंफ्रा-रेड बैंड में उन्नत ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का निर्माण किया है।
- ईओएस-02 अंतरिक्ष यान की लघु उपग्रह श्रृंखला का उपग्रह है।
- वहीं आजादीसैट में 75 अलग-अलग उपकरण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 50 ग्राम है।
- देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को इन उपकरणों के निर्माण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया था, जो स्पेस किड्स इंडिया की छात्र टीम के तहत काम कर रही हैं।

एक अतिरिक्त जीन ने चीनी चावल की किस्म की उपज को 40% तक बढ़ा दिया

- साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, स्वयं के जीन में से एक की दूसरी प्रति जोड़ने से चीनी चावल की किस्म की उपज में 40% तक की वृद्धि हुई है।
- एक जीन की दूसरी प्रति के जुड़ने से प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन का अवशोषण बढ़ गया और फूल आने और नाइट्रोजन अवशोषण की प्रक्रिया तेज हो गई।
- इसने पौधे को अधिक उर्वरकों को अवशोषित करने और तेजी से फूलने में मदद की। नतीजतन, इसने चावल की उत्पादकता में सुधार किया।
- एक ही जीन को फिर से जोड़ना आनुवंशिक मॉड्यूलेशन कहलाता है।
- 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद भारत ने प्रति हेक्टेयर चावल की पैदावार में तीन गुना वृद्धि देखी। हरित क्रांति उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर केंद्रित थी।
- लेकिन, पचास वर्षों के बाद, इस पद्धति के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं और पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित कर रहे हैं।
- भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। 2021-22 में भारत ने 150 से अधिक देशों को 18.75 मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया।

उत्तराखंड में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी

- अंतरिक्ष उद्योग में एक स्टार्ट-अप दिगंतारा, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला का निर्माण करेगा।
- यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम होगा।
- भारत अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (एसएसए) वेधशाला की मदद से कक्षीय मलबे से लेकर सैन्य उपग्रहों तक सभी अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम होगा।

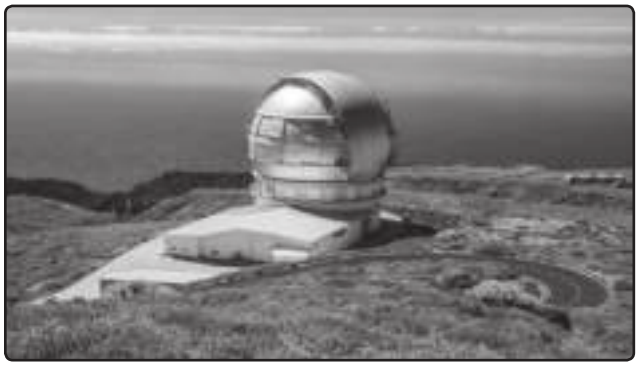

- वर्तमान में, अमेरिका कई स्थानों पर वेधशालाओं और वैश्विक इनपुट प्रदान करने वाली वाणिज्यिक कंपनियों के साथ अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
- उत्तराखंड में वेधशाला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के बीच के क्षेत्र में एसएसए अवलोकनों में अंतर को कम कर देगी जहां ऐसी सुविधाओं की कमी है।

वैज्ञानिकों ने बिना शुक्राणु के दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया

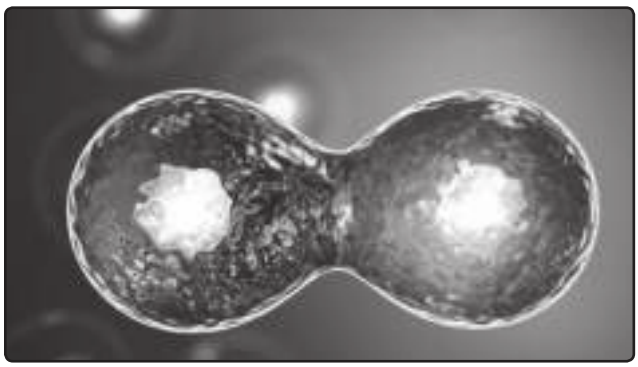

- इज़राइल के वीज़मैन संस्थान के शोधकर्ताओं ने बिना किसी शुक्राणु, अंडे या निषेचन के दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है।
- वैज्ञानिकों ने चूहों की कोशिकाओं से एक सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है।
- प्रारंभ में, शोधकर्ता गर्भ के बाहर कांच के कंटेनरों में माउस भ्रूण उगाए, जिन्हें सीधे असली चूहों से लिया गया था और उन्हें निषेचित किया गया था।
- वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने के बाद सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है कि माउस स्टेम कोशिकाएं प्रारंभिक भ्रूण जैसी संरचनाओं में स्वयं-इकट्ठा हो सकती हैं जिनमें एक आंत्र पथ, एक विकासशील मस्तिष्क और एक धड़कता हुआ दिल होता है।
- सिंथेटिक भ्रूण अपनी आंतरिक संरचना और कोशिकाओं के आनुवंशिक प्रोफाइल के मामले में प्राकृतिक भ्रूण के 95% समान हैं।
- विकसित सिंथेटिक माउस भ्रूण जीवित चूहों में विकसित होने में सक्षम नहीं हैं।
- हालांकि, इस तरह से मानव भ्रूण विकसित करने से पहले और अधिक शोध की आवश्यकता है।

भारत ने अपना पहला स्वदेशी मंकीपॉक्स परीक्षण किट लॉन्च किया

- मंकीपॉक्स रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहला आरटी-पीसीआर किट आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन (AMTZ) में लॉन्च किया गया है।
- केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने किट का अनावरण किया, जिसे ट्रांसएशिया बायो-मेडिकल्स द्वारा विकसित गया है।

- ट्रांसएशिया-एर्बा मंकीपॉक्स आरटी-पीसीआर किट उच्च सटीकता के लिए विशेष रूप से तैयार प्राइमर के साथ एक अत्यधिक संवेदनशील लेकिन सरल परीक्षण है।
- डब्ल्यूएचओ ने मंकीपॉक्स संक्रमण को अंतरराष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।
- यह किट संक्रमण का पहले पता लगाने और बेहतर प्रबंधन में मदद करेगी।

मंकीपॉक्स:

- मंकीपॉक्स (एमपीएक्स) एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें लक्षण चेचक के समान होते हैं।
- हालांकि यह रोग चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर है। यह मंकीपॉक्स वायरस के कारण होता है जो परिवार पॉक्सविरिडे में ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस का सदस्य है।
- इस बीमारी को मंकीपॉक्स कहा जाता है क्योंकि यह पहली बार 1958 में बंदरों की कॉलोनियों में पाया गया था और बाद में 1970 में मनुष्यों में पाया गया था।
- वायरस के लक्षण आमतौर पर 6 से 13 दिनों तक दिखाई देते हैं।

भारत रूस से लंबी दूरी के छह टीयू-160 बमवर्षक लेने की योजना बना रहा है

- रूसी वायुसेना में टीयू-160 को व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है।
- नाटो द्वारा इसका कोडनेम ब्लैकजैक है। यह चार इंजन वाला बमवर्षक है।
- इसकी परिचालन सीमा 12,000 किलोमीटर है। यह मैक 2 या 2,220 किमी/घंटा से अधिक गति प्राप्त कर सकता है।
- यह 40 टन तक पारंपरिक या परमाणु परिचालन भार ले जाने में सक्षम है।
- टीयू-160 लंबी दूरी के बमवर्षकों को रणनीतिक बमवर्षक के रूप में भी जाना जाता है।
- अभी तक, भारत के शस्त्रागार में रणनीतिक बमवर्षक मौजूद नहीं हैं। चीनी वायु सेना के पास जियान एचएस-6के है।
- चीन के अलावा, अमेरिका और रूस केवल दो अन्य देश हैं जिनके पास रणनीतिक बमवर्षक हैं।

- बी-1, बी2 और बी-52 अमेरिकी वायु सेना द्वारा संचालित रणनीतिक बमवर्षक हैं। रूस के पास टीयू-160, टीयू-22एम3एम और टीयू-95एमएस है।
- 2022 तक, टुपोलेव टीयू-160 सबसे बड़ा और सबसे भारी लड़ाकू विमान है। यह उपयोग में सबसे तेज़ बमवर्षक भी है और अब तक उड़ाया गया सबसे बड़ा और सबसे भारी वेरिएबल-स्वीप विंग हवाई जहाज है।

भारत का पहला 3-डी प्रिंटेड कॉर्निया

- आईआईटी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) ने संयुक्त रूप से एक 3डी -प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया विकसित किया और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया।
- यह पहला मेड-इन-इंडिया 3डी प्रिंटेड मानव कॉर्निया है, जो प्रत्यारोपण के लिए ऑप्टिकल और शारीरिक रूप से उपयुक्त है।
- यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें कोई सिंथेटिक घटक नहीं है। इसमें कोई पशु अवशेष नहीं है और उपयोग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है।
- इस 3डी- प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित करने के लिए, आईआईटी हैदराबाद और सीसीएमबी ने मानव आंख से प्राप्त डीसेलुलराइज्ड कॉर्नियल टिशू मैट्रिक्स और स्टेम सेल का उपयोग किया।
- 3डी- प्रिंटेड कॉर्निया में मानव कॉर्नियल ऊतक शामिल है, इसलिए यह जैव-संगत और प्राकृतिक है।
- यह इनोवेशन कॉर्नियल स्कारिंग जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करेगा।
- कॉर्निया आंख की बाहरी परत है जो पुतली और पूर्वकाल कक्ष को कवर करती है। यह प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है।

यूके ओमिक्रोन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना

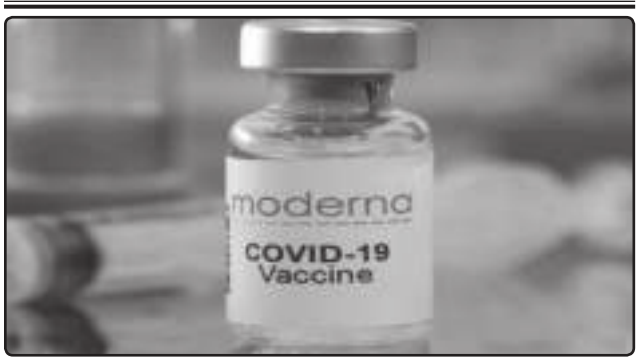

- यूनाइटेड किंगडम के मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मॉडर्ना के "बायवैलेंट" वैक्सीन को सशर्त मंजूरी प्रदान किया है।
- यह वायरस के मूल स्ट्रेन और Omicron BA.1 दोनों को लक्षित करेगा और मूल टीके की तुलना में अधिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करेगा।
- इसका उपयोग 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए किया जाएगा। यूके 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और उच्च नैदानिक रोगियों के लिए अपने बूस्टर खुराक कार्यक्रम में तेजी लाने की योजना बना रहा है।
- टीकों द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा से बचने के लिए SARS-CoV-2 वायरस लगातार उत्परिवर्तित हो रहा है।
- लैंसेट के अनुसार, कोविड-19 टीकों ने अपने उपयोग के पहले वर्ष में लगभग 20 मिलियन मौतों को रोका है।
- ओमिक्रोन कोविड-19 वायरस का एक प्रकार है जो वायरस की सामान्य संरचना में उत्परिवर्तन के कारण उभरा है।

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारम्भ किया

- यह एलईडी लैंप को रोशन करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करती है। लालटेन का नाम रोशनी है।
- डॉ सिंह ने तटीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई द्वारा संचालित एक तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका के भ्रमण के दौरान इसका अनावरण किया।
- उन्होंने भारत के डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।
- उन्होंने जहाज पर भारतीय ध्वज फहराया और 'हर घर तिरंगा' के अभियान का 'हर जहाज तिरंगा' तक विस्तार किया।
- उन्होंने कहा कि सेलाइन वाटर लालटेन भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के किनारे रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए "जीवन की सुगमता" लाएगी।
- उन्होंने कहा कि लालटेन एलईडी बल्बों के वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई उजाला योजना को बढ़ावा देगी।
- उन्होंने यह भी बताया कि लालटेन का उपयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है।
- किसी भी खारे पानी या सामान्य नमक के साथ मिश्रित पानी का उपयोग लालटेन को रोशन करने के लिए किया जा सकता है।

इसरो ने भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय 'स्पार्क' लॉन्च किया।

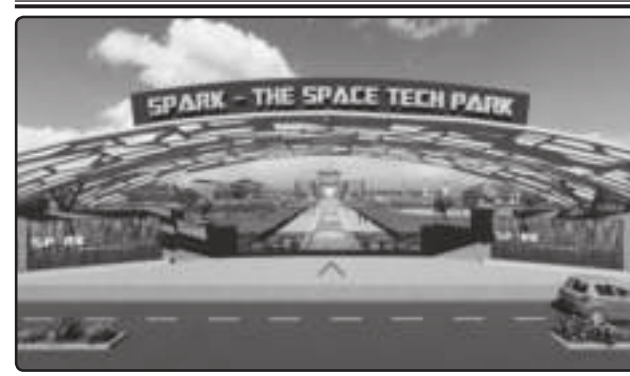

- आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सार्वजनिक उपयोग के लिए स्पेस टेक पार्क (अंतरिक्ष तकनीक पार्क) का शुभारंभ किया।
- इस टेक पार्क में एक संग्रहालय, थिएटर, वेधशाला कैफेटेरिया और खेल अखाड़ा शामिल है।
- 3डी वर्चुअल स्पेस टेक पार्क इसरो के विभिन्न मिशनों से संबंधित डिजिटल कंटेंट को इंटरैक्टिव तरीके से प्रदर्शित करेगा।
- संग्रहालय को उपग्रह गैलरी और प्रक्षेपण यान गैलरी में विभाजित किया गया है।
- टेक पार्क में एक थिएटर भी है जिसमें इसरो के अतीत, वर्तमान और भविष्य के मिशनों से संबंधित वीडियो की एक क्यूरेटेड सूची है।
- उपयोगकर्ता इस प्लेटफॉर्म पर इसरो लॉन्च वाहनों, उपग्रहों और वैज्ञानिक मशीनों से संबंधित विभिन्न दस्तावेज, चित्र और वीडियो को देख सकते हैं।
- स्पार्क में इसरो की 'स्पेस ऑन व्हील्स' पहल भी शामिल है, जिसमें लॉन्च, वाहनों और उपग्रहों के मॉडल ले जाने वाली एक मोबाइल प्रदर्शनी है।

कृषि मंत्री द्वारा स्वदेशी वैक्सीन लम्पी प्रोवैक लॉन्च किया गया

- पशुओं को लम्पी स्किन रोग से बचाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा स्वदेशी वैक्सीन "लम्पी प्रोवैक" लॉन्च किया गया है।
- राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार, हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली के सहयोग से टीका विकसित किया है।
- 2019 में इस बीमारी के भारत में प्रवेश करने के बाद से ही अनुसंधान संस्थान वैक्सीन विकसित करने में लगे हुए हैं।
- श्री तोमर ने कहा कि वैज्ञानिकों ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कम समय में सीमित परीक्षणों के बाद 100% प्रभावी टीकाकरण विकसित किया जो सभी मानकों को पूरा करता है।

लम्पी स्किन रोग:

- यह वायरस "कैप्रीपॉक्सवायरस" के कारण होता है।
- यह आनुवंशिक रूप से वायरस के परिवार से संबंधित है जो गोटपॉक्स और चेचक का कारण बनता है।
- यह मुख्य रूप से मवेशियों और भैंसों को रक्त-पोषक कीड़ों के माध्यम से संक्रमित करता है।
- वजन कम होना, बुखार, मुंह के छाले और दूध उत्पादन में कमी ये सभी लक्षण हैं जो जानवरों में संक्रमण के तुरंत बाद दिखाई देते हैं।
- यह रोग 2012 से अधिकांश अफ्रीकी देशों में स्थानिक है, और मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व यूरोप और पश्चिम और मध्य एशिया में तेजी से फैल रहा है।

पृथ्वी ने अपने मानक समय से 1.59 मिलीसेकंड कम में एक घूर्णन पूरा करके सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड तोडा

- पृथ्वी ने 29 जुलाई को 24 घंटे के अपने मानक घूर्णन से 1.59 मिलीसेकंड कम समय में एक पूर्ण चक्कर पूरा किया।
- पृथ्वी ने 1.47 मिलीसेकंड का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 19 जुलाई 2020 को दर्ज किया गया था।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नोट किया गया है कि हाल के दिनों में पृथ्वी की गति में वृद्धि हुई है।
- पृथ्वी की उच्च गति का मुख्य कारण अभी भी अज्ञात है लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोर की आंतरिक या बाहरी परतों, महासागरों, ज्वार में प्रक्रियाओं या जलवायु परिवर्तन के कारण गति में वृद्धि हुई है।
- कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी की गति में वृद्धि का कारण "चांडलर वॉबल" प्रभाव है, जो कि धुरी पर पृथ्वी के घूमने में परिवर्तन है।
- पृथ्वी आमतौर पर अपनी धुरी पर एक बार घूमने में ठीक 24 घंटे का समय लेती है।
- पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और पांच घंटे लगते हैं।

जर्मनी में दुनिया का पहला हाइड्रोजन-संचालित यात्री ट्रेन बेड़ा लॉन्च किया गया

- दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन के बेड़े में कुल 14 ट्रेनें हैं।
- हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनें गैर-विद्युतीकृत लाइनों पर संचालित 15 पुरानी डीजल ट्रेनों की जगह लेंगी।
- इन ट्रेनों की गति 140 किमी प्रति घंटा होगी और इनकी रेंज 1000 किमी होगी।
- फ्रांसीसी कंपनी एल्सटॉम ने ट्रेनों का निर्माण किया है, और इनका संचालन क्षेत्रीय रेल कंपनी एलएनवीजी द्वारा किया जाएगा।
- ट्रेनें ईंधन के रूप में अक्षय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग करेंगी। इससे सालाना 16 लाख लीटर डीजल की बचत होगी।
- ट्रेनें कम शोर के साथ उत्सर्जन मुक्त हैं और केवल भाप और संघनित पानी को अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न करती हैं।
- परिवहन उद्योग में हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत में रामसर स्थल

- हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है।
- विदित है कि भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई हैं।

रामसर स्थल

- 1971 में ईरान के रामसर में रामसर संधि पत्र पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में से भारत एक है।
- भारत ने 1 फरवरी, 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए।
- 1982 से 2013 के दौरान, रामसर स्थलों की सूची में कुल 26 स्थलों को जोड़ा गया, हालांकि, इस दौरान 2014 से 2022 तक, देश ने रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमि जोड़ी हैं।

पृष्ठभूमि

- इस वर्ष (2022) के दौरान ही कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है।
- रामसर प्रमाण पत्र में अंकित स्थल की तिथि के आधार पर इस वर्ष (2022) के लिए 19 स्थल और पिछले वर्ष (2021) के लिए 14 स्थल हैं।
- तमिलनाडु में रामसर स्थलों अधिकतम संख्या (14) है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में रामसर के 10 स्थल हैं।

11 नए स्थलों में शामिल क्षेत्र

- तमिलनाडु में चार (4)
- ओडिशा में तीन (3)
- जम्मू और कश्मीर में दो (2)
- मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक में एक (1) शामिल हैं।

रामसर स्थलों के रूप में नामित 11 आर्द्रभूमियों का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	आर्द्रभूमि का नाम	राज्य
1.	तंपारा झील	ओडिसा
2.	हीराकुंड जलाशय	
3.	अंशुपा झील	
4.	यशवंत सागर	मध्य प्रदेश
5.	चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य	तमिलनाडु
6.	सुचिन्द्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स	
7.	वडुवूर पक्षी अभयारण्य	
8.	कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य	
9.	ठाणे क्रीक	महाराष्ट्र
10.	हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व	जम्मू और कश्मीर
11.	शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व	
11 स्थलों का कुल क्षेत्र 76316 हैक्टेयर		

रामसर स्थलों के रूप में नामित 11 आर्द्रभूमियों से संबंधित जानकारियाँ

तंपारा झील

- तंपारा झील गंजम जिले में स्थित ओडिशा राज्य की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है।
- यहां की भूमि का क्षेत्र धीरे-धीरे वर्षा जल के प्रवाह से भर गया और इसे अंग्रेजों द्वारा "टैम्प" कहा गया और बाद में स्थानीय लोगों द्वारा इसे "तंपारा" कहा गया।
- आर्द्रभूमि पक्षियों की कम से कम 60 प्रजातियों, मछलियों की 46 प्रजातियों, फाइटोप्लांकटन की कम से कम 48 प्रजातियों और स्थलीय पौधों और मैक्रोफाइट्स की सात से अधिक प्रजातियों का पालन करती है।
- आर्द्रभूमि दुर्लभ प्रजातियों जैसे कि साइप्रिनस कार्पियो, कॉमन पोचार्ड (अथ्या फेरिना), और रिवर टर्न (स्टर्ना औरंतिया) के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है।
- यह आर्द्रभूमि मछलियों के साथ-साथ कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी जैसे प्रावधान की सेवाएं भी उपलब्ध कराती है और यह एक प्रसिद्ध पर्यटन और मनोरंजन स्थल भी है।

हीराकुंड जलाशय

- ओडिशा में सबसे बड़ा मिट्टी के बांध हीराकुंड जलाशय ने कई उच्च संरक्षण महत्व सहित पुष्प और जीव प्रजातियों की एक श्रृंखला का समर्थन करने के लिए 1957 में काम करना शुरू कर दिया था।
- जलाशय से ज्ञात 54 प्रजातियों की मछलियों में से एक को लुप्तप्राय, छह को निकट संकटग्रस्त और 21 मछली प्रजातियों को आर्थिक महत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इस स्थल पर 130 से अधिक पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जिनमें से 20 प्रजातियां उच्च संरक्षण महत्व की हैं।
- हीराकुंड जलाशय प्रचुर मात्रा में पर्यटन को भी बढ़ावा देता है और इसे संबलपुर के आस-पास स्थित उच्च पर्यटन मूल्य स्थलों का एक अभिन्न अंग बनाता है, जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 से अधिक पर्यटक आते हैं

अंशुपा झील

- अंशुपा झील कटक जिले के बांकी उप-मंडल में स्थित ओडिशा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्राचीन काल से इसकी प्रसिद्धि है।
- यह आर्द्रभूमि महानदी नदी द्वारा बनाई गई एक ऑक्सबो झील है और 231 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। आर्द्रभूमि पक्षियों की कम से कम 194 प्रजातियों,

मछलियों की 61 प्रजातियों और स्तनधारियों की 26 प्रजातियों के अलावा मैक्रोफाइट्स की 244 प्रजातियों का घर है।

- यह आर्द्रभूमि कम से कम तीन संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों- रिनचोप्स एल्बिकोलिस (ईएन), स्टर्ना एक्यूटिकौडा (ईएन) और स्टर्ना ऑरेंटिया (वीयू) और तीन संकटग्रस्त मछलियों की प्रजातियों- क्लारियस मगर (क्लेरिडे) (ईएन), साइप्रिनस कार्पियो (साइप्रिनिडे) (वीयू) और वालगो एटू (वीयू) को एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है।

यशवंत सागर

- यशवंत सागर इंदौर क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (आईबीए) में से एक है और साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है।
- इस आर्द्रभूमि का जलग्रहण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि है।
- यशवंत सागर को मध्य भारत में दुर्लभ सारस क्रेन का केंद्र माना जाता है।

चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य

- चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से "चित्रांगुडी कनमोली" के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है।
- यह आर्द्रभूमि 1989 से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है, जो तमिलनाडु वन विभाग, रामनाथपुरम डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए एक आदर्श आवास है।

सुचिन्द्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स

- सुचिन्द्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सुचिन्द्रम-थेरूर मनाकुडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है और यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।
- यह एक मानव निर्मित, अंतर्देशीय जलाशय है और बारहमासी है।

वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य

- वडुवूर पक्षी अभयारण्य 112.638 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यह एक बड़ा मानव निर्मित सिंचाई जलाशय और प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय है क्योंकि यह भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।

कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य

- भारत के तमिलनाडु के मुदुकुलथुर रामनाथपुरम जिले के पास कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य 1989 में घोषित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह कई प्रवासी बगुले प्रजातियों के लिए घोंसले बनाने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है
- प्रवासी जलपक्षियों की प्रजनन आबादी अक्टूबर और फरवरी के बीच यहां आती है और इसमें चित्रित सारस, सफेद आइबिस, ब्लैक आइबिस, लिटिल एग्रेट, ग्रेट एग्रेट शामिल हैं।
- यह स्थल आईबीए के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहां स्पॉट-बिल पेलिकन पेलेकैनस फिलिपेन्सिस नस्लों उपस्थिति दर्ज की गई है।

हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व

- हाइगम वेटलैंड झेलम नदी बेसिन के भीतर आता है और स्थानीय समुदायों के लिए बाढ़ अवशोषण बेसिन, जैव विविधता संरक्षण स्थल, पर्यावरण-पर्यटन स्थल और आजीविका सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- आर्द्रभूमि बारामुला जिले में स्थित है। यह कई निवासियों और प्रवासी पक्षी प्रजातियों के निवास के रूप में कार्य करता है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व

- शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है।
- यह कम से कम 21 प्रजातियों के चार लाख से अधिक स्थानिक और प्रवासी पक्षियों के आश्रय के रूप में कार्य करता है।
- शालबुग वेटलैंड प्राकृतिक नियंत्रण, सुधार या बाढ़ की रोकथाम में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, यह आर्द्रभूमि या डाउनस्ट्रीम संरक्षण महत्व के अन्य क्षेत्रों के लिए मौसमी जल प्रतिधारण के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- शालबुग वेटलैंड अत्याधिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है, इनमें मछली और फाइबर, जल आपूर्ति, जल शोधन, जलवायु विनियमन, बाढ़ विनियमन, मनोरंजन के अवसर शामिल हैं। आर्द्रभूमि जलपक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल के रूप में भी कार्य करती है।

महत्व

- इन स्थलों को नामित करने से इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

रामसर स्थल

- 1971 में ईरान के रामसर में रामसर संधि पत्र पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में से भारत एक है।
- भारत ने 1 फरवरी, 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए।
- 1982 से 2013 के दौरान, रामसर स्थलों की सूची में कुल 26 स्थलों को जोड़ा गया, हालांकि, इस दौरान 2014 से 2022 तक, देश ने रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमि जोड़ी हैं।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट

- हाल ही में, प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार; नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई पीएम 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।
- ज्ञातव्य है कि नई दिल्ली और कोलकाता क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं, जबकि मुंबई सूची में 14 वें स्थान पर है।

दो प्रमुख वायु प्रदूषक

- इस अध्ययन में पाए गए दो प्रमुख वायु प्रदूषकों पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) के आधार पर शहरों की रैंकिंग की गई है।
- PM2.5, 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का वायुमंडलीय कण है , जो मानव बाल के व्यास का लगभग 3 प्रतिशत है। यह सांस की समस्याओं का कारण बनता है और दृश्यता को कम करता है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- 2010 से 2019 के डेटा का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में पाया गया कि दो प्रमुख वायु प्रदूषकों (पीएम 2.5 और एनओ 2) के संपर्क में आने के लिए वैश्विक पैटर्न आश्चर्यजनक रूप से भिन्न थे।
- पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 कण प्रदूषक की एक श्रेणी को संदर्भित करता है, जो 2.5 माइक्रोन या आकार में छोटा होता है।
- पीएम 2.5 को मानव स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वे हमारे शरीर की कई सुरक्षा (नाक के बाल, बलगम) को बायपास करते हैं और हमारे फेफड़ों में जा सकते हैं, जहां से वे अंततः रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं।

- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) एक गैसीय वायु प्रदूषक है, जो उच्च तापमान पर कोयला, तेल, गैस या डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने पर बनता है।
- चूंकि शहर के निवासी अत्यधिक यातायात वाली व्यस्त सड़कों के करीब रहते हैं, इसलिए वे सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की तुलना में अधिक NO_2 प्रदूषण के संपर्क में आते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, जबकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्थित शहरों में PM2.5 प्रदूषण का जोखिम अधिक होता है, NO_2 का जोखिम उच्च आय वाले शहरों के साथ-साथ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अधिक है।
- रिपोर्ट में पाया गया कि अधिकांश वैश्विक शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वायु प्रदूषण दिशा-निर्देशों से कहीं अधिक हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहे हैं।
- 2019 में, विश्लेषण किए गए शहरों में से 86% ने WHO के 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) NO_2 के लिए दिशा-निर्देश की सीमा को पार कर लिया, जिससे लगभग 2.6 बिलियन लोग प्रभावित हुए।
- 2019 में जनसंख्या-भारित NO_2 एक्सपोज़र के मामले में शीर्ष 20 में कोई भारतीय शहर नहीं था। शंघाई, मॉस्को और तेहरान इस सूची में शीर्ष तीन शहर हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में सबसे अधिक जनसंख्या-भारित वार्षिक औसत PM2.5 एक्सपोजर दिल्ली में 110 µg / m^3 था, इसके बाद कोलकाता में 84 µg / m^3 था।
- पीएम2.5 में सर्वाधिक वृद्धि वाले 50 शहरों में से 41 भारत में हैं, जिनमें 9 इंडोनेशिया में हैं।
- दूसरी ओर, 2010 से 2019 तक PM2.5 प्रदूषण में सबसे अधिक कमी वाले सभी 20 शहर चीन में हैं।

विश्व के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों (पीएम2.5) की सूची, जहां पीएम2.5 का स्तर µg/m3 है:

1.	दिल्ली, भारत	(110)
2.	कोलकाता, भारत	(84)
3.	कानो, नाइजीरिया	(83.6)
4.	लीमा, पेरू	(73.2)
5.	ढाका, बांग्लादेश	(71.4)
6.	जकार्ता, इंडोनेशिया	(67.3)
7.	लागोस, नाइजीरिया	(66.9)
8.	कराची, पाकिस्तान	(63.6)
9.	बीजिंग, चीन	(55)
10.	अकरा, घाना	(51.9)
11.	चेंगदू, चीन	(49.9)
12.	सिंगापुर	(49.4)
13.	आबिदजान, आइवरी कोस्ट	(47.4)
14.	मुंबई, भारत	(45.1)
15.	बमाको, माली	(44.2)
16.	शंघाई, चीन	(40.1)
17.	दुशांबे, ताजिकिस्तान	(39.7)
18.	ताशकंद, उज़्बेकिस्तान	(38)
19.	किंशासा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	(35.8)
20.	काहिरा, मिस्र	(34.2)

द एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट

- स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर द्वारा प्रकाशित, द एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट, यूएस-आधारित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (HEI) और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के मध्य एक सहयोग है।

ग्रीनलैंड में घोंघा मछली का अस्तित्व संकट में

- घोंघा मछली आर्कटिक के बर्फीले पानी में जीवित रह सकती है क्योंकि इसके रक्त में एंटीफ्रीज़ प्रोटीन मौजूद होते हैं।
- ये एंटीफ्रीज़ प्रोटीन बर्फ के क्रिस्टल को इसकी कोशिकाओं में जमा होने से रोकते हैं।
- शोधकर्ताओं ने घोंघा मछली के बायोफ्लोरेसेंट गुणों की जांच के दौरान एंटीफ्रीज़ प्रोटीन की खोज की।
- आर्कटिक क्षेत्र में लंबे समय तक अंधेरा रहने के कारण आर्कटिक की मछलियों में बायोफ्लोरेसेंस शायद ही कभी पाया जाता है।
- एकमात्र ध्रुवीय मछली जिसे बायोफ्लोरेसेंस प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है, वह घोंघा मछली है।
- नीले प्रकाश को हरे, लाल या पीले प्रकाश में बदलने की जीव की क्षमता को बायोफ्लोरेसेंस के रूप में जाना जाता है।
- यदि आर्कटिक समुद्री बर्फ में गिरावट इसी दर से जारी रही, तो अगले तीन दशकों के भीतर आर्कटिक महासागर गर्मियों के दौरान ज्यादातर बर्फ मुक्त हो जाएगा।

भारत और श्रीलंका में लंबी उँगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज

- इसे डब्ल्यू डब्ल्यू ए फिलिप्स के नाम पर मिनिओप्टेरस फिलिप्सी नाम दिया गया है।
- डब्ल्यू डब्ल्यू ए फिलिप्स श्रीलंका और दक्षिण एशिया के स्तनधारियों पर अध्ययन में योगदान के लिए प्रसिद्ध है।

- इस प्रजाति के नमूने श्रीलंका में उवा प्रांत में इदुल्गाशिन्ना गुफा से एकत्र किए गए और भारत के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में जमा किए गए।
- इस खोज को एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका एक्टा चिरोप्टरोलोगिका में प्रकाशित किया गया है।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि इस प्रजाति के लंबे उँगलियों वाले चमगादड़ भारत के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर में रॉबर की गुफा में पाए जाते हैं।
- शोधकर्ताओं ने नई प्रजातियों की रूपात्मक और शारीरिक विशेषताओं का भी विश्लेषण किया है।
- लंबी उँगलियों वाले चमगादड़ मिनीओप्टरिडे परिवार से संबंधित है और दुनिया भर में इसकी 40 प्रजातियां हैं।
- लंबी उँगलियों वाले चमगादड़ बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं और गुफाओं और सुरंगों में पाए जाते हैं।
- इस शोध में विभिन्न देशों के 13 प्रसिद्ध वैज्ञानिक शामिल थे।

भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया।
- स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को केपीआईटी-सीएसआईआर द्वारा विकसित किया गया है।
- ईंधन सेल बस के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है और केवल पानी को अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न करता है।
- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा का एक उत्कृष्ट स्रोत है और यह रिफाइनिंग, उर्वरक और इस्पात उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन में मदद करेगा।
- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीएसआईआर-एनसीएल में बिस्फेनॉल-ए पायलट प्लांट का भी उद्घाटन किया।
- हाइड्रोजन ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। हाइड्रोजन आधारित वाहन की परिचालन लागत डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में कम होती है।
- लगभग 12-14% कार्बन डाइआक्साइड (CO2) उत्सर्जन और कण उत्सर्जन डीजल से चलने वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों से उत्पन्न होते हैं।
- हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे और 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2.5 से 3 बिलियन टन तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

दुनिया के 20 शहरों में से 18 शहर जहां PM 2.5 प्रदूषण में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, वे भारत से हैं: एचईआई अध्ययन

- स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान (एचईआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में, दिल्ली में PM2.5 का उच्चतम औसत स्तर है।
- 2010 से 2019 तक, सूक्ष्म कण प्रदूषकों (PM2.5) में सबसे अधिक वृद्धि वाले 20 शहरों में से 18 भारत से हैं।
- यह रिपोर्ट दो सबसे हानिकारक प्रदूषकों पर केंद्रित है: सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2)।
- इस रिपोर्ट में दुनिया भर के शहरों के लिए हवा की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए उपग्रहों और मॉडलों के साथ जमीन आधारित वायु गुणवत्ता डेटा को जोड़ा गया है।
- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 7,239 शहरों में PM2.5 के संपर्क में आने से 17 लाख मौतें हुई हैं। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों से एशिया, अफ्रीका और पूर्वी और मध्य यूरोप सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- भारत और इंडोनेशिया में PM2.5 प्रदूषण में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है।
- PM2.5 में सबसे अधिक वृद्धि वाले 50 शहरों में से 41 भारत से हैं और 9 इंडोनेशिया से हैं।
- 2010 से 2019 के बीच पीएम2.5 प्रदूषण में सबसे अधिक गिरावट वाले 20 शहर चीन से हैं।
- भारत, नाइजीरिया, पेरू और बांग्लादेश शहर के निवासी वैश्विक औसत से कई गुना अधिक PM2.5 जोखिम का सामना करते हैं।
- दुनिया भर में नौ में से एक मौत के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है।

अगस्त्यमलाई में एक नया हाथी अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा

- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि सरकार तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई में एक नए हाथी रिजर्व को अधिसूचित करेगी।
- यह 1,197 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला होगा। इसे देश के मौजूदा 31 ऐसे ही संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा।
- पिछले तीन वर्षों में, तीन हाथी अभ्यारण्य - कर्नाटक में दांदेली, नागालैंड में सिंगफन और छत्तीसगढ़ में लेमरू को अधिसूचित किया गया है।
- वर्तमान में, हाथी रिजर्व 14 राज्यों में 76,508 वर्ग मीटर में फैला हुआ है।
- हर साल हाथियों द्वारा लगभग 500 लोग मारे जाते हैं और लोगों द्वारा प्रतिशोध में लगभग 100 हाथी मारे जाते हैं।
- विश्व हाथी दिवस 2022 के अवसर पर भूपेंद्र यादव ने मानस टाइगर रिजर्व के महावत दांडेस्वर बोरो को गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया।
- उन्होंने तमिलनाडु के मसालार समुदाय और केरल के महावतों को भी गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया।
- गज गौरव पुरस्कार जंगल और कैप्टिविटी (कैद) में हाथियों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और महावतों के प्रयासों के लिए दिया जाता है।

पर्यावास क्षति और शहरीकरण के कारण, पेनिन्सुलर रॉक आगामा दक्षिणी भारत से गायब

- पेनिन्सुलर रॉक आगामा (समोफिलस डॉर्सालिस) दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की उद्यान छिपकली है।

- पेनिन्सुलर रॉक आगामा आमतौर पर चट्टानी स्थानों और गर्म स्थानों में पाई जाती है। कई पर्यावरणीय कारकों ने शहरी क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति को प्रभावित किया है।

- पेनिन्सुलर रॉक आगामा नारंगी और काले रंग की एक बड़ी छिपकली है। वे अपने शरीर से गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बाहरी स्रोतों से गर्मी की आवश्यकता होती है।
- वे कीड़े खाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- एक अध्ययन के अनुसार बेंगलुरू जैसे शहरों से बहुत सारी वनस्पतियां और जीव-जंतु गायब हो रहे हैं, रॉक अगामा ऐसी ही एक प्रजाति है।
- छोटे जीव और वनस्पति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख संकेतक हैं और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के शोधकर्ताओं द्वारा पेनिन्सुलर रॉक आगामा पर एक अध्ययन किया गया था।

यूएनएफसीसीसी को सूचना दिए जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतन निर्धारित योगदान को मंजूरी

- अद्यतन एनडीसी का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य में भारत के योगदान को बढ़ाना है।
- अद्यतन एनडीसी के अनुसार, भारत 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम कर देगा।
- भारत 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता भी हासिल कर लेगा।
- भारत के मौजूदा एनडीसी का यह अद्यतन संस्करण 2070 तक भारत के नेट-जीरो तक पहुंचने के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

- इससे भारत को कम उत्सर्जन वृद्धि की राह पर चलने में भी मदद मिलेगी।
- यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों के आधार पर, यह देश के हितों और भविष्य की विकास जरूरतों को बनाए रखेगा।
- ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के सम्मेलन के 26वें सत्र में भारत ने दुनिया के सामने अपनी जलवायु कार्रवाई के पांच अमृत तत्व (पंचामृत) पेश किया था।

पेरिस जलवायु समझौता

- इसे 12 दिसंबर, 2015 को पेरिस में COP21 में 196 पार्टियों द्वारा अपनाया गया था।
- यह 4 नवंबर, 2016 को लागू हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे की वृद्धि को सीमित करना है।

पैरालिंपियन राहुल जाखड़ ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2022 डब्ल्यूएसपीएस शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता

- राहुल जाखड़ ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2022 डब्ल्यूएसपीएस शूटिंग विश्व कप में 25 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।
- अवनि लेखरा ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2022 डब्ल्यूएसपीएस शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता।
- पूजा अग्रवाल ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2022 डब्ल्यूएसपीएस शूटिंग विश्व कप में 25 मीटर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।

फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया

- फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
- फीफा ने कहा कि एआईएफएफ को निलंबित करने का कदम "तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव" के कारण उठाया गया है।
- निलंबन के बाद निर्धारित अंडर-17 महिला विश्व कप अब भारत में नहीं होगा।
- मई में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएफएफ को भंग कर दिया और फेडरेशन को संचालित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की।
- समिति का गठन एआईएफएफ के संविधान में संशोधन और 18 महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए किया गया है।
- एआईएफएफ प्रशासन के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद ही निलंबन हटाया जाएगा।
- फीफा के नियमों के अनुसार, सदस्य संघों को किसी भी कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ)

- यह भारत में फुटबॉल का प्रमुख शासी निकाय है।
- इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

तमारा वालकॉट ने 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

- मैरीलैंड की एक महिला पॉवरलिफ्टर तमारा वालकॉट ने स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट को मिलाकर कुल 737.5 किलोग्राम वजन उठाया।
- जुलाई 2022 में, उन्हें वर्जीनिया के मानस में वर्ल्ड रॉ पॉवरलिफ्टिंग फेडरेशन अमेरिकन प्रो में सम्मानित किया गया था।
- तब इस एथलीट ने 680 किलो उठाया था लेकिन एक महीने बाद ही तमारा ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन कर दिया।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

- यह 1955 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है।
- यह मानव उपलब्धियों के विश्व रिकॉर्ड का संकलन है।

44वें शतरंज ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान और यूक्रेन क्रमश: ओपन और महिला वर्ग में चैंपियन बनकर उभरे

- ओपन वर्ग में उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता जबकि आर्मेनिया और भारत-B की टीम ने क्रमश: रजत और कांस्य पदक जीते।
- उज्बेकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया जबकि आर्मेनिया ने स्पेन को हराया।
- महिला वर्ग में यूक्रेन ने स्वर्ण, जॉर्जिया ने रजत और भारत ने कांस्य पदक जीता।
- ओपन सेक्शन में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हराया। डी. गुकेश और निहाल सरीन ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते।
- भारत-A की टीम ने चौथा और अमेरिका ने पांचवां स्थान हासिल किया।
- यह पहली बार है कि शतरंज ओलंपियाड भारत में तमिलनाडु के मामल्लापुरम में आयोजित किया गया।
- पहला महिला ओलंपियाड 1957 में आयोजित किया गया था।

भारत के 75वें ग्रैंडमास्टर बने चेन्नई के वी प्रणव

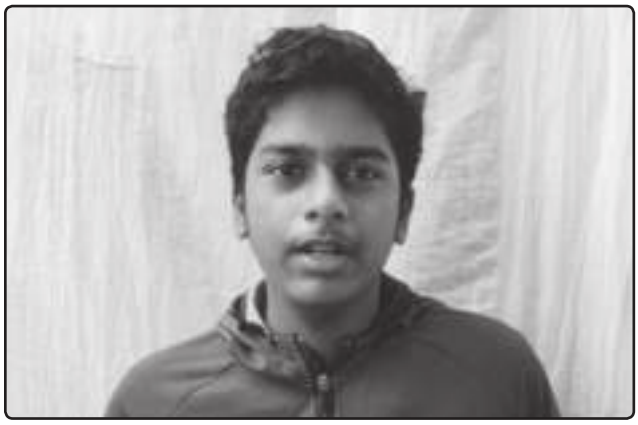

- रोमानिया में टूर्नामेंट जीतकर शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव 7 अगस्त को भारत के 75वें ग्रैंडमास्टर बन गए।
- प्रणव ने अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म हासिल किया और रोमानिया के बाया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया।
- उन्होंने जीएम नॉर्म की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौ राउंड में 7 अंक अर्जित किए।
- प्रणव तमिलनाडु के 27वें ग्रैंडमास्टर हैं, जो इस सूची में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद के साथ शामिल हैं।
- इसके अलावा, उन्होंने 2021 में वर्ल्ड रैपिड इवेंट में कांस्य पदक जीता है और तीन बार राज्य चैंपियनशिप जीती है।

XXII (22वें) राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 पदक प्राप्त किए

- इनमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल हैं।
- राष्ट्रमंडल खेलों में जीते गए कुल पदकों के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा।
- ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण पदक, 57 रजत पदक और 54 कांस्य पदक सहित 178 पदक के साथ खेलों में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- इंग्लैंड ने कुल 176 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। कनाडा 92 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में महिला और पुरुष एकल खिताब जीतकर स्वर्ण पदक जीते।
- सिंधु ने महिला एकल फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को हराया। लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में मलेशिया के त्जे योंग एनजी को हराया।
- पुरुष बैडमिंटन युगल में चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी की जोड़ी ने इंग्लैंड के बेन लेन और सीन वेंडी को हराकर स्वर्ण पदक जीता।
- टेबल टेनिस में, अचंता शरथ कमल ने अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता।
- जी साथियान ने टेबल टेनिस पुरुष एकल का कांस्य पदक जीता।
- भारत की पुरुष हॉकी टीम फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इसने रजत पदक जीता।

भारत ने बांग्लादेश को हराकर U-20 एसएएफएफ चैंपियनशिप जीती

- भारत के गुरकीरत सिंह आठ गोल के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे।
- भारत ने ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में बांग्लादेश को 5-2 से हराया।
- 2022 एसएएफएफ U-20 चैंपियनशिप का चौथा संस्करण था। भारत 2022 एसएएफएफ U-20 चैंपियनशिप का मेजबान था।
- एसएएफएफ U-20 चैंपियनशिप पुरुषों की अंडर-18 राष्ट्रीय टीमों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है।
- यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (एसएएफएफ) द्वारा आयोजित किया जाता है।

भारत ने लॉन बॉल कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

- बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बाउल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ लॉन बाउल्स में यह देश के लिए पहला पदक है।
- रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, पिंकी और नयनमोनी सैकिया की भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराया।
- भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
- भारोत्तलन में विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम वर्ग कुल 346 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता।

राष्ट्रमंडल खेल:

- कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का 22वां संस्करण बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।

- पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किया गया था।
- इस आयोजन की देखरेख कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करता है।
- 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में किया गया था।
- यह हर चार साल में आयोजित किया जाता है।

इंग्लैंड ने अपना पहला यूईएफए महिला यूरो 2022 खिताब जीता

- अतिरिक्त समय के बाद यूरोपीय चैम्पियनशिप के फाइनल में जर्मनी को 2-1 से हराकर इंग्लैंड ने अपना पहला प्रमुख महिला फुटबॉल खिताब जीता।
- जर्मनी के गोल करने में विफल रहने के बाद, क्लो केली ने अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में विजयी गोल किया।
- वेम्बली स्टेडियम में 90 मिनट के बाद खेल 1-1 से समाप्त हुआ।
- जर्मनी के लिए लीना मैगल ने 79वें मिनट में और इंग्लैंड के लिए अल्ला टून ने 62वें मिनट में गोल किया।

यूईएफए यूरोपीय महिला चैम्पियनशिप:

- यह महिला संघ फुटबॉल में मुख्य प्रतियोगिता है, जो हर चार साल में यूईएफए परिसंघ की राष्ट्रीय टीमों के बीच आयोजित की जाती है।
- इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। पहला टूर्नामेंट स्वीडन ने 1984 में जीता था।
- आठ जीत के साथ जर्मनी इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है।

"गेम्स वाइड ओपन" पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा

- पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए साझा नारा "गेम्स वाइड ओपन" होगा।
- 2024 में पेरिस तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। यह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाला है।

- पेरिस ओलंपिक का लक्ष्य सबसे अधिक लिंग-संतुलित ओलंपिक खेल होना है। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लगभग 13 मिलियन टिकट बेचे जाएंगे।
- भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।

ओलंपिक खेल	स्थल
ओलंपिक खेल 2021	टोक्यो (जापान)
ओलंपिक खेल 2024	पेरिस (फ्रांस)
ओलंपिक खेल 2028	लॉस एंजिल्स (संयुक्त राज्य अमेरिका)
ओलंपिक खेल 2032	ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया)

नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में लुसाने डायमंड लीग मीट जीतकर इतिहास रचा

- नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भाला फेंक स्पर्धा जीती।
- नीरज प्रतियोगिता में अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले भारतीय बने।
- नीरज ने डायमंड लीग फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जो 7 और 8 सितंबर को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा।
- उन्होंने अब 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है।
- लुसाने लीग के बाद शीर्ष छह ने ज्यूरिख फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है।
- इस बीच, टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता जैकब वाडलेज 85.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, इसके बाद यूएसए के कर्टिस थॉम्पसन रहे।

यूपी सरकार की भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना

- उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को पांच शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
- शिक्षा टाउनशिप को 'सिंगल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट' के विचार पर विकसित किया जाएगा।
- यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और उन्हें पेशेवर कौशल सिखाने में मदद करेगा।
- यह छात्रों और शिक्षकों को आवास और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगा।
- शिक्षा टाउनशिप न केवल भारत के छात्रों के लिए बल्कि अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और मध्य एशियाई देशों के छात्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी।
- कौशल विकास विश्वविद्यालय शिक्षा टाउनशिप की अनूठी विशेषता होगी। यह युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा।
- टाउनशिप में प्रतिष्ठित सरकारी व निजी विश्वविद्यालय भी अपना कैंपस खोलेंगे।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर 'शेरू' का अनावरण किया

- सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य में 29 अगस्त से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि इसके लिए 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक सभी आयु वर्ग के लिए है। इन खेलों में करीब 30 लाख लोग हिस्सा लेंगे।
- दो लाख टीमें बनाई गई हैं। खेलों का उद्देश्य ग्रामीण खिलाड़ियों की खोज करना और उन्हें आगे लाना है।
- खेलों का उद्देश्य उनकी प्रतिभा को निखारना और आम जनता के बीच खेल भावना को बढ़ावा देना भी है।
- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन 29 अगस्त से 1 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर होगा।
- इसका आयोजन 12 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर किया जाएगा।
- इसका आयोजन जिला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर तक और राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा।
- सीएम गहलोत ने कहा कि सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और उन्हें डीएसपी स्तर तक की नौकरी दी जा रही है।

भारत में पहली नाईट सफारी लखनऊ में शुरू की जाएगी

- राज्य की राजधानी लखनऊ में, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिंगापुर की तर्ज पर एक 'नाइट सफारी' और जैव विविधता पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- कुकरैल वन क्षेत्र में भारत का पहला रात का चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा।
- भारत में 13 'डे सफारी' (दिन की सफारी) हैं लेकिन रात की सफारी नहीं है।
- पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार 2027.46 हेक्टेयर में फैले कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में रात की सफारी की स्थापना की जाएगी।
- जूलॉजिकल पार्क 150 एकड़ में स्थापित किया जाएगा।
- सरकार की योजना 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की है।
- जानवरों को पिंजरों में नहीं रखा जाएगा बल्कि वे जंगल की तरह खुलेआम घूमेंगे।

झारखंड किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना

- कृषि निदेशालय, झारखंड और सेटलमिंट, भारत ने संयुक्त रूप से ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित किसानों को बीज वितरण शुरू करने की घोषणा की।

- सेटलमिंट एक वैश्विक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कंपनी है। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा रहा है।
- कृषि निदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं के तहत आदानों (इनपुट्स), उपकरणों आदि के वितरण को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किए जाने की उम्मीद है।
- ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेन्द्रीकृत, वितरित खाता बही है जो डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड को संग्रहीत करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति-2022 का मसौदा जारी किया

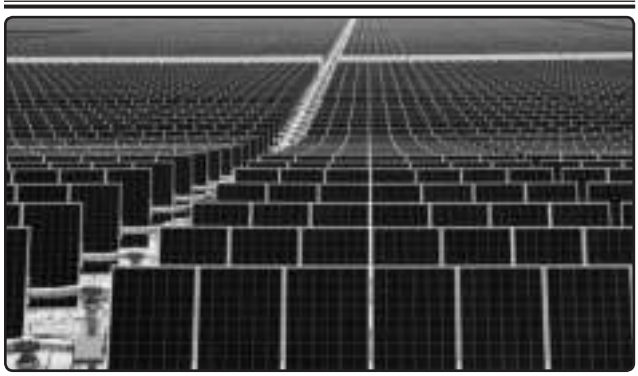

- उत्तर प्रदेश सरकार 2026-27 तक 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना बना रही है।
- प्रस्तावित नीति के अनुसार, राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 20 सौर शहरों का विकास करेगी, जिसमें 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन शामिल होंगे।
- लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद आदि जैसे महत्वपूर्ण शहरों को रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए चुना गया है।
- सौर ऊर्जा नीति-2022 के मसौदे को सौर नीति 2017 के पूरा होने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
- उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2017 ने 2022 तक 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन 3,000 मेगावाट से भी कम का उत्पादन किया गया।
- नई नीति के तहत, परिवार अपने घर से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को वितरण कंपनी को बेच सकते हैं।
- सौर ऊर्जा नीति-2022 के अनुसार, राज्य भर के 21,000 गैर-विद्युतीकृत प्राथमिक विद्यालयों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से कवर किया जाएगा।
- सरकार नगर निगम की संपत्तियों की छत पर भी सोलर पैनल लगाएगी।
- सार्वजनिक संस्थानों जैसे छात्रावासों और प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के एक हिस्से को पूरा करने के लिए कहा जाएगा।
- सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बुंदेलखंड में बंजर / गैर-खेती योग्य सरकारी / निजी भूमि का उपयोग करने की योजना बना रही है।

बिहार के मुख्यमंत्री ने आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया

- विधायिका के 243 सदस्यों के आधार पर, बिहार कैबिनेट में 36 मंत्रियों के लिए जगह है, जिनमें से 31 मंत्रियों ने 16 अगस्त को शपथ ली।
- RJD से 16, नीतीश कुमार की JDU से 11, कांग्रेस से दो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) से एक उम्मीदवार था।
- नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय और चुनाव विभाग अपने पास रखे।
- तेजस्वी प्रसाद यादव को स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, शहरी विकास और ग्रामीण निर्माण विभाग दिया गया।
- विजय कुमार चौधरी को वित्त मंत्रालय मिला, जबकि RJD नेता तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नियुक्त किया गया।
- कांग्रेस के अफाक आलम और मुरारी गौतम भी मंत्री बने।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया

- छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में PESA नियम-2022 लागू करने की घोषणा की।
- PESA अधिनियम के लागू होने से ग्राम सभा की शक्ति में वृद्धि होगी।
- ग्राम सभा में आदिवासी समुदाय के 50% सदस्य होंगे। 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा और ग्राम सभाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय अधिनियम के तहत नियम बनाए हैं।
- राज्य सरकार 15 अगस्त से 26 जनवरी तक ग्राम सभाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाएगी।
- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना ने भी राज्य विशिष्ट PESA नियम बनाए हैं।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम या PESA अधिनियम:

- पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए PESA अधिनियम 1996 में अधिनियमित किया गया था।
- यह अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह जनजातीय समुदायों के स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वशासन करने के अधिकार को मान्यता देता है।

एक सदी पुराने बिहार कॉलेज की खगोलीय प्रयोगशाला को यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया

- यूनेस्को ने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है।
- खगोलीय वेधशाला भीम राव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू) के अधीन है।
- पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली वेधशाला की स्थापना 1916 में इस 123 साल पुराने कॉलेज में छात्रों को विस्तार से खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई थी।
- 1946 में, कॉलेज ने एक तारामंडल भी स्थापित किया, जो शायद भारत में पहला था।
- विश्व धरोहर स्थल वे स्थान/स्मारक/क्षेत्र हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक या किसी अन्य महत्व के कारण विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।
- यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में कम से कम एक बार जून या जुलाई में होती है।

यूपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 'पंचामृत योजना' शुरू की

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'पंचामृत योजना' की शुरुआत की है।

- इस योजना के तहत किसान अतिरिक्त आय के लिए गन्ने के साथ तिलहन, दाल और सब्जियां उगाएंगे।
- योजना का मुख्य उद्देश्य गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना और उत्पादकता और भूमि की उर्वरता को बढ़ाना है।
- इस योजना का उद्देश्य पानी की बचत और गन्ने के ठूंठ और पत्तियों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से लागत को कम करना है।
- यह उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में भी मदद करेगा।
- पंचामृत योजना को लागू करने वाले किसानों को सरकार 'उत्तम गन्ना किसान' पुरस्कार भी देगी।
- सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए कृषि की नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी।

विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनेगा

- अनुमान है कि यह परियोजना 3000 करोड़ रुपये से अधिक की होगी।
- खंडवा में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र (फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट) बनेगा। इससे 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी।
- यह ओंकारेश्वर बांध के पास नर्मदा नदी पर बनेगा।
- मध्य प्रदेश में खंडवा एकमात्र जिला होगा, जहां ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत और सौर ऊर्जा एक साथ होगी।
- भारत की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना अब तेलंगाना में एनटीपीसी- रामागुंडम में पूरी तरह से चालू है।

विविध

महत्वपूर्ण दिवस

इंटरनॉट दिवस: 23 अगस्त

- वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार को चिह्नित करने के लिए 23 अगस्त को दुनिया भर में इंटरनॉट दिवस मनाया जाता है।
- एक "इंटरनॉट" एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे इंटरनेट और उसके इतिहास का उपयोग करने का पूरा ज्ञान है।
- 23 अगस्त उस दिन को चिह्नित करता है जब वर्ल्ड वाइड वेब (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू) को 1991 में पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली द्वारा जनता के लिए खोला गया था।
- टिम बर्नर्स ली एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था।
- उन्होंने पहला वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर भी तैयार किया।
- 1990 में, रॉबर्ट कैइलियौ के साथ, उन्होंने हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट तैयार किया जिसे वर्ल्डवाइडवेब कहा गया।

अक्षय ऊर्जा दिवस 2022: 20 अगस्त

- हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है।
- इस दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी है।
- अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। यह भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
- इस दिन का मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

नोट

- चालू वित्त वर्ष में, राजस्थान और गुजरात ने 31 जनवरी, 2022 तक सबसे अधिक नवीकरणीय क्षमता (क्रमशः 4.8 GW और 2.4 GW) जोड़ी है।
- जून 2022 तक, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 114.07 GW थी। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
- बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के उदाहरण हैं।

विश्व संस्कृत दिवस 2022: 12 अगस्त

- विश्व संस्कृत दिवस हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है।
- वर्ष 2022 में यह दिवस 12 अगस्त को मनाया गया था।
- यह जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है।
- यह पहली बार वर्ष 1969 में मनाया गया था।
- संस्कृत एक प्राचीन भारतीय भाषा है और इंडो-यूरोपीय भाषाओं के समूह से संबंधित है। इसे देववाणी यानी भगवान की भाषा भी कहा जाता है।
- संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और यह भारत में बोली जाने वाली पहली भाषाओं में से एक है।
- 'सुधर्मा' विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र है।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022: 12 अगस्त

- हर साल 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
- यह युवा लोगों और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में उनकी भूमिका का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है।
- हालांकि, इस वर्ष ने केवल युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के लिए सभी पीढ़ियों की कार्रवाई के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय "अंतर पीढ़ीगत एकजुटता: सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना" है।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में युवा मामलों पर मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया।
- यह दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था।
- भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।

विश्व हाथी दिवस 2022: 12 अगस्त

- हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है।
- यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है।
- इस दिन का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है।
- हाथी दुनिया के सबसे बड़े भूमि जानवर हैं।
- 12 अगस्त 2012 को पहला विश्व हाथी दिवस थाईलैंड के एलिफेंट रिइंट्रोडक्शन फाउंडेशन और कनाडा के फिल्म निर्माताओं पेट्रीसिया सिम्स और माइकल क्लार्क द्वारा मनाया गया था।
- भारत में सभी एशियाई हाथियों का लगभग 60% हिस्सा है।
- पिछले 8 वर्षों में हाथी रिजर्व की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
- आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अफ्रीकी हाथियों को असुरक्षित (वल्नरेबल) और एशियाई हाथियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

विश्व शेर दिवस: 10 अगस्त

- विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को शेर संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
- पहला विश्व शेर दिवस 2013 में मनाया गया था।
- विश्व शेर दिवस की स्थापना बिग कैट इनिशिएटिव और नेशनल ज्योग्राफिक के डेरेक और बेवर्ली जौबर्ट ने एक साझेदारी में की थी।
- उनका उद्देश्य शेरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना था।
- आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शेरों को असुरक्षित (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

- गिर वन, गुजरात अफ्रीका के बाहर शेरों की एकमात्र जंगली आबादी का घर है।
- नवीनतम जनगणना (जून 2020 तक) के अनुसार, भारत में एशियाई शेरों की जनसंख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई।
- यह पिछले पांच वर्षों में गुजरात के गिर जंगलों में रहने वाले एशियाई शेरों की आबादी में लगभग 29% की वृद्धि है।

विश्व आदिवासी दिवस 2022: 9 अगस्त

- अंतर्राष्ट्रीय मूलनिवासी दिवस/ विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है।
- यह जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मूलनिवासी दिवस/ विश्व आदिवासी दिवस 2022 का विषय 'पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका' है।
- यह स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह के उद्घाटन सत्र की तारीख को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।
- 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी आबादी पर पहला कार्य समूह बनाया गया था।
- 23 दिसंबर 1994 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मूलनिवासी दिवस के रूप में अपनाया।
- आदिवासी दिवस पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1994 में मनाया गया था। आदिवासी समुदाय के लोग दुनिया के 90 से अधिक देशों में रहते हैं।

नियुक्ति

आईएएस पीयूष गोयल नेटग्रिड के सीईओ नियुक्त

- आईएएस पीयूष गोयल को नेटग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया है, पीयूष गोयल वर्तमान में गृह मंत्रालय (एमएचए) में अतिरिक्त सचिव (एएस) के रूप में कार्यरत थे।
- आशीष गुप्ता को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद नेटग्रिड के सीईओ का पद खाली था।

- अशोक के के मीणा को भारतीय खाद्य निगम (FCI) का सीएमडी नियुक्त किया गया है।
- चंद्र भूषण कुमार को कृषि और किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेटग्रिड)

- 26/11 के हमलों के बाद पहली बार 2009 में इसकी अवधारणा की गई थी। इसे 2010 में मंजूरी दी गई थी।
- यह सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए आव्रजन प्रवेश और निकास, बैंकिंग और संदिग्धों के टेलीफोन विवरण, हवाई और ट्रेन यात्रा विवरण आदि से संबंधित डेटाबेस तक पहुंचने के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- यह 11 केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी, आईबी, रॉ और सभी राज्यों की पुलिस के लिए उपलब्ध है।

जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने

- जस्टिस उदय उमेश ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
- वह वर्तमान सीजेआई, न्यायमूर्ति एनवी रमना के 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद 27 अगस्त को पदभार संभालेंगे।
- अगस्त 2014 में, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वह न्यायमूर्ति एसएम सीकरी के बाद बार से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं।
- न्यायमूर्ति ललित ने सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप में दो कार्यकालों की सेवा की है।
- न्यायमूर्ति ललित, जिनका जन्म 9 नवंबर, 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था, को जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश

- अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- 1993 के दूसरे न्यायाधीशों के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सीजेआई के नाम की सिफारिश करते है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।
- हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।

विश्वनाथन आनंद एफआईडीई के उपाध्यक्ष चुने गए

- भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को खेल की विश्व शासी निकाय अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है।
- अर्कादी ड्वोर्कोविच को दूसरे कार्यकाल के लिए एफआईडीई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।
- एफआईडीई के चुनाव एफआईडीई कांग्रेस के दौरान हुए थे। एफआईडीई कांग्रेस का आयोजन 44वें शतरंज ओलंपियाड के साथ किया जा रहा है।
- एफआईडीई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ या विश्व शतरंज संघ को संदर्भित करता है।
- एफआईडीई अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका गठन 1924 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है।

नल्लाथम्बी कलाइसेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी

- सीनियर साइंटिस्ट नल्लाथम्बी कलाइसेल्वी (Nallathamby Kalaiselvi) वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की पहली महिला महानिदेशक (Director General) बन गई हैं।
- उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।
- वह शेखर मांडे की जगह लेंगी। मांडे अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए थे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश गोखले को सीएसआईआर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
- वह लिथियम-आयन बैटरी के क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वह वर्तमान में तमिलनाडु में सीएसआईआर- सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक हैं।
- वह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव का पद भी संभालेंगी।
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन और एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी।

श्वेता सिंह प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त

- भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) की अधिकारी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक (डायरेक्टर) पद पर नियुक्ति दी गई है।
- वह 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने श्वेता सिंह की नियुक्ति की तारीख से तीन साल के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी।

प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ):

- इसमें भारत के प्रधान मंत्री के तत्काल कर्मचारी के साथ-साथ कई स्तर के सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं जो प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करते हैं।
- पीएमओ को पहले 1977 तक प्रधान मंत्री सचिवालय के रूप में जाना जाता था, और मोरारजी देसाई मंत्रालय के दौरान इसका नाम बदल दिया गया था।
- प्रमोद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रधान मंत्री कार्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं।
- इसका गठन 1947 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार सतर्कता आयुक्त नियुक्त

- राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधान हैं।
- प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने राइट्स लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य किया हैं।
- अरविंद कुमार ने 30 जून, 2019 से 30 जून, 2022 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के 27वें निदेशक के रूप में कार्य किया।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक अध्यक्ष और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं।
- सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।

सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक नियुक्त

- भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश ने प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया।
- श्री प्रकाश भारतीय सूचना सेवा में 1988 बैच के अधिकारी हैं।
- इससे पहले, उन्होंने केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य किया है।
- उन्होंने यूनेस्को, यूनिसेफ और यूएनडीपी सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है।

- उन्होंने इंटरनेट और डिजिटल मीडिया नीति, एफएम रेडियो नीति, डिजिटल सिनेमा नीति, सरकारी विज्ञापन के कंटेंट विनियमन के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के मसौदा दिशानिर्देशों के निर्माण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्हें 2021-22 में मतदाता जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)

- यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है।
- इसका गठन 1919 में हुआ तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

अगस्टे तानो कौमे भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक नियुक्त

- अगस्टे तानो कौमे ने भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक का पदभार संभाल लिया।
- उन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया है।
- इससे पहले, उन्होंने जनवरी 2017 से अप्रैल 2019 तक विश्व बैंक समूह के स्वतंत्र मूल्यांकन समूह (IEG) में मानव विकास और आर्थिक प्रबंधन विभाग के निदेशक के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने विश्व बैंक के मैक्रोइकॉनॉमिक्स और वित्तीय प्रबंधन अभ्यास में अभ्यास प्रबंधक के रूप में कार्य किया।

- वित्त वर्ष 2021-22 में, भारत ने अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) से 3.98 बिलियन डॉलर और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA) से 83 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है।

विश्व बैंक:

- यह 1944 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है।
- यह पूंजी परियोजनाओं के लिए गरीब देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी)

- हाल ही में, सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commission) के रूप में शपथ ग्रहण की।
- विदित है कि सुरेश एन पटेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commission) के पद की शपथ दिलाई।

पृष्ठभूमि

- विदित है कि इससे पूर्व सुरेश एन पटेल कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commission) के रूप में कार्य कर रहे थे।
- आंध्र बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पटेल को अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।
- श्री पटेल की पदोन्नति को प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता (एलओपी) की अध्यक्षता में एक चयन पैनल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सीवीसी की स्थापना

- सतर्कता के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी एजेंसिस को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी,1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की।

सीवीसी की पृष्ठभूमि

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केन्द्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है।
- राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त, 1988 को "सांविधिक दर्जा" देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वर्तमान दर्जा क्या है?

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पारित किया गया तथा राष्ट्रपति ने 11 सितम्बर, 2003 को इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।
- इस प्रकार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 45) उसी तिथि से प्रभावी हुआ।

आयोग की संरचना निम्न है

- एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त- अध्यक्ष
- सतर्कता आयुक्त जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी- सदस्य

क्यो गठन किया गया?

- अप्रैल, 2004 के "लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण" पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरूपयोग करने सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एक "नामित एजेंसी" के रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया है।

भूमिका और कार्य

- **धारा 8 (1) (क)** के अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के कार्यकरण का अधीक्षण करना, जहां तक वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों अथवा लोक सेवकों की कतिपय श्रेणियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी अपराध के अन्वेषण से संबंधित है।
- **धारा 8 (1) (ख)** के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को अधीक्षण के लिए निदेश देना, जहां तक इनका संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराधों के अन्वेषण से है।
- **धारा 8 (1) (ग)** केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ की जांच करना अथवा जांच या अन्वेषण करवाना।
- **धारा 8 (1) (घ)** - केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरूद्ध प्राप्त किसी शिकायत में जांच करना या जांच अथवा अन्वेषण कराना।
- **धारा 8 (1) (ड)** - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अपराध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किए गए अन्वेषणों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना।
- **धारा 8 (1) (च)** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना।
- **धारा 8 (1) (छ)** - केन्द्रीय सरकार तथा इसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना, जो इनके द्वारा आयोग को भेजे जाएंगे।
- **धारा 8 (1) (ज)** विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण रखना।
- **धारा 11** किसी भी जांच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।
- **धारा 19** संघ के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामलों का नियंत्रण करने वाले कोई भी नियम अथवा विनियम बनाने से पहले आयोग से किए जाने अनिवार्य परामर्श पर केन्द्र सरकार को उत्तर देना।
- **धारा 25** केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति के अध्यक्ष हैं तथा दोनों सतर्कता आयुक्त सदस्य हैं, जिसकी सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार, प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है।
- **धारा 25** - प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति को यह अधिकार भी है कि वह प्रवर्तन निदेशालय में उप निदेशक तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, प्रवर्तन निदेशक से परामर्श करने के पश्चात अपनी सिफारिशें दें।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

- अनुभाग 26 तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 (ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, उस समिति के अध्यक्ष हैं तथा दोनों सतर्कता आयुक्त सदस्य हैं, जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों, निदेशक को छोड़कर, अधिकारियों की नियुक्ति तथा इन अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तारण अथवा लघुकरण करने के लिए, निदेशक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) से परामर्श करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें देने का अधिकार प्राप्त है।

डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक (भारत) नियुक्त

- डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक (भारत) के पद पर नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है।
- वह 1 नवंबर, 2022 को इस पद पर अपना कार्यकाल शुरू करेंगे और तीन साल तक रहेंगे।
- डॉ. सुब्रमण्यम डॉ. सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे।
- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. भल्ला को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

- आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है।
- इसकी स्थापना 1945 में हुई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं।

समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त

- समीर वी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें रक्षा अनुसंधान विभाग का सचिव नामित किया गया है ।
- समीर वी कामत डीआरडीओ में नौसेना प्रणाली और सामग्री के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे।
- समीर वी कामत 60 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- जी. सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है।
- नई नियुक्ति से रक्षा अनुसंधान को उद्योग के अनुकूल बनाने और स्थानीय रक्षा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)

- यह भारत में एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- यह रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है।
- इसकी स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन और कुछ तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर की गई थी।
- इसका देश भर में 52 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है।
- यह भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने में शामिल है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

पुस्तकें और लेखक

संजय बारू की नई पुस्तक : "द जर्नी ऑफ ए नेशन: 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी"

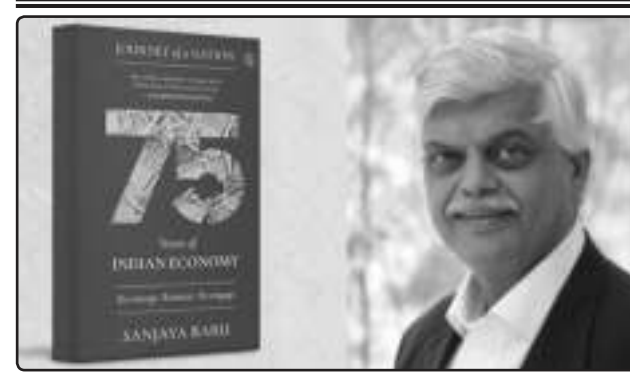

- पुस्तक रूपा पब्लिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है।
- इसका पूर्ण शीर्षक "द जर्नी ऑफ ए नेशन: 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी: री-इमर्ज, रीइन्वेस्ट, री-एंगेज" है।
- यह उस श्रृंखला का एक हिस्सा है जो स्वतंत्र भारत के पिछले 75 वर्षों को देखती है।
- यह ब्रिटिश इतिहासकार एंगस मैडिसन और उनकी पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी: ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव (2001) के संदर्भ से शुरू होता है।
- एंगस मैडिसन की पुस्तक का अनुमान है कि 1700 में, चीन और भारत मिलकर दुनिया की राष्ट्रीय आय का आधा हिस्सा थे।
- मैडिसन की पुस्तक में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 1950 तक, चीन और भारत का संयुक्त हिस्सा 10 प्रतिशत से भी कम हो गया था।

'इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी: ए ब्रीफ हिस्ट्री'

- पुलाप्रे बालकृष्णन द्वारा लिखित 'इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी: ए ब्रीफ हिस्ट्री' का एक अंश 30 सितंबर को जारी किया जाएगा।
- इसे परमानेंट ब्लैक द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।
- इस पुस्तक के अनुसार, नेहरूवादी काल (1950 से 1964) के दौरान वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4% थी। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1.9% थी।

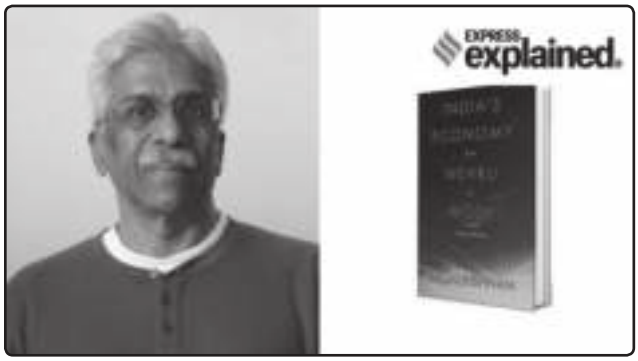

- पुलाप्रे बालकृष्णन ने नेहरूवादी आर्थिक रणनीति की दो प्रमुख आलोचनाएँ कीं। पहला यह कि इसने कृषि की उपेक्षा की और दूसरी आलोचना सार्वजनिक क्षेत्र के "सफेद हाथियों" के निर्माण की है।
- आर्थिक मंदी नेहरूवादी युग के बाद शुरू हुई। 1965-66 में जीडीपी वृद्धि 3.4% से गिरकर 1971-72 में 3.1% हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई, जिसके कारण जून 1966 में 36.5% अवमूल्यन हुआ।
- पुस्तक में 1947 के बाद भारत और चीन की प्रगति की तुलना की गई है।
- भारत में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय कम है।
- विकास के सबसे बुनियादी संकेतकों के मामले में भारत वैश्विक स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है।

पुरस्कार और सम्मान

राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2020 की घोषणा

- सीएसआर विशेषज्ञों और ग्रैंड जूरी ने तीन श्रेणियों में 20 पुरस्कार विजेताओं और 17 सम्मानजनक उल्लेखों का चयन किया।
- राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पुरस्कार उन कंपनियों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी अभिनव और टिकाऊ सीएसआर पहल के माध्यम से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
- ये पुरस्कार भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च सम्मान हैं।
- पहला राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 29 अक्टूबर 2019 को दिया गया।

सीएसआर पुरस्कारों की मुख्य श्रेणियां नीचे दी गई हैं:

- **सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार:** कुल पात्र सीएसआर खर्च के आधार पर एक कंपनी को दिया जाता है।
- **आकांक्षी जिलों/ दुर्गम इलाकों में सीएसआर के लिए सीएसआर पुरस्कार:** आकांक्षात्मक जिलों, दुर्गम इलाकों/अशांत क्षेत्रों, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों आदि में सीएसआर प्रयासों के आधार पर एक कंपनी को दिया जाता है।
- **राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए सीएसआर पुरस्कार:** विजेताओं का चयन राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के योगदान के आधार पर किया जाता है।

वर्ग	विजेता
सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार	
100 करोड़ रुपये के बराबर और उससे अधिक उपयुक्त सीएसआर खर्च करने वाली कंपनियां	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10 करोड़ रुपये के बराबर और 100 करोड़ रुपये से कम खर्च करने वाली कंपनियां	टाटा स्टील लिमिटेड
1 करोड़ रुपये के बराबर और 10 करोड़ रुपये से कम खर्च करने वाली कंपनियां	क्रिसिल लिमिटेड
आकांक्षी जिलों/दुर्गम इलाकों में सीएसआर के लिए सीएसआर पुरस्कार	
उत्तर भारत	आईटीसी लिमिटेड
उत्तर-पूर्व भारत	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पूर्वी भारत	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
पश्चिमी भारत	टाटा कम्युनिकेशंस ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड
दक्षिणी भारत	अवंतेल लिमिटेड
राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए सीएसआर पुरस्कार	
शिक्षा	टाटा स्टील लिमिटेड
कौशल विकास और आजीविका	टेक महिंद्रा लिमिटेड
स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
पर्यावरण, सतत विकास और सौर ऊर्जा	ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड

भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न के 13वें संस्करण में रणवीर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता

- भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न का 13वां संस्करण 12 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ।
- महोत्सव के दौरान भारत की कुछ प्रमुख फिल्में, टीवी शो और वेब सीरीज दिखाई जाएंगी।
- यह 30 अगस्त को समाप्त होगा और व्यक्तिगत कार्यक्रम 20 अगस्त को समाप्त होगा।

- सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार "83" को मिला और इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता।
- शूजीत सरकार (सरदार उधम) और अपर्णा सेन (द रेपिस्ट) ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता।
- जय भीम और गंगूबाई काठियावाड़ी को सबसे अधिक नामांकन मिले लेकिन वे एक भी पुरस्कार जीतने में असफल रहे।

पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार है:

श्रेणी	विजेता
सर्वश्रेष्ठ फिल्म	83
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	शूजित सरकार (सरदार उधम) और अपर्णा सेन (द रेपिस्ट)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	रणवीर सिंह (83)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	शेफाली शाह (जलसा)
सर्वश्रेष्ठ सीरीज	मुंबई डायरीज 26/11
सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	मोहित रैना (मुंबई डायरीज 26/11)
सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	साक्षी तंवर (माई)
सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म	जग्गी
उपमहाद्वीप से सर्वश्रेष्ठ फिल्म	जॉयलैंड
लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड	कपिल देव

यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022

- कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक है।
- कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को 'मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम' के लिए सम्मानित किया जाएगा।
- कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है।
- यह 1993 में एक आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में शुरू हुआ और 2017 में एक डीम्ड-टू-बी-विश्वविद्यालय बन गया।

यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार:

- यह पहली बार 1989 में दिया गया था।
- यह कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- विजेता को एक पदक, एक डिप्लोमा और US$20,000 प्राप्त होता है।
- यह सेजोंग महान के सम्मान में दिया जाता है जिन्होंने कोरियाई वर्णमाला हंगुल को बनाया था।
- यह साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है।

शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

- उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी'होनूर मिलेगा।
- वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वह केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं।
- फ्रांस सरकार उन्हें उनके लेखन और भाषणों के लिए सम्मानित कर रही है।

- 2010 में थरूर को स्पेन की सरकार से भी ऐसा ही सम्मान मिला था।
- स्पेन के राजा ने उन्हें इन्कमेंडा डी ला रियल आर्डर एस्पेनोला डी कारलोस III से सम्मानित किया था।

रामाधर सिंह यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फ़ेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने

- अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर रामधर सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी (एसपीएसपी) की 'हेरिटेज वॉल ऑफ फेम' पर चिह्नित किया गया है।
- यह सम्मान पाने वाले वे भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं।
- ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलंबस ने रामाधर सिंह को 'हेरिटेज वॉल ऑफ फेम' में शामिल करने के लिए नामित किया।
- चीन, भारत, जापान, कोरिया, सिंगापुर और अमेरिका के नौ सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने उनके नामांकन का समर्थन किया है।
- रामाधर सिंह मनोविज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में शोधकर्ता हैं। उन्होंने एशिया में मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने में अहम भूमिका निभाई।

सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को एआईएफएफ फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर चुना गया

- राष्ट्रीय कप्तान सुनील छेत्री को 2021-22 सीज़न के लिए सातवीं बार एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया।
- मनीषा कल्याण को 2021-22 सीज़न के लिए महिला वर्ग में पहली बार फ़ुटबॉलर ऑफ़ द ईयर चुना गया।

- उनके संबंधित राष्ट्रीय टीम के कोच, इगोर स्टिमैक और थॉमस डेननरबी ने छेत्री और कल्याण को नामित किया।
- तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले सक्रिय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी छेत्री को 2007 में पहली बार इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
- बाद में उन्होंने 2011, 2013, 2014, 2017, और 2018-19 में इसे जीता।
- 2020-21 सीज़न के दौरान, मनीषा ने महिला इमर्जिंग फ़ुटबॉलर ऑफ़ द ईयर का पुरस्कार जीता था।

2021-22 सीज़न के लिए एआईएफएफ पुरस्कार:

वर्ग	खिलाड़ी
महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर	मनीषा कल्याण
पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर	सुनील छेत्री
महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ़ द ईयर	मार्टिना थोकचोम
पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ़ द ईयर	विक्रम प्रताप सिंह
बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर	क्रिस्टल जॉन
बेस्ट असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर	उज्जवल हलदर

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार प्रदान किए

- यह पुरस्कार कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना में विभिन्न बैंकों और राज्यों और विभिन्न क्षेत्र के अधिकारियों के योगदान को सम्मानित करता है।
- भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आता है।
- दूसरी श्रेणी में बैंकों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का नंबर आता है।
- लक्ष्य हासिल करने वालों की श्रेणी में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और कर्नाटक बैंक को पुरस्कृत किया गया।
- सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक सर्वश्रेष्ठ रहा।
- इसके बाद मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थान रहा।
- राज्य श्रेणी में, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया।
- पैक्स आवेदनों की मंजूरी में आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई।
- पैक्स आवेदनों के तेजी से निपटान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में, कर्नाटक को सम्मानित किया गया।
- राजस्थान को एआईएफ के तहत उभरता राज्य घोषित किया गया।

एग्री इंफ्रा फंड (कृषि अवसंरचना कोष):

- अगले महीने इसका दूसरा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसे दो साल पहले आत्मानिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था।
- इसे एक समर्पित केंद्र सरकार की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था जो फसल के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान करता है।
- यह ऋण सुविधा सरकार से तीन प्रतिशत ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) शुल्क द्वारा दो करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी के माध्यम से वित्तीय सहायता के साथ आती है।

वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर्स' भेंट किया

- उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति निशान' (प्रेसिडेंट्स कलर्स) प्रदान किया।
- उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए तमिलनाडु पुलिस को पुरस्कार प्रदान किया।
- तमिलनाडु में महिला पुलिस थानों की संख्या सबसे अधिक है और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या दूसरे नंबर पर है।
- महिला कमांडो फोर्स रखने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है। यह देश का एकमात्र राज्य है जिसके पास एक विशेष 'आइडल विंग' है।
- इससे पहले, तमिलनाडु को 2009 में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स मिल चुका हैं।

प्रेसिडेंट्स कलर्स:

- प्रेसिडेंट्स कलर्स किसी भी सैन्य/राज्य पुलिस को उसकी असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
- इसे "राष्ट्रपति का निशान" के नाम से भी जाना जाता है।
- डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को भारतीय नौसेना को पहला "प्रेसिडेंट्स कलर्स" दिया था।

यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

1. मध्य पुरापाषाणकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. इस काल में औजारों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल मात्र क्वार्टजाइट था।
   2. इस काल में मानव के व्यवहार में अधिक विकास दृष्टिगत होता है।
   3. भारत में भीमबेटका व नर्मदा घाटी क्षेत्र इस काल से संबन्धित है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
2. निम्नलिखित में से कौन-से कारण मगध की सफलता के लिए उत्तरदायी थे?
   1. साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास।
   2. लोहे के समृद्ध भंडार उनकी राजधानी से निकट थे।
   3. मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्भेद्य दुर्ग था।
   4. मगध के शासकों ने अपने पड़ोसियों के विरूद्ध बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
3. उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल मुख्य खाद्य फसल थी।
   2. लोगों का तांबे से परिचय इसी काल के अंत में हुआ।
   3. इस काल के लोग उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड से परिचित थे।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
4. हड़प्पा सभ्यता के दौरान व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. व्यापार धन के उपयोग के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था।
   2. वस्तुओं के निर्माण के लिए अपेक्षित कच्चा माल नगरों से ही प्राप्त हो जाता था।
   3. हड़प्पावासियों को समुद्र का ज्ञान नहीं था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी
5. ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था एवं उसे असीमित अधिकार प्राप्त हो गए थे।
   2. चोरी और सेंधमारी जैसी समाज विरोधी हरकतों पर दण्ड देने हेतु न्यायाधिकारी होता था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
6. उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. कर केवल वैश्यों द्वारा चुकाया जाता था।
   2. शूद्र गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था।
   3. स्त्रियों की स्थिति में सामान्यतः गिरावट आयी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी
7. 'गोत्र' शब्द का मूल अर्थ है-
   (a) एक ही मूल पुरूष से उत्पन्न लोगों का परिवार।
   (b) आम कबाइली लोगों को वश में लाकर करदाता बनाने की प्रक्रिया।
   (c) समूचे कुल का अलग-अलग परिवार, जिनका अपना-अपना गोत्र था।
   (d) वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था।
8. प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे?
   1. बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन।
   2. बौद्ध भिक्षुओं का विलासिता पूर्ण जीवन।
   3. छठी-सातवीं सदियों में बौद्धो का क्रूरतापूर्वक दमन।
   4. क्षत्रियों द्वारा बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म से विलगाव।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 2, 3 और 4
9. सूची-I (बुद्ध काल के अधिकारी) को सूची-II (संबंधित कार्य) के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (बुद्धकाल के अधिकारी)	सूची-II (संबंधित कार्य)
(a) शौल्किक	1. राज्य कोषाध्यक्ष
(b) भंडागारिक	2. वसूली करने वाला अधिकारी
(c) बलिसाधक	3. चुंगी लगाने वाला अधिकारी
(d) ग्रामणी	4. कबायली लड़ाकू टोली का नेता

   कूटः

	A	B	C	D
(a)	1	3	2	4
(b)	2	1	4	3
(c)	4	2	1	3
(d)	3	1	2	4

10. शक शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. शकों ने भारी मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए।
    2. शक शासक रूद्रदामन प्रथम ने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया।
    3. शकों द्वारा जारी किए गए सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित हैं।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 2 (d) केवल 1 और 3
11. प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. सर्वप्रथम कुषाण शासको द्वारा बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए गए।
    2. सातवाहनों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के सीसे (लेड) के हैं।
    3. गुप्त शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्णांश वाली स्वर्ण मुद्राएँ जारी की।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी
12. भागवत संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. गुप्तकाल में महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया।
    2. यह सम्प्रदाय मूर्ति पूजक था।
    3. शूद्रों एवं महिलाओं का इस समुदाय में प्रवेश वर्जित था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

13. प्राचीन भारत के सुदूर दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर, सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था।
2. पांड्यो के समाज पर मातृतंत्रात्मक प्रभाव था।
3. मध्यकाल के आरम्भ में चेरो का शासन सम्पूर्ण कोरोमण्डल तट पर था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

14. हाथी गुंफा अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हाथी गुंफा अभिलेख उदयगिरी की गुफाओं में स्थित है।
2. इस अभिलेख का आरम्भ बौद्ध धार्मिक मंत्रों के साथ होता है।
3. यह अभिलेख बाह्मी लिपि में अंकित है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

15. मूर्ति कला की अमरावती शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में हुआ।
2. अमरावती शैली की मूर्तियां चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तरों का उपयोग करके बनाई गई थी।
3. इस शैली की मूर्तियों में बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर अधिक बल दिया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

16. मूर्ति कला शैलियों, गांधार शैली और मथुरा शैली में कौन-सी बात/बातें समान है/हैं?
1. दोनों का विकास कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ।
2. दोनों पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का समान रूप से प्रभाव है।
3. दोनों मूर्तियों के निर्माण में नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का प्रयोग किया गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1 बुद्ध को बांए हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है।
2. हथेली गोद में सीधी एवं दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है?
3. यह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करती है।
उपर्युक्त कथनों में बुद्ध से संबंधित कौन सी मुद्रा का वर्णन किया गया है?
(a) वितर्क मुद्रा (b) धर्म चक्र मुद्रा
(c) उत्तरबोधि मुद्रा (d) भूमि स्पर्श मुद्रा

18. प्रयाग-प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अभिलेख में अशोक की नेपाल यात्रा का उल्लेख किया गया है।
2. इसमें अशोक की पत्नी कारूवाकी के राजकीय धर्मार्थ कार्यों का वर्णन करने वाला रानी का अभिलेख है।
3. इसमें फारसी में जहाँगीर का अभिलेख है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नही

19. मंदिर निर्माण कला के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए-
1. विमान और मंडप को ज्यादा महत्व
2. खुले प्रदक्षिणा पथ
3. खंभो, दरवाजों और छत को बारीक नक्काशी से सजाया जाता था।
उपर्युक्त विशेषता मंदिर निर्माण की कौन सी शैली से संबंधित है?
(a) नागर शैली (b) द्रविड शैली
(c) वेसर शैली (d) विजय नगर शैली

20. निम्नलिखित मंदिरों पर विचार कीजिए-
1. विट्ठलस्वामी मंदिर 2. विरूपाक्ष मंदिर
3. होयसालेश्वर मंदिर 4. वृहदेश्वर मंदिर
उपर्युक्त में से कौन-से मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4

21. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) गुजरात का पालिताना मंदिर जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतिनिधित्व करता है।
(b) झारखण्ड का शिखर जी मंदिर जैनों के 20 तीर्थंकरों का मोक्ष प्राप्ति स्थल है।
(c) अरूणाचल में स्थित त्वांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है।
(d) राजस्थान के पाली जिले में स्थित रनकपुर मंदिर पर नागर शैली का सर्वाधिक प्रभाव है।

22. अवध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अवध वास्तुकला की संरचनाओं में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है।
2. इसमें धार्मिक और धर्म निरपेक्ष संरचनाओं का निर्माण किया गया है।
3. बड़ा इमामबाड़ा एवं रूमी दरवाजा अवध वास्तुकला में निर्मित प्रमुख संरचनाएं हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

23. कला की अपभ्रंश शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह शैली मूल रूप से गुजरात और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्रों में पाई जाती है।
2. यह चित्रकला बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है।
3. इनमें सामान्यतः लाल, पीले और गेरूआ रंगों का उपयोग किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

24. हिंदुस्तानी संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हिंदुस्तानी संगीत मूलतः स्वदेशी है।
2. इसकी अनेक उपशैलियां हैं, जिनसे 'घरानो' का उद्भव हुआ है।
3. इस शैली में मुख्य रूप से रागों पर बल दिया जाता है।
4. इसमें प्रयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र तबला, सारंगी और सितार हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4

25. बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वज्रयान संप्रदाय हिंदू धर्म से प्रभावित है।
2. वज्रयान बौद्ध दर्शन के हीनयान शाखा पर आधारित है।
3. वज्रयान में अंतिम लक्ष्य क्लेशों की समाप्ति और निर्वाण की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करना है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

26. सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. पंद्रहवी शताब्दी में गुरू नानक के द्वारा सिख धर्म की शुरूआत की गई।
2. सिखों को लडाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरू गोविंद सिंह ने आरम्भ किया।
3. गुरू गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

27. पानीपत का तृतीय युद्ध के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. मराठों की हार से अंग्रेजो को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया।
2. अफगानों को अपनी जीत से बहुत लाभ हुआ एवं पंजाब लम्बे समय तक उनके अधिकार क्षेत्र में चला गया।
3. इस युद्ध के परिणामों ने यह निश्चित कर दिया की भारत पर अब अंग्रेजों का शासन होगा।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

28. कथनों पर विचार कीजिए-
1. अठारहवीं सदी में दहेज की कुप्रथा मुख्यतः महाराष्ट्र और पश्चिमोत्तर भारत में व्यापक रूप से फैली हुई थी।
2. अठारहवीं सदी के दौरान सती प्रथा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

29. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?
(a) महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक शाही चार्टर (आदेश-पत्र) जारी करके कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किए गए।
(b) जहाँगीर कंपनी को फरमान प्रदान करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था।
(c) कंपनी ने भारतीय उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं के लिए नये बाजार खोले।
(d) कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी।

30. रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) यह प्रारम्भ में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी भारत में लागू किया गया था।
(b) इस व्यवस्था के अंतर्गत बंदोबस्त को समय-समय पर संशोधित किया जाता था।
(c) कृषकों द्वारा राज्य को भू-राजस्व का भुगतान मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता था।
(d) यह बंदोबस्त 1820 में सर थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था।

31. नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. नागरिक सेवा के जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली थे।
2. ईस्ट इंडिया कम्पनी की नागरिक सेवा, दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा थी।
3. कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना नागरिक सेवा में आने वाले लोगों के प्रशिक्षण के लिए किया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी।
2. भारत में 'विधि का शासन' की आधुनिक अवधारणा अंग्रेजो द्वारा लागू की गई।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

33. भारतीय समाज की निम्नलिखित में से किन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कानूनी प्रयास किया गया?
1. सती प्रथा 2. विधवा पुनर्विवाह
3. नरबलि 4. शिशु हत्या
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

34. ब्रह्मसमाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था।
2. इसने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया।
3. इसने बहुविवाह तथा विधवाओं की अवनत स्थिति की निंदा की।
4. ब्रम्ह समाज वेदों एवं उपनिषदों का घोर विरोधी था।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

35. निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए-
1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
2. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना
3 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना
4. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी की स्थापना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) 1-3-2-4 (b) 1-2-3-4
(c) 3-4-2-1 (d) 4-2-3-1

36. ब्रिटिश काल में हुए निम्नलिखित आंदोलनो पर विचार कीजिए-
1. ताना भगत आंदोलन 2. रम्पा विद्रोह
3. मोपला विद्रोह 4. चुआर विद्रोह
5. कूका विद्रोह
उपर्युक्त में से कौन-से जनजातीय आन्दोलन थे?
(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 3 और 5
(c) केवल 1, 2, 4 और 5 (d) केवल 2, 3 और 4

37. थियोसोफिकल सोसायटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना श्रीमती ऐनी बेसेंट ने की।
2. इसने मुख्यतया हिंदू, पारसी और जैन धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

38. स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण थे-
1. प्रभावी संगठन का अभाव एवं अनुशासनात्मक दिशा हीनता
2. सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ़्तारी से आंदोलन का नेतृत्वविहीन होना
3. संकुचित समाजिक जनाधार

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

39. मार्ले-मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. मार्ले-मिंटो सुधार के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई।
2. इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई।
3. इसके अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था (केंद्रीय विधान सभा तथा राज्य परिषद) बना दिया गया।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

40. कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, 1916 के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
1. उग्रवादी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हुए।
2. कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की मांगे स्वीकार कर ली गयीं।
3. कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

41. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार
2. न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य
3. विधान परिषदों का बहिष्कार

उपर्युक्त कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन के तहत सुनिश्चित किए गए?
(a) दिल्ली अधिवेशन 1918 (b) कलकत्ता अधिवेशन 1920
(c) नागपुर अधिवेशन 1920 (d) कानपुर अधिवेशन 1925

42. कांग्रेस - खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी स्थापना चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की।
2. स्वराजियों का तर्क था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरूद्ध होगी।
3. स्वराजवादियों ने विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यो के माध्यम से जनता को दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रेरित किया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

43. निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए-
1. चटगांव शस्त्रागार में लूट
2. साण्डर्स हत्याकांड
3. केंद्रीय विधान सभा में बम विस्फोट
4. पुलिस मुठभेड में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) 1-2-3-4 (b) 3-4-2-1
(c) 2-4-3-1 (d) 2-3-1-4

44. साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में "प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्वरूप" में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया।
2. लिबरल फेडरेशन और मुस्लिम लीग ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया।
3. कमीशन में भारतीयों को शामिल न किए जाने के पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि भारतीय सुशासन के योग्य नही हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

45. सूची-I (नमक सत्याग्रह) को सूची-II (नेतृत्वकर्ता) के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (नमक सत्याग्रह)	सूची-II (नेतृत्वकर्ता)
A. तमिलनाडु	1. गोपाल बंधु चौधरी
B. मालाबार	2. अम्बिका कांत सिंहा
C. उड़ीसा	3. के. केलप्पम
D. बिहार	4. सी. राजगोपालाचारी

कूटः

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	3	4	2	1
(c)	2	4	1	3
(d)	1	3	4	2

46. भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतो, सभी भारतीय प्रांतो तथा देशी रियासतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था।
2. इसके तहत प्रांतो को स्वायत्तता एवं पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार दिया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

47. सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. सविनय अवज्ञा आन्दोलन का लक्ष्य 'पूर्ण स्वतंत्रता' था जबकि असहयोग आन्दोलन का लक्ष्य 'स्वराज्य' था।
2. सविनय अवज्ञा आन्दोलन में मुसलमानों की सहभागिता असहयोग आंदोलन के समान नही थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

48. 1937 के चुनावों में कुछ प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। इनके द्वारा किये गए कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
1. कांग्रेसी मंत्रियों ने अपना वेतन बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया ताकि इसका उपयोग वे जनता की भलाई के लिए कर सकें।
2. नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया।
3. पुलिस के अधिकारों में कमी की गई।
4. राजनैतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया।

ऊपर्युक्त में से कौन-से कार्य कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा किये गए थे?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

49. हंटर शिक्षा आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. आयोग प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक एवं देशी भाषा में दिए जाने का पक्षधर था।

2. इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित करने की वकालत की गई।
3. आयोग ने धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का समर्थन किया।
4. इसमें बालिकाओं को शिक्षा दिए जाने का प्रावधान था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
1. बंटवारा परिषद् के अध्यक्ष लार्ड लूई माउन्टबेटन थे।
2. बंटवारे के समय यूरोपीय तथा भारतीय ICS अधिकारीयों के अधिकार समान थे।
3. रोकड़ बाकी (cash balance) के सन्दर्भ में महात्मा गाँधी ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

51. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सकल आय का योगदान जिस अनुपात से घटा है, आजीविका के लिए इस पर लोगों की निर्भरता उस अनुपात से नही घटी।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का आय में योगदान और उस पर निर्भर जनसंख्या में साम्यता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

52. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आकलन में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित होता है/है?
1. राष्ट्रीय निजी उपभोग 2. सकल निवेश
3. सरकारी एवं व्यापार शेष

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

53. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. किसी अर्थव्यवस्था का GNP उसके GDP में, होने वाली विदेशी आय को जोड़कर हासिल होता है, इस आय के अंतर्गत विदेशी ऋणों का ब्याज एवं विदेशी अनुदान भी सम्मिलित है।
2. भारत निजी प्रेषण (Private Remittances) के माध्यम से सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करने वाला देश है।
3. भारत का GNP हमेशा उसकी GDP से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

54. निम्नलिखित में से कौन से सरकार द्वारा समावेशी वृद्धि के लिए बनाई जाने वाली अल्पकालिक नीतियों के उदाहरण है?
1. खाद्य एवं पोषाहार संबंधी योजनाएँ
2 गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन को लक्षित सभी योजनाएँ
3. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाएँ
4. आवास, पेयजल एवं शिक्षा संबंधी योजनाएँ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

55. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. केंद्रीय योजनाएं पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएँ केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा सम्मिलित रूप से वित्त पोषित होती हैं।
2. केंद्रीय योजनाएं संघ सूची से संबंधित होती हैं जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएँ राज्य सूची से संबंधित होती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

56. गत्यावरोध/मार्गावरोध मुद्रास्फीति (Bottleneck Inflation) के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
(a) यह मुद्रास्फीति की गणना करते वक्त वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किए जाने या न किए जाने पर आधारित है।
(b) यह मुद्रास्फीति लम्बी अवधि के दौरान देखने को मिलती है और सामान्यतः एक अंकीय होती है।
(c) इस मुद्रास्फीति मे मांग में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जबकि आपूर्ति अपने स्तर पर स्थिर रहती है।
(d) इस मुद्रास्फीति में आपूर्ति में अचानक बहुत तेजी से गिरावट आ जाती है जबकि मांग अपने पुराने स्तर पर बरकरार रहती है।

57. मुद्रास्फीतिकारी अंतर (Inflationary Gap) के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
(a) राष्ट्रीय आय के ऊपर कुल सरकारी खर्च में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी अंतर आता है।
(b) राष्ट्रीय आय के ऊपर होने वाले सरकारी खर्च में बढ़ोत्तरी को मुद्रास्फीतिकारी अंतर कहा जाता है।
(c) अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमे मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होते है, मुद्रास्फीतिकारी अंतर कहलाता है।
(d) जब मुद्रास्फीति के लिए एक औपचारिक परास की घोषणा की जाती है, तब उसे मुद्रास्फीतिकारी अंतर कहते हैं।

58. सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक (GDP Deflator) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. यह पिछले साल कीमतों के स्तर में हुई बढ़ोत्तरी के चालू वर्ष में कीमतों के स्तर में समरूपी प्रभाव में वृद्धि को संदर्भित करता है।
2. यह चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद तथा स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है।
3. सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक के अंतर्गत देश में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाएं समाविष्ट रहती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 1 और 3

59. निम्नलिखित में से कौन-सा/से मंदी (Depression) के प्रमुख लक्षण है/हैं?
1. मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से काफी निम्न होती है।
2. रोजगार के निम्न अवसर परंतु बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि होती है।
3. अर्थव्यवस्था में कुल मांग निम्न स्तर पर पहुँच जाती है जिससे आर्थिक गतिविधियाँ लगभग स्थिर हो जाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

60. गैर-कृषिगत उत्पाद बाजार पहुंच (Non-Agricultural Product Market Access-NAMA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह विश्व व्यापार संगठन का प्रावधान है, जो गैर-कृषिगत उत्पादों को सदस्य देशों के बाजारों में पहुंच स्थापित करने से संबंधित है।

2. यह गैर-कृषिगत उत्पादों का विकसित और विकासशील देशों के लिए कटौती की विभिन्न दरों से संबंधित प्रावधान है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

61. निम्नलिखित में से कौन-से संगठित भारतीय मुद्रा बाजार का हिस्सा हैं?

1. ट्रेजरी बिल 2. कॉल मुद्रा बाजार
3. पार्टिसिपेटरी नोट 4. म्युचुअल फंड
5. वाणिज्यिक पत्र

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 और 5 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 2, 4 और 5

62. वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह एक असुरक्षित वचन पत्र है।
2. यह धन प्राप्त करने के लिए बड़े निगमों द्वारा जारी किया गया एक मुद्रा बाजार का साधन है।
3. छोटी परिपक्वता अवधि के कारण यह बांड की तुलना में उच्च ब्याज पुनर्भुगतान दर वहन करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

63. जमा प्रमाण पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. इसका उपयोग भारत के बैंकों द्वारा अपनी तत्कालिक धन की कमी की पूर्ति के लिए किया जाता है।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक इन्हे वित्तीय बाजार में जारी नही कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

64. सरकारी बॉण्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. बांड बाजार के विकास से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण दबाव कम होगा।
2. भारत में सरकारी बॉण्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा 20% है।
3. रेपो रेट में कमी से सरकारी बॉण्ड की माँग बढ़ेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

65. पूंजी बाजार (Capital Market) के संदर्भ में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह दीर्घकालिक वित्तीय बाजार है।
2. किसी अर्थव्यवस्था के विकास में एक उन्नतिशील और मजबूत पूंजी बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. पूंजी बाजार में ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और बैंकरों की स्वीकृतियां आदि खरीदे और बेचे जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

66. निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रमुख उद्देश्य था/थे?

1. निजी क्षेत्र के बैंकों के नुकसान की रोकथाम
2. वित्तीय समावेशन में वृद्धि
3. आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण
4. अर्थव्यवस्था में ऋण का स्थिरीकरण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3 और 4

67. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

1. भारत में 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के तहत कोई लक्ष्य नही है।
2. लघु वित्तीय संस्थानों (MFIs) को प्रदत्त बैंक साख को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के रूप में जाना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

68. अगर किसी संस्था या व्यक्ति का नाम बिल्कुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंध लागू हो जाते हैं?

1. पूंजी बाजार में हिस्सा लेने से रोक दिया जाता है।
2. बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
3. कर्ज देने वाली संस्थाएँ बकाया वसूली के लिए कार्यवाही कर सकती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

69. निम्नलिखित में से किसे आरबीआई के नियंत्रण से छूट है?

1. निधि कंपनी
2. चिट फंड कंपनी
3. वेंचर कैपिटल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म
4. हाउंसिंग फिनांस कंपनी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

70. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अनुसूचित बैंक, आरबीआई एक्ट 1934 की प्रथम अनुसूची में शामिल होते हैं।
2. बैंक की प्रदत्त पूंजी एवं कोष 5 लाख रूपए से कम न हों।
3. बैंक का कार्य, जमाकर्ताओं के हितों के विरूद्ध न हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

71. पेमेंट्स बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

1. पेमेंट्स बैंक की स्थापना उर्जित पटेल समिति के आधार पर की गई थी
2. ये किसी भी रूप में लोन नहीं दे सकते
3. ये क्रेडिट कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड प्रदान नहीं कर सकते

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

72. विश्व बैंक समूह के आर्थिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

1. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का मूल उद्देश्य अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का मूल उद्देश्य सदस्य देशों में आधारभूत संरचना/आर्थिक सेवाओं का विकास है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, सदस्य देशों के निजी क्षेत्रीय संगठनों/कंपनियों को वाणिज्यिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

73. हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। एयरटेल पेमेंटस बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो गया है।
2. एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का, पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद दूसरा भुगतान बैंक था।
3. एयरटेल, भारती एयरटेल की अनुषंगी कंपनी है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

74. बंगाल विभाजन के बाद तेज हुई गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में एक ऐतिहासिक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में 'स्वदेशी आंदोलन' की घोषणा तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ।
2. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने विभाजन पर कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है।
3. सैय्यद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास प्रेसीडेंसी में बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

75. विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा 2000 में की गई थी।
2. इसका मुख्य उद्देश्य देश में विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः 'निर्यात के केन्द्र' का विकास करना है।
3. विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना केन्द्र, राज्य एवं निजी क्षेत्रों द्वारा जाती है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

76. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. प्रबंधित विनिमय दर वास्तव में नियत एवं उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्थाओं का एक मिश्रित स्वरूप है जिसमें सरकारों द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री द्वारा प्रत्यक्षतः या मौद्रिक नीति में परिवर्तन द्वारा परोक्षतः हस्तक्षेप किया जाता है।
2. किसी देश के एक साल में दूसरे देशों को कुल लेन देन का परिणाम अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन कहा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

77. राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाता है?
1. सरकार द्वारा उठाया गया रक्षा खर्च
2. विधि व्यवस्था पर किया जाने वाला व्यय
3. सरकार द्वारा भारतीय राज्यों तथा अन्य देशों को दिया जाने वाला अनुदान
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

78. एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसका उद्देश्य एशिया और सुदूर पूर्व के क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है और विकासशील सदस्य देशों के आर्थिक विकास में सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से योगदान करना है।
2. एशियाई विकास बैंक का कार्य, विशेष तौर पर कम विकसित सदस्य देशों में सार्वजनिक एवं निजी दोनों की क्षेत्रों में निवेश एवं सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

79. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. ओईईसी का मूल कार्य अमेरिकी वित्त पोषित मार्शल प्लान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में विध्वंसित यूरोप का पुनर्निर्माण करना था।
2. ओईईसी के बाद इसका स्वरूप बदलकर ओईसीडी हो गया जिसकी औपचारिक स्थापना 1961 में हुई।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

80. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. जब कंपनी अपने खुद के लोगों पर ध्यान देते हुए अपना ही ख्याल रखती है क्रोनी पूंजीवाद कहलाता है।
2. क्रांस सब्सिडी प्रक्रिया में किसी एक उपक्षेत्र को रियायत अथवा छूट दूसरे उपक्षेत्र से हुए लाभ की मदद लेकर की जाती है।
3. क्राउड फंडिग, वित्तपोषण का वह तरीका है जिसमें किसी कार्य में निवेश किए जाने वाले कोष की व्यवस्था सामूहिक प्रयास के माध्यम से की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

81. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. वह पूंजी, जिसका वास्तविक रूप में भुगतान शेयर धारकों द्वारा किया जाता है, अभिदत्त पूंजी कहलाता है।
2. किसी कंपनी द्वारा शेयरों के जारी करने से पूंजी प्राप्ति की अनुमानित मात्रा को प्रचलित पूंजी कहते हैं।
3. चरणबद्ध भुगतान नियमों के अन्तर्गत शेयर पूँजी की वह मात्रा, जिसका शेयरधारकों को भुगतान करना पड़ता है, प्रतिदेय पूंजी कहलाता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

82. बैंकों की पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. टियर I पूंजी, बिना कारोबार बंद किये नुकसान को अवशोषित करती है।
2. टियर II पूंजी मंदी के समय नुकसान को अवशोषित करती है इसलिए जमाकर्ताओं को अपेक्षाकृत कम सुरक्षा प्रदान होती है।
3. टियर III पूंजी में बाजार जोखिम, सामग्री जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम की स्थिति में सहायता की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

83. शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ऋण संस्थाएं कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करती हैं, वह शहरी सहकारी बैंक के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं।
2. शहरी सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र महानगरों, शहरी या अर्द्ध शहरी केन्द्रों तक सीमित रहता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

84. बीमा सुधार में आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिशों में क्या शामिल है/हैं?
1. बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए इरडा की स्थापना
2. बीमा नियंत्रक सर्वेक्षकों को लाइसेंस देने के अधिकार का समापन
3. भारतीय एवं विदेशी निजी क्षेत्र की कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश दिलाना

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

85. स्टार्ट अप इंडिया नवाचार सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
2. वर्चुअल तरीके से 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
3. इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख स्टार्टअप्स उद्यामियों, निवेशकों, इन्म्यूबेटरों, वित्तपोषण करने वाले निकायों, बैंकों और नीति निर्माताओं आदि को एक मंच पर लाना है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

86. ब्रिक्स बैंक की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. ब्रिक्स बैंक के पूंजीगत आधार का इस्तेमाल शुरूआत में ब्रिक्स देशों में आधारभूत ढाँचे और 'दीर्घकालिक विकास' परियोजनाओं को पैसा देने के लिए किया गया।
2. भुगतान समस्याओं के समय संतुलन बनाए रखने के लिए सदस्य देशों की तरलता की रक्षा के लिए 100 अरब डॉलर का एक आकास्मिक संचित प्रावधान भी तैयार किया जायेगा।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

87. सीएआर बनाए रखना जरूरी है क्योंकि-
1. बैंकों के नाकाम होने से रोकने में मदद करती है।
2. पूंजी का यह हिस्सा बैंकों के मालिकों के मुनाफे पर असर डालता है।
3. व्यवसाय में नुकसान होने पर कम पूंजी वाले बैंकों की शुद्ध संपत्ति नकारात्मक हो जाती है, ऐसे में यह कानून बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में कुशन का काम करती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) उपर्युक्त सभी

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए बार-बार की जाती है तो इसे प्रारंभिक आम निर्गम कहते हैं।
2. उस शेयर की बिक्री करना जिसकी विक्रेता के पास उपस्थिति या स्वामित्व नही हो शॉर्ट सेलिंग कहलाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

89. गैर कर राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. वित्तीय सेवाओं, मुद्रा छापना, डाक टिकट छापना आदि से गैर कर राजस्व की प्राप्ति होती है।
2. सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान केन्द्र सरकार के संदर्भ में यह हमेशा बाह्य होता है तथा राज्य सरकार के संदर्भ में यह आंतरिक होता है।
3. सरकार द्वारा आगे दिए गए सभी ऋणों, चाहे ये देश के अंदर दिये गए हो या देश के बाहर पर मिलने वाला ब्याज।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

90. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।
2. अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केन्द्र, एक निवेश विवाद निपटान केन्द्र है जिसके निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

91. बेसल समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. बेसल समझौते संधियों का एक समुच्चय है जो बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा तैयार किया गया।
2. विश्व में देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा विषमता को हटाना इसका उद्देश्य है।
3. ये पूंजी जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के मामले में बैंकिंग विनियम पर सिफारिशें उपलब्ध कराता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

92. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. एक जिले में एक से अधिक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक होते हैं जो राज्य सहकारी बैंक को रिपोर्ट करते हैं
2. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक नाबार्ड, आरडीबीआई और सहकारी संस्थाओं के पंजीयक के तहत कार्य करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

93. परिसम्पत्ति (एसेट) से तात्पर्य है-
1. ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनका भौतिक रूप होता है मूर्त परिसंपत्ति कहलाती हैं।
2. ऐसी परिसंपत्ति जिनका आन्तरिक मूल्य कुछ नहीं होता किंतु इनका मूल्य स्वामित्व एवं कब्जे के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त किया जाता है, अमूर्त परिसंपत्ति कहलाती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

94. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन देना
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास एवं विनिमय दरों का स्थरीकरण करना
3. विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था करना

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

95. कर तथा अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. कर का लोगों की आय, उनकी क्रय शक्ति, उपभोग तथा परिणामस्वरूप उनके जीवन स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
    2. कर का वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका उत्पादन मूल्य प्रभावित होता है।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
96. भारत में जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
    1. आठवीं अनुसूची में उल्लिखित जनगणना राज्य सूची का विषय है।
    2. जनगणना करने, आकड़े एकत्रित करने तथा प्रकाशित करने की जिम्मेदारी ऑफिस ऑफ़ द रजिस्टार जनरल की है जो कार्मिक, लोक शिकायतें और प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
97. हाल के दिनों में भारतीय बाज़ारों में ईंधन के कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक हैं –
    1. आयात शुल्क 2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
    3. विपणन कंपनियों का लाभांश 4. शोधन लागत
    5. माल ढुलाई लागत

    नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए –
    (a) केवल 1, 2, 3 और 5 (b) केवल 3 और 4
    (c) केवल 1, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी
98. हाल ही में भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) में ट्रिप्स प्रस्ताव पर छूट की माँग की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
    1. ट्रिप्स समझौता औद्योगिक डिज़ाइन, कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गोपनीयता जैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर एक बहुपक्षीय समझौता है।
    2. ट्रिप्स समझौता 1990 में लागू किया गया था।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
99. सीमांत प्रतिस्थापन दर के संबंध में क्या सही है :
    (a) यह बजट रेखा के ढलान को दर्शाता है।
    (b) यह आय रेखा के ढलान को दर्शाता है।
    (c) यह उत्पादन संभावना की ढलान को दर्शाता है।
    (d) यह तटस्थता रेखा के ढलान को दर्शाता है।
100. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
    1. DFCCIL मालभाड़ा गलियारे के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाती है।
    2. वर्ष 2006 में इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।
    3. DFCCIL का उद्देश्य परिस्थितिकी संधारणीयता की दिशा में की जाने वाली सरकार की पहल का समर्थन करना है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(b)	3.	(a)	4.	(a)	5.	(d)	6.	(d)	7.	(d)	8.	(c)	9.	(d)	10.	(a)
11.	(c)	12.	(c)	13.	(a)	14.	(c)	15.	(a)	16.	(a)	17.	(d)	18.	(b)	19.	(c)	20.	(d)
21.	(d)	22.	(c)	23.	(c)	24.	(d)	25.	(a)	26.	(c)	27.	(c)	28.	(d)	29.	(d)	30.	(c)
31.	(b)	32.	(c)	33.	(d)	34.	(a)	35.	(d)	36.	(a)	37.	(b)	38.	(d)	39.	(a)	40.	(d)
41.	(b)	42.	(a)	43.	(d)	44.	(a)	45.	(a)	46.	(b)	47.	(c)	48.	(b)	49.	(b)	50.	(b)
51.	(a)	52.	(d)	53.	(c)	54.	(d)	55.	(c)	56.	(d)	57.	(b)	58.	(b)	59.	(d)	60.	(a)
61.	(d)	62.	(d)	63.	(c)	64.	(a)	65.	(a)	66.	(b)	67.	(b)	68.	(b)	69.	(d)	70.	(a)
71.	(c)	72.	(d)	73.	(b)	74.	(d)	75.	(d)	76.	(c)	77.	(d)	78.	(c)	79.	(c)	80.	(d)
81.	(d)	82.	(d)	83.	(c)	84.	(d)	85.	(d)	86.	(c)	87.	(d)	88.	(b)	89.	(d)	90.	(c)
91.	(d)	92.	(b)	93.	(c)	94.	(d)	95.	(c)	96.	(d)	97.	(d)	98.	(a)	99.	(d)	100.	(d)

दीक्षांत
Education Centre

FREE COACHING & SCHOLARSHIP PROGRAMME

GENERAL STUDIES

FOUNDATION COURSE FOR IAS

ENGLISH MEDIUM

ONLINE/OFFLINE

NEW BATCH

STARTS FROM

13 SEPT., 5 PM

FEATURES

CLASSROOM PROGRAMME
24 Months/14 Months
1200-1500 Hrs. Classes
300 Hrs. NCERT Video
& 150 Hrs. PT Booster
Classes on App

STUDY MATERIALS
Latest, Updated &
Exam Oriented
Study Materials
10,000 Pages
(50 Booklets)

CURRENT AFFAIRS
200 Hrs.+ Classes on
Important Issues
for 2 Yrs.
& 3 Years Monthly
Magazine Subscription

WORKBOOK (MAINS)
16 workbooks provides
opportunity to review
and extend your
classroom learnings

UNIT TEST (PRE+MAINS)
32 unit test improves
knowledge, skills,
& aptitude for
prelims & mains exam

DAILY CLASS TEST
250 Prelims and 200 Mains
Test is used to check the
quality of knowledge gained
& started executing

CURRENT AFFAIRS PRE TEST
Through 100 tests you will get
right approach for
current affairs MCQs
and their relevance in
the UPSC exam

MENTORSHIP PROGRAMME
Individual doubt clearance
by faculties/experts to
increase confidence and
exposure on
different perspectives

COURSE VALIDITY
4 Years/3 Times Course
Validity will help to increase
your confidence and
preparation for your exam

दीक्षांत
Education Centre

UPSC CSE RESULT - 2021

CONGRATULATIONS

Our 200+ Successful Candidates of
UPSC Civil Service Examination - 2021-22

1 Rank — SHRUTI SHARMA — Roll No. - 0803237

3 Rank — GAMINI SINGLA — Roll No. - 3524519

4 Rank — AISHWARYA VERMA — Roll No. - 5401266

6 Rank — YAKSH CHAUDHARY — Roll No. - 0834409

9 Rank — PREETAM KUMAR — Roll No. - 1118762

24 Rank — SAHITYA PUSAPATI — Roll No. - 5110593

31 Rank — AVINASH — Roll No. - 0323860

33 Rank — JASPINDER SINGH — Roll No. - 3516855

35 Rank — KARTIKEYA JAISWAL — Roll No. - 0413129

43 Rank — SHUBHAM SHUKLA — Roll No. - 0623772

44 Rank — ANJALI SHROTRIYA — Roll No. - 7808206

50 Rank — ABHIJEET RAY — Roll No. - 8101939

53 Rank — ARPIT SANGAL — Roll No. - 0835485

54 Rank — ARPIT GUPTA — Roll No. - 6000943

57 Rank — ALFRED OV — Roll No. - 1903199

60 Rank — SHRADDHA GOME — Roll No. - 7806666

62 Rank — TIRUMANI S POOJA — Roll No. - 6206389

71 Rank — SHREYA SHREE — Roll No. - 6808285

73 Rank — NAMRATA CHOUBEY — Roll No. - 4103715

93 Rank — DEEPESH KUMARI — Roll No. - 0879483

96 Rank — MINI SHUKLA — Roll No. - 6903989

200 + Results

289, DHAKA JOHAR, NEAR DUSSEHRA GROUND, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09 ✆ 7428092240